सूर्योदय 6:35 सूर्यास्त 5:34

आज का तापमान

शिमला	10.0 न्यू	20.5 अधि
धर्मशाला	12.0 न्यू	22.5 अधि

बाजार

सेंसेक्स	74,459.53
निफ्टी	23,053.10

सोना 1,41, 000 चांदी 1,84, 000

भारतेन्दु शिखर

हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू व उत्तराखंड में प्रसारित

आरएनआई नं. HPHIN/2000/02437 | शिमला | शनिवार, 31 अक्तूबर 2026 | 15 कार्तिक, विक्रमी संवत 2083 | वर्ष 28, अंक 185, कुल पृष्ठ 12 | मूल्य : 5 रुपए | info@bhartendushikhar.com | 8894677702

न्यूज शॉर्ट्स

दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज बाइनेंस से 60,000 करोड़ चोरी

एजेंसी, नई दिल्ली। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बाइनेंस हैक हो गया है। इसे इतिहास की सबसे बड़ी क्रिप्टो हैकिंग माना जा रहा है। कंपनी ने जमा और निकासी पर रोक लगा दी है यानी, सुरक्षा जांच पूरी होने तक बाइनेंस अकाउंट में न तो नया पैसा जमा किया जा सकता है और न ही अंदर मौजूद पैसा या क्रिप्टो बाहर निकाला जा सकता है। इस हैकिंग में 6.3 बिलियन डॉलर यानी करीब 60 हजार करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी चोरी हुई है। घटना के बाद बिटकॉइन समेत अन्य क्रिप्टो करेंसीज में 5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। ब्लॉकचेन रिसर्च फर्म रूलैब्स के मुताबिक इस हैकिंग के पीछे नॉर्थ कोरिया का हाथ है। क्रिप्टोकरेंसी एक तरह का डिजिटल पैसा है, जिसे ऑनलाइन खरीदा-बेचा जा सकता है। इसे कोई सरकार या बैंक जारी नहीं करता, बल्कि यह ब्लॉकचेन तकनीक से चलता है।

सोमनाथ मंदिर के पास नॉनवेज बेचने पर रोक रद्द

एजेंसी, अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने सोमनाथ मंदिर के आसपास बिकने वाले नॉन-वेज खाने पर सरकार की लगाई रोक रद्द कर दी है। कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगाने की राज्य सरकार की मांग भी ठुकरा दी। जस्टिस निशा एम ठाकोर की बेंच ने सरकार की दलील खारिज कर दी और प्रतिबंध को रद्द कर दिया। राज्य सरकार ने सोमनाथ मंदिर के आसपास नॉन-वेज खाना बेचने पर रोक लगाई थी। कोर्ट ने माना कि कलेक्टर ने गुजरात पुलिस एक्ट की धारा 33(1)(2) के तहत अपनी शक्तियों से बाहर जाकर एक वैध व्यापार पर स्थायी रोक लगा दी, जो असंवैधानिक है। सरकार अब इस फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच या सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए बैन खत्म है।

6 राज्यों में एसआईआर की समयसीमा बढ़ी

एजेंसी, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और नगालैंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम की समयसीमा बढ़ा दी है। आयोग ने इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश में दावे-आपत्तियां दाखिल करने, उनके निस्तारण और अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीखों में संशोधन किया है। संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारियों से मिले अनुरोधों और परिस्थितियों की समीक्षा के बाद संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। चुनाव आयोग के अवर सचिव संदीप कुमार और सचिव पवन दीवान की ओर से जारी निर्देशों में संबंधित राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम का विभिन्न प्रचार माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार कराने को कहा गया है। साथ ही सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी संशोधित समय-सारिणी की लिखित जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पात्र मतदाता निर्धारित समयसीमा में अपना पंजीकरण करा सकें।

बनासकांठा में कोई आलू से सोना बनाने की नहीं करता बात : मोदी

किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी, 9.34 करोड़ किसानों को मिले 19 हजार करोड़

एजेंसी, बनासकांठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के बनासकांठा में कहा कि यहां का आलू दुनियाभर में मशहूर है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, बनासकांठा में आकर कोई नहीं कहता कि आलू से सोना बनाएंगे, क्योंकि यहां के लोग पहले ही आलू से सोना बना रहे हैं।

मोदी की सभा में किसानों के बैठने के लिए कुर्सियों की जगह चारपाइयां बिछाई गई थीं। इस पर उन्होंने कहा कि देश के लोगों के लिए यह अजूबा होगा कि एक सभा में सभी लोग चारपाई पर बैठे हैं। बनासकांठा के लोगों ने गांवों की इस पुरानी परंपरा को जिंदा रखा है। अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को बुलाया होता तो यह रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता। इस दौरान पीएम ने किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी की। इसके तहत 9.34 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को 18,690 करोड़ से अधिक की रकम मिलेगी। उन्होंने 14 हजार करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही दो नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाई।



पीएम ने 'भारत पर्व' का किया उद्घाटन

पीएम मोदी ने गुजरात के एकता नगर में 'भारत पर्व' का उद्घाटन किया। उन्होंने वहां लगी प्रदर्शनी भी देखी। उन्होंने बनासकांठा जिले में 'भारत बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर' के पशु फार्म और 'एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी-इन विट्रो फर्टिलाइजेशन' प्रयोगशाला का भी दौरा किया। ये केंद्र पशु प्रजनन, आनुवंशिक सुधार (जेनेटिक अपग्रेडेशन) और उन्नत प्रजनन तकनीकों पर रिसर्च करेंगे।

किसानों को बीजों की 3 हजार नई किस्में दी गईं

पीएम मोदी ने कहा किसानों के लिए मौसम में हो रहा बदलाव बहुत बड़ी चुनौती है। बीते सालों में बीजों की करीब 3 हजार नई किस्में किसानों को दी गईं। बीते दशक में भी पशुपालन और डेयरी सेक्टर में भी विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर जोर दिया है। पशुओं की नस्ल बेहतर होगी तो दूध उत्पादन बढ़ेगा। 4 गाय से मिलने वाला दूध एक ही गाय से मिले। समय पर टीकाकरण इलाज समय पर मिलेगा तो बीमारी से होने वाला नुकसान कम होगा। यानी पशु स्वस्थ होगा तो मेरे पशुपालक भाई बहनों की कमाई भी बढ़ेगी।

बद्रीनाथ से देहरादून आ रहा हेलिकॉप्टर क्रैश, पायलट समेत 6 यात्रियों की मौत

एजेंसी, देहरादून। उत्तराखंड में शुक्रवार को बद्रीनाथ से देहरादून आ रहा एक प्राइवेट कंपनी का हेलिकॉप्टर जोशीमठ के पास क्रैश हो गया। हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की मौत हो गई। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं।

हेलिकॉप्टर ने दोपहर करीब 1:14 बजे बद्रीनाथ से देहरादून के सहस्त्रधारा के लिए उड़ान भरी थी। जोशीमठ घाटी के ऊपर उड़ान के दौरान उसका संपर्क टूट गया। इसके बाद ट्रैकिंग सिस्टम पर भी उसकी लोकेशन मिलनी बंद हो गई। यह घटना ऐसे समय हुई है, जब उत्तराखंड के कई इलाकों में खराब मौसम बना हुआ है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो रही है। केंद्र सरकार के मुताबिक, 2016 और 2026 के बीच उत्तराखंड में 12 हेलीकॉप्टर हादसे हुए, जिनमें 27 मौतें लोगों की मौत हुई। आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदकिशोर जोशी के मुताबिक, जेपी डैम के ऊपर जंगल में सफेद रंग की किसी चीज में आग लगने की सूचना मिली थी। इसकी जांच के लिए दो हेलिकॉप्टर भेजे गए थे।



◆ हेलिकॉप्टर हादसे के बाद ट्रांस भारत एविएशन की सभी उड़ानें रोकी गईं

लापता हेलिकॉप्टर ट्रांस भारत एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का था। इसमें पायलट कैप्टन हिमांशु के अलावा 5 यात्री सवार थे। इनमें प्रतापा, अरुण, शंकर गौड़ा, सुधीर के और एचएस नटराज शामिल हैं। यात्री बेंगलुरु के बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद एहतियात के तौर पर ट्रांस भारत एविएशन के सभी हेलिकॉप्टरों की उड़ानें रोक दी गई हैं।

नौसेना को मिलेंगे अगली पीढ़ी के आठ नए युद्धपोत

एजेंसी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने भारतीय नौसेना के लिए आठ 'नेक्स्ट-जनरेशन कॉर्वेट्स' (युद्धपोत) बनाने के 40,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इन युद्धपोतों का निर्माण दो सरकारी शिपयार्ड कोलकाता स्थित 'गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स' और 'गोवा शिपयार्ड लिमिटेड' द्वारा किया जाएगा। इन आठ युद्धपोतों के लिए दोनों शिपयार्ड के साथ अगले कुछ दिनों में अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट से नौसेना के सरफेस फ्लीट (सतही बेड़े) को मजबूती मिलेगी और देश में ही युद्धपोत बनाने की प्रक्रिया को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

◆ कैबिनेट ने 40 हजार करोड़ की परियोजना को दी मंजूरी

'सहमति से बने संबंध ब्रेकअप के बाद दुष्कर्म नहीं' : सुप्रीम कोर्ट

एजेंसी, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि व्यस्क युवक-युवती के बीच आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंधों को ब्रेकअप के बाद दुष्कर्म नहीं माना जा सकता।

कोर्ट ने शादी का वादा करके रिलेशन बनाने के आरोप वाले मामले में एक व्यक्ति को आरोपों से मुक्त कर दिया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि प्रेम और आपसी सहमति वाले रिश्ते में बने संबंधों को ब्रेकअप के बाद अपराध नहीं बनाया जा सकता। हर टूटे रिश्ते को दुष्कर्म का मामला बनाना गलत है। हालांकि, अगर शुरुआत से ही शादी का झूठा वादा करके या धोखे से सहमति हासिल की गई थी, तो मामला अलग होगा। ऐसे मामलों में यह देखना जरूरी है कि क्या सहमति वास्तव में धोखे पर आधारित थी।



◆ हर टूटे रिश्ते को दुष्कर्म केस में बदलना गलत

दुष्कर्म का आरोप का डर दिखाना गलत

किसी पुरुष पर सिर्फ इसलिए आपराधिक मामला दर्ज करना उचित नहीं है, क्योंकि उसने रिश्ता खत्म करने का फैसला किया है। दुष्कर्म के आरोप का डर दिखाकर किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती रिश्ते में बने रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

भूटान में ग्लेशियर झील फटी, सड़कें उखड़ीं

पानी भारत पहुंचने का खतरा, बंगाल-असम में बाढ़ का अलर्ट

एजेंसी, थिम्पू/कोलकाता। भूटान में वीरवार देर रात शिंताफू ग्लेशियर झील फटने से भारी तबाही हुई। पानी के तेज बहाव में यहां का मशहूर गर्म पानी का कुंड 'गासा त्साचु' पूरी तरह बह गया। पुनाखा-गासा हाईवे का एक हिस्सा भी टूट गया, जिससे वहां ट्रैफिक बंद करना पड़ा। हालांकि, अब तक किसी की मौत की खबर नहीं है। झील से निकले पानी के कारण संकोश नदी का जलस्तर बढ़ गया है।

यह नदी भूटान से निकलकर असम और पश्चिम बंगाल की सीमा वाले इलाकों से गुजरती है और आगे ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसे देखते हुए दोनों राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में प्रशासन ने 10 हजार से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचाया है। रातभर सायरन बजाकर लोगों को सतर्क किया गया और जल्द से जल्द घर छोड़ने को कहा गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीमें भी तैनात की गई हैं।



◆ 10 हजार से अधिक लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए

भूटान की शिंताफू ग्लेशियर झील फटने पर उसमें जमा पानी नदियों के रास्ते भारत पहुंच सकता है। सबसे पहले यह पानी भूटान की मो छू नदी में आएगा। आगे मो छू और फो छू नदियां मिलकर पुनात्सांगछू नदी बनाती हैं। यह नदी दक्षिण की ओर बहते हुए भारत में प्रवेश करती है। भारत में इसे संकोश नदी कहा जाता है। इसके पानी से पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी के साथ असम के कोकराझार और धुबरी जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा हो सकता है।

आगे चलकर संकोश नदी असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इस तरह भूटान की झील का पानी नदियों के रास्ते भारत के मैदानी इलाकों तक पहुंच सकता है।

राफेल मरीन लड़ाकू विमान ने आईएनएस विक्रांत पर पहली कोशिश में की सफल लैंडिंग



एजेंसी, पणजी। भारतीय नौसेना के लिए समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षमताओं के लिहाज से एक अहम उपलब्धि सामने आई है। नौसेना के स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर राफेल मरीन लड़ाकू विमान ने पहली ही कोशिश में सफल लैंडिंग की। यह परीक्षण 29 अक्तूबर 2026 को किया गया।

यह राफेल मरीन फ्रेंच नेवी का लड़ाकू विमान है। इसे फ्रेंच पायलट उड़ा रहे थे। इन ट्रायल्स से भारतीय नौसेना में राफेल मरीन विमान को ऑपरेशनल बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। भारत को अभी तक राफेल मरीन मिला नहीं है। इस सफल परीक्षण के साथ ही राफेल मरीन विमान को भारतीय नौसेना में ऑपरेशनल यानी परिचालन रूप से शामिल करने की दिशा में शुरुआती कदम बढ़ा दिया गया है। इस परीक्षण को विमानवाहक पोत पर इसकी क्षमता परखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है।

◆ नौसेना में शामिल करने के लिए ट्रायल सक्सेसफुल

उत्तराखंड में 8.08 लाख किसान खातों में पहुंचे 161.96 करोड़

किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाना सरकार की प्राथमिकता : मुख्यमंत्री धामी

एजेंसी, देहरादून। उत्तराखंड में किसानों को आर्थिक मदद देने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का दायरा पिछले 7 साल में दोगुना हो गया है।

वर्ष 2019 में जब योजना की पहली किस्त जारी हुई थी, तब प्रदेश के करीब 4 लाख किसान इसके लाभार्थी थे। अब यह संख्या बढ़कर 8 लाख 8 हजार से अधिक हो गई है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना की 24वीं किस्त जारी की। इसके तहत उत्तराखंड के किसानों के खातों में 161.96 करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किए गए। देशभर में 9.34 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,690 करोड़ रुपए भेजे गए। देहरादून के सर्वे ऑडिटोरियम, हाथीबड़कला में आयोजित पीएम किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार का फोकस अब केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक तकनीक, बागवानी, प्राकृतिक खेती और खाद्य प्रसंस्करण के जरिए कृषि को मजबूत बनाने पर भी है।



◆ कहा- आधुनिक तकनीक और प्राकृतिक खेती से मजबूत होगी उत्तराखंड की कृषि अर्थव्यवस्था

पुतिन की यूरोप को चेतावनी- रूस से टकराव महंगा पड़ेगा

एजेंसी, मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपीय देशों को चेतावनी दी है कि रूस से टकराव बढ़ाना उनके लिए महंगा पड़ सकता है। मॉस्को में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पुतिन ने कहा, अगर बाल्टिक सागर में जहाजों की आवाजाही रोकने की कोशिश की गई, तो वहां भी होर्मुज जैसे हालात बन सकते हैं। पुतिन ने कहा कि रूस यूरोप के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई देश उससे टकराव करता है तो उसे इसके नतीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा तो किसी की जीत नहीं होगी।



दृष्टिबाधितों के हुनर से सजा दिवाली बाजार, सीएम रेखा ने किया उद्घाटन

एजेंसी, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन द्वारा आयोजित 'दीपावली बाजार 2026' का विधिवत उद्घाटन किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने न केवल बाजार में लगाए गए स्टॉल्स का जायजा लिया, बल्कि संस्था के दृष्टिबाधित सदस्यों के साथ भोजन कर उनसे आत्मीय संवाद भी किया। यह दीपावली बाजार दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए एक विशेष मंच है, जहां वे अपने हाथों से बनाए गए उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह बाजार समावेशिता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि इस बाजार से होने वाली आय का उपयोग संस्था द्वारा दृष्टिबाधित बच्चों और युवाओं की निशुल्क शिक्षा तथा उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा। यह एक नेक कार्य है, जो इन विशेष बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे 30 अक्तूबर से 5 नवंबर तक लगने वाले इस दीपावली बाजार में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचें और हस्तनिर्मित उत्पाद खरीदकर इस सराहनीय पहल का समर्थन करें।



◆ मुख्यमंत्री ने दृष्टिबाधितों के साथ बिताए आत्मीय पल

उनकी इस अपील का उद्देश्य समाज में इन विशेष प्रतिभाशाली व्यक्तियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

अब व्यापारी के विश्वास का प्रकाश है रात में जगमगाते बाजारों की रोशनी : सीएम योगी

एजेंसी, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 के पश्चात रात में जगमगाते बाजारों को व्यापारी के विश्वास का प्रकाश बताया है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर पोस्ट कर पूर्ववर्ती सरकार की कार्यपद्धति पर सवालिया निशान खड़ा किया।

उन्होंने कहा कि 2017 से पहले अपराध और असुरक्षा के कारण सूर्यास्त के साथ व्यापारिक गतिविधियां सीमित होने लगती थीं। मुख्यमंत्री ने लिखा कि आज नए उत्तर प्रदेश में रात्रि के समय जगमगाते बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की रोशनी केवल व्यापार की नहीं, बल्कि व्यापारी के विश्वास का प्रकाश भी है। नाइट शिफ्ट में अपने कार्यस्थल पर निर्भय होकर दायित्व निभाती हमारी मातृशक्ति का आत्मविश्वास केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे समाज की प्रगति का प्रतीक है।

डबल इंजन सरकार ने बदली परिस्थिति



मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने इस परिस्थिति को बदला। अपराध और अपराधियों के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति ने कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ किया एवं महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी। आज बाजार रात में भी खुले रहते हैं। व्यापारियों को व्यवसाय के विस्तार के नए अवसर मिल रहे हैं और हमारी बेटियां सुरक्षित वातावरण में अपनी प्रतिभा एवं परिश्रम से आगे बढ़ रही हैं।

◆ 'सुरक्षा से समृद्धि' की ओर अग्रसर 'नया उत्तर प्रदेश'

मुख्यमंत्री ने बताया कि सुरक्षा और विश्वास का यह वातावरण उत्तर प्रदेश में सदैव नहीं था। वर्ष 2017 से पहले अपराध और असुरक्षा के कारण सूर्यास्त के साथ व्यापारिक गतिविधियां सीमित होने लगती थीं। देर रात तक कार्य करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर परिवारों में चिंता बनी रहती थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 में प्रदेश की महिला श्रम बल भागीदारी लगभग 13 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 36 प्रतिशत हो चुकी है।

यह मातृशक्ति के बढ़ते आत्मविश्वास, आर्थिक सामर्थ्य और स्वावलंबन की सशक्त अभिव्यक्ति है। यह 'सुरक्षा से समृद्धि' की ओर अग्रसर 'नए उत्तर प्रदेश' की नई पहचान है।

सुविधा मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से नौहराधार में 6.92 करोड़ से बने सीएचसी भवन का किया लोकार्पण

दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकता : सुक्खू

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, नाहन। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला से वर्चुअल माध्यम द्वारा सिरमौर जिले के रेणुका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नौहराधार में नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भवन का लोकार्पण किया।

6.92 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित छह बिस्तरों की क्षमता का स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र में स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ करने और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्वास्थ्य केंद्र से आस-पास की 20 ग्राम पंचायतों और 47 गांवों के लगभग 50 हजार लोग लाभान्वित होंगे।



◆ नौहराधार सीएचसी से 20 पंचायतों के 50 हजार लोगों को मिलेगी स्वास्थ्य सुविधा

यहां मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे लोगों को अपने घर-द्वार के निकट ही समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

इस दिशा में विशेषकर ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना सरकार की प्राथमिकता है, ताकि लोगों को बेहतर उपचार के लिए प्रदेश से बाहर न जाना पड़े। इस स्वास्थ्य केंद्र के शुरू होने से स्थानीय लोगों को समयबद्ध और बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र में दो चिकित्सा अधिकारियों और एक स्टॉफ नर्स को नियुक्त किया गया है, ताकि मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से उपलब्ध करवाई जा सकें। उन्होंने कहा कि चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता से स्थानीय लोगों की स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

31 मार्च 2027 तक स्वास्थ्य संस्थानों में 70 प्रतिशत से अधिक होगा स्टाफ

सीएम ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य क्षेत्र की अनदेखी हुई और उस समय अस्पतालों में केवल 35 प्रतिशत स्टॉफ ही उपलब्ध था। जबकि वर्तमान प्रदेश सरकार 31 मार्च, 2027 तक स्वास्थ्य संस्थानों में स्टॉफ की संख्या 70 प्रतिशत से अधिक करने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दे रही है, ताकि गांवों में रहने वाले लोगों की आर्थिकी को सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों को घर के समीप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सीबीएसई स्कूल भी खोले जा रहे हैं। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला संगड़ह को सीबीएसई स्कूल बनाने की घोषणा भी की। उन्होंने क्षेत्र में प्रतिदिन 5,000 लीटर क्षमता का मिल्क चिलिंग प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन भी दिया।

सुप्रीम कोर्ट से सुक्खू सरकार को फिर झटका डेढ़ लाख कर्मचारियों के वित्तीय अधिकारों पर मुहर

अनुबंध सेवाकाल की वरिष्ठता और वित्तीय लाभ देने का रास्ता साफ, सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज



भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में अनुबंध कर्मचारियों की वरिष्ठता और वित्तीय लाभों से जुड़े मामले में प्रदेश सरकार को सर्वोच्च न्यायालय से भी राहत नहीं मिली है। हिमाचल प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एक्ट, 2024 को लेकर राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई है। इस फैसले से करीब डेढ़ लाख कर्मचारियों से जुड़े मामले में सरकार को एक और कानूनी झटका लगा है। इससे पहले उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भी सरकार को राहत नहीं मिली थी। भाजपा ने इस फैसले के बाद पात्र कर्मचारियों को उनके वित्तीय लाभ और वरिष्ठता का अधिकार शीघ्र देने की मांग की है।

भाजपा प्रदेश सचिव सुमीत शर्मा ने कहा कि सरकार को अब अदालतों के फैसलों का सम्मान करते हुए कर्मचारियों के हित में कदम उठाने चाहिए। वहीं, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पूर्व प्रांत महामंत्री डॉ. मामराज पुंडीर ने कर्मचारियों की कानूनी लड़ाई को सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचाने के लिए डॉ. देवेन्द्र एटलस को बधाई दी।

अनुबंध सेवा की अवधि और वरिष्ठता का विवाद : प्रदेश में वर्ष 2003 से विभिन्न विभागों में अनुबंध आधार पर नियुक्तियां होती रही हैं। शुरुआती दौर में कर्मचारियों को आठ वर्ष तक अनुबंध पर रखा जाता था। बाद में यह अवधि घटाकर सात, पांच, तीन और अंत में दो वर्ष कर दी गई। कर्मचारियों की मांग रही है कि नियमितीकरण से पहले अनुबंध पर दी गई सेवा को भी वरिष्ठता और वित्तीय लाभ निर्धारित करने में शामिल किया जाए।

इस मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 25 अप्रैल 2026 को संबंधित कानूनी प्रावधानों को असंवैधानिक करार देते हुए कर्मचारियों को वित्तीय लाभ और वरिष्ठता देने के निर्देश दिए थे। इसके बाद राज्य सरकार ने फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने 29 जुलाई 2026 को सरकार की याचिका खारिज कर दी थी और कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देने के लिए चार महीने का समय निर्धारित किया था।

पुनर्विचार याचिका भी नहीं आई काम : सरकार ने एसएलपी खारिज होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। डॉ. मामराज पुंडीर के अनुसार 27 अक्टूबर 2026 को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मामले पर सुनवाई की। अदालत ने विलंब को क्षमा करते हुए पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही सभी लंबित अंतरिम आवेदनों का भी निस्तारण कर दिया गया। मामले का अंतिम निस्तारण 29 अक्टूबर को दर्ज हुआ।

डॉ. पुंडीर ने हिमाचल प्रदेश महाविद्यालय शैक्षिक महासंघ के प्रांत अध्यक्ष डॉ. देवेन्द्र एटलस की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई को सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने इसे कर्मचारी हितों के लिए समर्पित प्रयास बताया।

भाजपा ने सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल : भाजपा प्रदेश सचिव सुमीत शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार बार-बार अदालतों में जाकर कर्मचारियों के वित्तीय लाभों को टालने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण हजारों कर्मचारियों को अपने वैध अधिकारों के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक परेशानी भी उठानी पड़ रही है।

शर्मा ने सवाल उठाया कि जब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दे चुके हैं, तो सरकार लाभ देने में देरी क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगहाली का हवाला देकर कर्मचारियों के अधिकारों को अनिश्चितकाल तक नहीं रोका जा सकता। उन्होंने सरकार से अदालती आदेशों का पालन करते हुए पात्र कर्मचारियों को वित्तीय लाभ और वरिष्ठता शीघ्र प्रदान करने की मांग की। डॉ. पुंडीर ने भी सरकार से न्यायिक निर्णयों का सम्मान करने, कर्मचारी संगठनों के साथ संवाद स्थापित करने और सेवा संबंधी अधिकारों का न्यायसंगत समाधान निकालने की अपील की।

अशोक तिवारी ने जगाई नशामुक्त हिमाचल की अलख, युवाओं को खेलों से जुड़ने का आह्वान

कुमारसैन में विद्यार्थियों को नशे के बताए दुष्परिणाम, खेलों से जुड़कर स्वस्थ जीवन अपनाने का संदेश



पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है। नशे के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस या प्रशासन के प्रयासों से सफल नहीं हो सकती, बल्कि इसमें शिक्षकों, अभिभावकों, युवाओं और सामाजिक संगठनों को भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। वह कुमारसैन स्थित डीएवी वरिष्ठ माध्यमिक पब्लिक स्कूल में आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे।

अशोक तिवारी ने कहा कि प्रदेश में चलाए जा रहे एंटी चिट्टा जन आंदोलन का उद्देश्य केवल नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करना नहीं, बल्कि युवाओं को नशे की गिरफ्त में आने से बचाना और उन्हें सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना भी है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को नशे से दूर रखने के लिए शिक्षकों और अभिभावकों को उनके व्यवहार, संगति और गतिविधियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। परिवार और विद्यालय के स्तर पर समय रहते जागरूकता बढ़ाकर युवाओं को गलत रास्ते पर जाने से रोका जा सकता है। उन्होंने लोगों से चिट्टे के खिलाफ जागरूकता का संदेश घर-घर तक पहुंचाने की अपील की।

पुलिस महानिदेशक ने बताया कि 'खेलो हिमाचल, चिट्टा मुक्त हिमाचल' अभियान के तहत कबड्डी, क्रिकेट और वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं आयोजित करने की योजना बनाई गई है। ये प्रतियोगिताएं खंड, जिला और राज्य स्तर पर करवाई जाएंगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा और वे खेल गतिविधियों के माध्यम से अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन, टीम भावना और आत्मविश्वास विकसित करने के साथ उन्हें नशे जैसी बुराइयों से दूर रखने में भी सहायक हैं।

अशोक तिवारी ने विद्यार्थियों से कहा कि किसी भी खतरे, उत्पीड़न या आपातस्थिति में वे बिना डर के पुलिस की सहायता लें। उन्होंने आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112) की जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश ने इस सेवा के राष्ट्रीय प्रदर्शन में 34वें स्थान से प्रथम स्थान तक पहुंचकर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने प्रत्येक विद्यार्थी से आग्रह किया कि वह कम से कम पांच अन्य लोगों को 112 हेल्पलाइन के बारे में जागरूक करे, ताकि जरूरत पड़ने पर अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

पुलिस महानिदेशक ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का भविष्य बच्चों और युवाओं के हाथों में है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी नशे को ना कहने का संकल्प ले और हर परिवार इस अभियान से जुड़े, तो चिट्टामुक्त हिमाचल का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने, कानून का पालन करने, पुलिस का सहयोग करने और नशामुक्त समाज के निर्माण में योगदान देने का सामूहिक संकल्प भी दिलाया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय के प्रधानाचार्य रमेश शर्मा, शिक्षकों और विद्यार्थियों को सफल आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि युवाओं को जागरूक और जिम्मेदार बनाकर ही प्रदेश को नशे की समस्या से मुक्त करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा सकते हैं।

केवल सिंह पठानिया ने दूध प्रोत्साहन राशि बढ़ाने पर मुख्यमंत्री का जताया आभार

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने प्रदेश सरकार की ओर से दूध उत्पादकों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि तीन रुपये से बढ़ाकर छह रुपये प्रति लीटर करने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पशुपालकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। सरकार के इन निर्णयों से हजारों पशुपालक परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिल रहा है।

पठानिया ने कहा कि गैर-सरकारी डेयरी सहकारी समितियों से जुड़े पात्र दूध उत्पादकों को अब प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से छह रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए सरकार ने 14 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। प्रोत्साहन राशि में हुई वृद्धि से दूध उत्पादकों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी और उन्हें पशुपालन व्यवसाय जारी रखने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है, जिसने दूध खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था लागू की। प्रदेश सरकार गाय और भैंस के दूध की खरीद पर देशभर में सर्वाधिक समर्थन मूल्य उपलब्ध करवा रही है। सरकार ने गाय के दूध का खरीद मूल्य 32 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध का मूल्य 47 रुपये से बढ़ाकर 71 रुपये प्रति लीटर किया है। इस फैसले से दूध उत्पादकों को औसतन 48.86 करोड़ रुपये प्रतिमाह का वित्तीय लाभ मिल रहा है। पठानिया ने बताया कि प्रदेश में दूध की खरीद भी एक लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़कर लगभग तीन लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंच गई है। यह बढ़ोतरी डेयरी क्षेत्र में किसानों की बढ़ती भागीदारी और सरकार की प्रोत्साहन नीतियों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले के ढगवार में लगभग 250 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इसकी शुरुआती क्षमता 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन होगी। इसके अतिरिक्त आने वाले वर्षों में विभिन्न जिलों में दूध संग्रहण और प्रसंस्करण सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

ढगवार में 250 करोड़ से बनेगा आधुनिक संयंत्र, दूध प्रसंस्करण क्षमता में होगा विस्तार

उपमुख्य सचेतक ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य पशुपालन को केवल पारंपरिक गतिविधि तक सीमित न रखकर इसे लाभकारी और सम्मानजनक आजीविका के रूप में विकसित करना है। उचित खरीद मूल्य, समय पर भुगतान, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और आधुनिक प्रसंस्करण सुविधाओं के माध्यम से पशुपालकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

रिज मैदान पर देश की एकता और संकल्प शक्ति का दिखेगा संदेश



भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। राष्ट्रीय संकल्प दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर जिला शिमला में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

उपायुक्त ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय संकल्प दिवस तथा सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर ऐतिहासिक रिज मैदान में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू दोनों महान नेताओं को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि देंगे।

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय संकल्प दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ भी दिलाई जाएगी। इसके अतिरिक्त देशभक्ति से ओत-प्रोत गीतों के माध्यम से दोनों नेताओं के योगदान और उनके विचारों को याद किया जाएगा। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयोजन से संबंधित सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर ली जाएं, ताकि कार्यक्रम गरिमापूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त सचिन शर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (प्रोटोकॉल) ज्ञान सागर नेगी और एसडीएम शिमला ग्रामीण कार्तिकेय शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

सुमीत शर्मा ने कर्मचारी लाभों में देरी पर सुक्खू सरकार को घेरा

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव सुमीत शर्मा ने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़े वित्तीय लाभों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज किए जाने पर कांग्रेस सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने के बजाय बार-बार अदालत का दरवाजा खटखटाकर उनके वित्तीय लाभों को टालने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि यह मामला प्रदेश के करीब डेढ़ लाख कर्मचारियों के हितों से जुड़ा है और सरकार की कार्यप्रणाली से हजारों कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान तथा मानसिक परेशानी उठानी पड़ रही है।

◆ सर्वोच्च न्यायालय से याचिका खारिज, कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देने की मांग तेज

सुमीत शर्मा ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2003 से अनुबंध आधार पर नियुक्तियां होती रही हैं। शुरुआती वर्षों में कर्मचारियों को आठ-आठ साल तक अनुबंध पर रखा गया। बाद में यह अवधि घटाकर सात वर्ष, पांच वर्ष, तीन वर्ष और अंततः दो वर्ष की गई। इस दौरान कई कर्मचारियों को नियमितीकरण से पहले की सेवा अवधि के आधार पर वित्तीय लाभ और वरिष्ठता प्राप्त करने के लिए न्यायालय का सहारा लेना पड़ा। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार वर्ष 2024 में हिमाचल प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एक्ट लेकर आई। इसके माध्यम से अनुबंध कर्मचारियों को उनकी पूर्व सेवा अवधि के आधार पर मिलने वाले वित्तीय लाभों और वरिष्ठता से वंचित करने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को अपने वैध अधिकार हासिल करने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है।

सुमीत शर्मा ने बताया कि 25 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने संबंधित कानूनी प्रावधानों को असंवैधानिक करार देते हुए कर्मचारियों को वित्तीय लाभ और वरिष्ठता प्रदान करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि 29 जुलाई 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की एसएलपी खारिज करते हुए कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देने के लिए चार महीने का समय दिया था।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने न्यायालय के आदेशों का पालन करने के बजाय पुनर्विचार याचिका दायर कर दी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने उसे भी खारिज कर दिया है। इसके बावजूद कर्मचारियों को उनके अधिकारों से वंचित रखना उचित नहीं है।

भाजपा प्रदेश सचिव ने सवाल उठाया कि जब न्यायालय कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दे चुका है तो सरकार उनके वित्तीय लाभों का भुगतान करने में देरी क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगहाली का हवाला देकर कर्मचारियों के वैध अधिकारों को अनिश्चितकाल तक नहीं रोका जा सकता।

चायल-कोटी कॉलेज की भावना ने ताइक्वांडो में जीता स्वर्ण



भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से राजकीय महाविद्यालय बैजनाथ में आयोजित अंतरमहाविद्यालय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में राजकीय महाविद्यालय चायल-कोटी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर संस्थान का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में महाविद्यालय की भावना ठाकुर ने स्वर्ण पदक, जबकि हार्दिक शर्मा ने कांस्य पदक हासिल किया। कॉलेज पहुंचने पर दोनों खिलाड़ियों का प्राचार्या, स्टाफ और विद्यार्थियों ने फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया।

महिला वर्ग की अंडर-78 किलोग्राम भार श्रेणी में बीए तृतीय वर्ष की छात्रा भावना ठाकुर ने बेहतरीन खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं, पुरुष वर्ग की अंडर-68 किलोग्राम भार श्रेणी में बीए तृतीय वर्ष के छात्र हार्दिक शर्मा ने तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक अपने नाम किया। दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धि से महाविद्यालय परिसर में खुशी का माहौल है।

खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता के लिए महाविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के सहायक आचार्य हरेंद्र ठाकुर ने प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान किया। उनके प्रयासों और खिलाड़ियों की मेहनत से महाविद्यालय को यह उपलब्धि हासिल हुई। महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. दीप शिखा भारद्वाज ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

शिमला में नशा तस्करों पर शिकंजा, 586 आरोपी गिरफ्तार

12.52 करोड़ की संपत्ति फ्रीज, स्कूलों और पंचायतों तक पहुंचेगा जागरूकता अभियान



नशा छोड़ चुके युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ने में भूमिका निभाए प्रशासन - अनुपम कश्यप

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। जिला एनकॉर्ड (नारको कोऑर्डिनेशन सेंटर) की बैठक उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा की गई और आगामी रणनीति पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने कहा कि नशे के खिलाफ लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अभी भी कई शिक्षण संस्थान ऐसे हैं, जहां तक जागरूकता की मुहिम नहीं पहुंच पाई है। सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों के प्रत्येक शिक्षण संस्थान तक अभियान पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने नशा छोड़ चुके युवाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए भी सकारात्मक प्रयास करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने कहा कि नशे के खिलाफ कार्रवाई केवल तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि युवाओं को नशे से दूर रखने और प्रभावित लोगों के पुनर्वास पर भी ध्यान देना जरूरी है। सभी एसडीएम और डीएसपी को आगामी एनकॉर्ड बैठक में अपने क्षेत्रों में किए गए प्रयासों की प्रस्तुति देने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि यदि सड़क किनारे ढाबों में नशे का कारोबार होता पाया जाता है और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण भी किया गया है तो संबंधित लोगों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए। सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाने के निर्देश भी दिए गए।

इस वर्ष 291 मामले दर्ज, 586 आरोपी गिरफ्तार : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बैठक में जिला पुलिस की कार्रवाई का ब्योरा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अब तक नशे से संबंधित 291 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें 567 पुरुषों और 19 महिलाओं सहित कुल 586 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चालू माह में 28 मामले दर्ज कर 46 पुरुषों और दो महिलाओं सहित 48 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने नशा तस्करी के मामलों में शामिल नेटवर्क को तोड़ने के लिए भी विशेष अभियान चलाया है। वर्ष 2026 में अब तक 66 नेटवर्क ध्वस्त किए गए हैं, जबकि वर्ष 2025 और 2024 में चार-चार नेटवर्क पर कार्रवाई की गई थी।

स्कूलों और पंचायतों में चलाए जागरूकता कार्यक्रम : एसएसपी ने बताया कि युवाओं और आम लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए स्कूलों और पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष पुलिस ने 19 स्कूलों का दौरा किया और छह जागरूकता कार्यक्रम किए। इसके अलावा 15 पंचायत बैठकों में भाग लेकर लोगों को नशे के खिलाफ अभियान से जोड़ने का प्रयास किया गया। एसएचओ और पुलिस चौकी प्रभारियों की ओर से भी छह स्कूलों का दौरा किया गया।

मशोबरा स्कूल में सात दिवसीय एनएसएस शिविर शुरू, सेवा संस्कारों पर जोर



भारतेन्दु संवाददाता, मशोबरा। राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मशोबरा में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के सात दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ उत्साह और सेवाभाव के साथ हुआ। शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों में सामाजिक उत्तरदायित्व, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, सामुदायिक सेवा और राष्ट्रप्रेम की भावना विकसित करना है।

कार्यक्रम में शिक्षाविद् एवं पोर्टमोर विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य नरेंद्र सूद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में शिव देव, आशा और विद्यालय की पूर्व शिक्षिका डॉ. कंचन वर्मा शामिल रहीं। विद्यालय परिवार ने सभी अतिथियों का स्वागत किया।

मुख्य अतिथि नरेंद्र सूद ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए सेवा, संस्कार और समर्पण के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ जीवन मूल्यों को अपनाना भी आवश्यक है। अनुशासन, परिश्रम, सकारात्मक सोच और सामाजिक समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

विद्यालय की प्रधानाचार्या मीनाक्षी सूद ने कहा कि एनएसएस विद्यार्थियों में निःस्वार्थ सेवा, सहयोग, नेतृत्व और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने स्वयंसेवियों से स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जनकल्याण की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया। उन्होंने एनएसएस के मूल मंत्र 'मैं नहीं, बल्कि आप' को सामूहिक कल्याण और निःस्वार्थ सेवा का प्रतीक बताया।

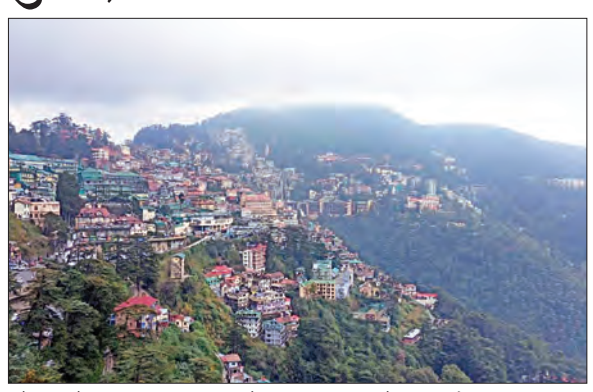
हिमपात किन्नौर, लाहौल-स्पीति और चंबा की चोटियों पर हिमपात, तीन नवंबर से प्रदेशभर में मौसम साफ रहने का अनुमान

हिमाचल में बर्फबारी से बढ़ी ठिठुरन, जनजातीय क्षेत्रों में पारा शून्य से नीचे

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार दूसरे दिन भी बदला हुआ है। शुक्रवार को किन्नौर, लाहौल-स्पीति और चंबा जिलों की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पर बर्फबारी का दौर जारी रहा। इससे प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। जनजातीय इलाकों में तापमान शून्य से नीचे पहुंचने लगा है। कुकुमसेरी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान माइनस 1.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दो नवंबर तक कुछ जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है, जबकि तीन नवंबर से प्रदेशभर में मौसम साफ रहने का अनुमान है।

राजधानी शिमला और पर्यटन नगरी मनाली में शुक्रवार सुबह से ही बादल छाए रहे। वहीं, मैदानी इलाकों में मौसम का मिला-जुला असर देखने को मिला। कुछ स्थानों पर धूप खिली रही, जबकि कई क्षेत्रों में आसमान पर बादल छाए रहे। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार दूसरे दिन हिमपात होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। विशेषकर किन्नौर और लाहौल-स्पीति के जनजातीय क्षेत्रों में रात और सुबह के समय ठंड का असर अधिक महसूस किया जा रहा है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 31 अक्टूबर को लाहौल-स्पीति जिले के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है। पहली नवंबर को मौसम में फिर बदलाव आएगा। इस दिन चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, लाहौल-स्पीति और किन्नौर जिलों में बारिश तथा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने का अनुमान है। दो नवंबर को चंबा, कांगड़ा, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों में मौसम खराब रह सकता है। इसके बाद तीन से पांच नवंबर तक प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना जताई गई है।



बीते 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई। किन्नौर जिले के मोरंग में सबसे अधिक 12 मिलीमीटर वर्षा हुई। धर्मपुर में छह, सांगला में पांच, कसौली में चार, पांवटा साहिब में तीन और कल्पा में दो मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में हुई बारिश के कारण ठंड का प्रभाव बढ़ा है।

तापमान के आंकड़ों के अनुसार कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 1.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि ताबो में 2.5 डिग्री, कल्पा में 4.4 और कुफरी में 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भरमौर में न्यूनतम तापमान नौ डिग्री, सेओबाग में 9.8 और मनाली में 9.9 डिग्री सेल्सियस रहा। शिमला में पारा 10 डिग्री और सोलन में 10.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा पालमपुर में 11 डिग्री, भुंतर में 11.2, बजौरा में 11.3 और ऊना में 11.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। बिलासपुर में 12, जुब्बड़हट्टी में 12.8, कांगड़ा में 13.2 और सुंदरनगर में 13.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बरठीं में 13.4, देहरा गोपीपुर में 14, नाहन और मंडी में 14.1 डिग्री तापमान रहा।

एसजेवीएन का विशेष अभियान 6.0, स्वच्छता के साथ प्रशासनिक कार्यप्रणाली में लाया सुधार

13.32 टन बैटरियों का निस्तारण, 25 टन ई-कचरे की पहचान, लंबित फाइलों का हुआ समाधान



भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन) ने स्वच्छता को संस्थागत कार्यप्रणाली का हिस्सा बनाने और कार्यालयों में लंबित मामलों के निपटारे की दिशा में विशेष अभियान 6.0 के तहत कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। विद्युत मंत्रालय और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के मार्गदर्शन में चलाए गए इस अभियान के अंतर्गत निगम के सभी कार्यालयों और परियोजनाओं में स्वच्छता, अभिलेख प्रबंधन, अपशिष्ट निस्तारण तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। अभियान के दौरान एसजेवीएन ने निगम मुख्यालय से 7,500 किलोग्राम और नाथपा झाकड़ी जल विद्युत स्टेशन (एनजेएचपीएस) से 5,820 किलोग्राम प्रयुक्त बैटरियों का व्यवस्थित निपटान किया। इस प्रकार कुल 13.32 टन प्रयुक्त बैटरियों का निस्तारण किया गया, जिनका कुल मूल्य 16,11,453 रुपये आंका गया है। इसके अतिरिक्त करीब 25 टन ई-कचरे और अनुपयोगी सामग्री की पहचान की गई। इसमें लगभग 800 किलोग्राम पुराने टायर भी शामिल हैं।

इन सामग्रियों के उचित निस्तारण से कार्यालयों और परियोजना परिसरों में उपलब्ध स्थान का बेहतर उपयोग करने के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। एसजेवीएन ने पर्यावरण संरक्षण के साथ प्रशासनिक कार्यों को गति देने के लिए भी कदम उठाए। निगम की विभिन्न परियोजनाओं में लगभग 585 किलोग्राम वजन वाली 322 लंबित फाइलों और दस्तावेजों का निपटारा किया गया।

न्यूज शॉर्ट्स

बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने निकाली जागरूकता रैली



भारतेन्दु संवाददाता, देहरादून। केंद्रीय सतर्कता आयोग के मार्गदर्शन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के देहरादून अंचल द्वारा 26 अक्टूबर से एक नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम 'सत्यनिष्ठा से समृद्धि' रखी गई है। इसी कड़ी में 30 अक्टूबर को जागरूकता रैली निकाली गई। इसका शुभारंभ उप अंचल प्रबंधक आशुतोष त्रिपाठी और अंचल सतर्कता अधिकारी दीपक पाण्डेय ने किया। रैली के माध्यम से ईमानदारी, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार विरोधी जागरूकता का संदेश दिया गया।

केदारनाथ धाम में छह इंच बर्फ जमी

भारतेन्दु संवाददाता, रुद्रप्रयाग। केदारनाथ धाम में गुरुवार और शुक्रवार को हुई बर्फबारी से पूरा क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर में ढक गया। धाम में करीब छह इंच तक बर्फ जम गई है। बर्फबारी के बावजूद बाबा केदार के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। कड़ाके की ठंड के बीच भक्त घंटों कतारों में खड़े होकर दर्शन करते रहे। वहीं, निचले इलाकों में बारिश और ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम में आए बदलाव से ठिठुरन बढ़ गई है। दूसरी ओर, ऊंचाई वाले जंगलों और बुग्यालों में रह रहे भेड़पालकों ने अपने पशुओं के साथ निचले गांवों की ओर लौटना शुरू कर दिया है।

पोस्ट हटाना पर्याप्त नहीं कांग्रेस माफी मांगे : दीप्ति

भारतेन्दु संवाददाता, देहरादून। भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से राष्ट्रीय सेविका समिति की महिलाओं के प्रति की गई कथित अभद्र टिप्पणी पर विरोध जताया है। प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि आपत्तिजनक पोस्ट हटाना पर्याप्त नहीं है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा कि महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान से जुड़े मुद्दों पर मोर्चा आवाज उठाता रहेगा। मातृशक्ति लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी।

देहरादून में गूंजेगी गोरखाली संस्कृति की पहचान

विकास बलूनी

देहरादून। देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विविधता और गोरखाली परंपराओं का संगम एक बार फिर देखने को मिलेगा। देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित महेंद्र ग्राउंड में 30 अक्टूबर से एक नवंबर तक दसवें गोरखा दशैं-दीपावली महोत्सव एवं राजकीय मेले-2026 का आयोजन किया जा रहा है। वीर गोरखा कल्याण समिति की ओर से आयोजित यह तीन दिवसीय महोत्सव गोरखा समाज की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और लोककलाओं को करीब से जानने का अवसर प्रदान करेगा।

◆ समारोह में लोकगीतों और पारंपरिक कलाओं का दिखेगा संगम

मेले में पारंपरिक गोरखाली वेशभूषा, नेपाली खान-पान के विशेष व्यंजन, लोककलाओं और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से गोरखा समाज की सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिलेगी।



नेपाली संस्कृति और परंपराओं की दिखेगी झलक

लोकगीतों और पारंपरिक प्रस्तुतियों के जरिए नेपाली संस्कृति को मंच प्रदान किया जाएगा। साथ ही दशैं और दीपावली जैसे प्रमुख पर्वों से जुड़ी परंपराओं और रीति-रिवाजों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। उत्तराखंड की पहचान केवल प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां विभिन्न समुदायों की भाषा, संस्कृति, परंपराएं और आपसी भाईचारा भी इसकी विशेष पहचान हैं। गोरखा समाज की विरासत प्रदेश की इसी सांस्कृतिक विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे आयोजनों से विभिन्न समुदायों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलता है और नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जुड़ने का अवसर मिलता है। महोत्सव के माध्यम से गोरखाली संस्कृति के संरक्षण और प्रचार के साथ सामाजिक सौहार्द को भी मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा।

देहरादून में बेरोजगारों का प्रदर्शन
सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

17 सूत्रीय मांगों को लेकर बेरोजगार युवाओं ने किया सचिवालय कूच

भारतेन्दु संवाददाता, देहरादून

उत्तराखंड के विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती विज्ञप्तियां जारी करने और लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को जल्द पूरा करने की मांग को लेकर शुक्रवार को बेरोजगार युवाओं ने राजधानी देहरादून में महारैली निकाली। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के नेतृत्व में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से पहुंचे युवाओं ने परेड ग्राउंड से सचिवालय तक कूच किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी 17 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने की आवाज उठाई। युवाओं ने कहा कि लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को अब तक राहत नहीं मिली है। कई विभागों में पद रिक्त होने के बावजूद भर्ती विज्ञप्तियां जारी नहीं की जा रही हैं, जिससे योग्य युवाओं को रोजगार के अवसरों से वंचित रहना पड़ रहा है।

महारैली का नेतृत्व कर रहे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि प्रदेश के हजारों युवा विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कई भर्तियों की प्रक्रियाएं लंबे समय से लंबित हैं, जबकि कुछ परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने में भी अनावश्यक देरी हो रही है। इससे अभ्यर्थियों का समय और मेहनत दोनों प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए सभी विभागों में खाली पदों का आकलन किया जाए और जल्द भर्ती विज्ञप्तियां जारी की जाएं। साथ ही लंबित चयन प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होने तक आंदोलन जारी रखा जाएगा।

संघ की प्रमुख मांगों में सिंचाई विभाग में प्रतिरूप सहायक के पदों पर भर्ती विज्ञप्ति जारी करना और लोक निर्माण विभाग में अमीन के पदों के लिए नया भर्ती विज्ञापन निकालना शामिल है।



युवाओं ने रोजगार के लिए मांगे ठोस कदम।

लंबित भर्तियां समयबद्ध पूरी करने की मांग

इससे युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण और रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। युवाओं ने सभी सरकारी विभागों में रिक्त पदों का पारदर्शी आकलन कर नियमित भर्ती कैलेंडर जारी करने की मांग की। उनका कहना था कि भर्ती परीक्षाओं और चयन प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी रोकने के लिए स्पष्ट समयसीमा तय होनी चाहिए। बेरोजगार संघ ने सरकार से 17 सूत्रीय मांगों पर जल्द निर्णय लेने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की।

आईटीआई में 859 अनुदेशकों की भर्ती की मांग

इसके अलावा शहरी विकास विभाग में अधिशासी अधिकारी, पर्यावरण पर्यवेक्षक और कर संग्रहकर्ता के रिक्त पदों को भरने की मांग भी उठाई गई। युवाओं ने उच्च शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला सहायकों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और विभिन्न विभागों में खाली पुस्तकालयाध्यक्ष के पद भरने की मांग रखी। इसके साथ ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में अनुदेशकों के रिक्त 859 पदों पर भर्ती विज्ञप्ति जारी करने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण से जुड़े संस्थानों में पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति जरूरी है।

जनता का प्यार मेरी ताकत : रेखा आर्या

रेखा आर्या ने कांग्रेस से मांगा विकास कार्यों का हिसाब

भारतेन्दु संवाददाता, सोमेश्वर

कैबिनेट मंत्री एवं सोमेश्वर की विधायक रेखा आर्या ने शुक्रवार को विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में शिरकत की। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जनसभा को संबोधित करते हुए रेखा आर्या ने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियों में भी सोमेश्वर की जनता ने जिस तरह उनके प्रति प्रेम, विश्वास और अपनत्व दिखाया है, वह उनके जीवन की सबसे बड़ी व्यक्तिगत पूंजी है। जनता का स्नेह और आशीर्वाद ही उनकी असली ताकत है। उन्होंने कहा कि जनता के इस भरोसे को बनाए रखना और क्षेत्र की अपेक्षाओं पर खरा उतरना उनकी जिम्मेदारी है।

इस दौरान रेखा आर्या ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष उनकी परिस्थितियों को लेकर अनर्गल सवाल उठा रहा है। कांग्रेस को दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अपने कार्यकाल का हिसाब जनता के सामने रखना चाहिए। उसे अपने कार्यकाल में हुए कार्यों और कथित घोटालों पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बताए कि सत्ता में रहते हुए उसने सोमेश्वर और पूरे प्रदेश के विकास के लिए क्या किया।



मसूरी में हरे-भरे पेड़ों पर चली आरी, रातोंरात गायब किए कटे पेड़

◆ क्लिफ कॉटेज एस्टेट में पेड़ों के कटान से मचा हड़कंप

सुनील सोनकर

मसूरी। पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार बढ़ते निर्माण के बीच हरियाली पर संकट गहराने लगा है। मसूरी पेट्रोल पंप के सामने पार्किंग के निकट क्लिफ कॉटेज एस्टेट में हरे-भरे पेड़ों को काटने और कुछ पेड़ों को सुखाने की कोशिश के आरोप लगे हैं। हैरानी की बात यह है कि कटे पेड़ों को रातोंरात मौके से हटा दिया गया, जबकि उनकी जड़ें जमीन में मौजूद मिलीं। शिकायत मिलने पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और संपत्ति स्वामी का चालान किया। साथ ही शेष पेड़ों पर नंबरिंग कर उनकी पहचान सुनिश्चित की गई। इस मामले ने प्लिंथ प्रमाणपत्र, वन विभाग की अनापत्ति और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) से नक्शा स्वीकृत कराने की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए हैं। आरोप हैं कि पुराने निर्माण के स्पष्ट प्रमाण नहीं होने के बावजूद कुछ भूखंडों पर प्रमाणपत्र जारी कराने की कोशिश होती है। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका के अभिलेखों, वन विभाग की एनओसी और भवन नक्शों की जांच की मांग उठाई है। लोगों का कहना है कि अनियंत्रित निर्माण और पेड़ों की कटाई से मसूरी की पर्यावरणीय सुरक्षा, पहाड़ी ढलानों और भूस्खलन के खतरे पर गंभीर असर पड़ सकता है।

युवाओं को मिलेगा देश-विदेश में रोजगार

युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय रोजगार के अवसर तलाशेगी सरकार

अनिल थपलियाल

देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में स्टेट स्टीयरिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इसमें उत्तराखंड के युवाओं को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और देश-विदेश में रोजगार से जोड़ने पर चर्चा हुई। बैठक में स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट लिमिटेड की ओर से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर विकसित करने को लेकर प्रस्तुतीकरण दिया गया।

मुख्य सचिव ने कंपनी और संबंधित अधिकारियों को प्रस्तावित रोजगार मॉडल के सभी पहलुओं पर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले योजना का राजस्व मॉडल स्पष्ट किया जाए। इसके साथ ही यह भी तय किया जाए कि कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा, उन्हें किस प्रकार का कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण के बाद उनके लिए रोजगार एवं नियुक्ति की व्यवस्था कैसे सुनिश्चित होगी।

उन्होंने रोजगार की संभावित मांग के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने पर जोर दिया, ताकि युवाओं को बाजार की जरूरतों के अनुरूप दक्ष बनाया जा सके। इसके लिए अनुभवी प्रशिक्षकों की पहचान कर गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।



सरकार का जोर

मुख्य सचिव ने कहा कि इस पहल में युवाओं के साथ महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाए, जिससे उन्हें स्वरोजगार और देश-विदेश में नौकरी के बेहतर अवसर मिल सकें। उन्होंने कंपनी को सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा करने और संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए कार्यशाला आयोजित करने को कहा।

साइबर सुरक्षा के प्रति किया जागरूक

देहरादून में सेंट्रल बैंक ने निकाली सतर्कता जागरूकता वॉकाथॉन

भारतेन्दु संवाददाता, देहरादून। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से 'सत्यनिष्ठा से समृद्धि की ओर' संदेश के साथ 17 अगस्त से 16 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता अभियान-2026 चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य समाज में ईमानदारी, पारदर्शिता और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के साथ भ्रष्टाचार के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसके तहत देहरादून क्षेत्र की विभिन्न शाखाओं द्वारा ग्रामीण इलाकों में ग्राम सभाएं आयोजित कर आमजन को सतर्कता, साइबर सुरक्षा और डिजिटल बैंकिंग से जुड़ी सावधानियों की जानकारी दी जा रही है। वहीं, विद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं।

इसी क्रम में 30 अक्टूबर को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से देहरादून में वॉकाथॉन निकाली गई। क्षेत्रीय प्रमुख रजत बजाज के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय और देहरादून मुख्य शाखा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने आमजन को सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त समाज का संदेश दिया। इस अवसर पर रजत बजाज ने कहा कि ईमानदारी और सत्यनिष्ठा प्रत्येक व्यक्ति के कार्य एवं व्यवहार का अभिन्न हिस्सा होनी चाहिए। उन्होंने सभी से दैनिक जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाने की अपील की।



मांगें पूरी नहीं हुई तो खून से खत लिखेंगे पीआरडी जवान

भारतेन्दु संवाददाता, पौड़ी। प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों ने लंबित मांगों को लेकर प्रदेश सरकार को नौ नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन के प्रदेश संयोजक प्रमोद मंद्रवाल ने कहा कि निर्धारित समय तक मांगों के संबंध में शासनादेश जारी नहीं हुआ तो प्रदेशभर के जवान नौ नवंबर को खून से पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विभागीय मंत्री रेखा आर्य, प्रदेश के पांचों सांसदों, मुख्य सचिव और उच्चाधिकारियों को भेजेंगे। मंद्रवाल ने बताया कि जवान लंबे समय से दो प्रमुख मांगें उठा रहे हैं। इनमें समान काम के लिए समान वेतन और होमगार्ड व उपनल कर्मचारियों की तर्ज पर मूल वेतन पर महंगाई भत्ता (डीए) देने की मांग शामिल है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर संगठन उग्र आंदोलन शुरू करेगा। साथ ही वर्ष 2027 में भी सरकार के प्रति विरोध दर्ज कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन और आगे की रणनीति के लिए सरकार, प्रशासन और संबंधित विभाग जिम्मेदार होंगे।

स्वच्छता अभियान के तहत देहरादून में पर्यावरण मित्रों को मिला सम्मान



भारतेन्दु संवाददाता, देहरादून। देशव्यापी स्वच्छता अभियान 6.0 के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को नगर निगम देहरादून में स्वच्छता सैनिक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 पर्यावरण मित्रों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर निगम आयुक्त आलोक कुमार पांडेय ने की।

विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आनंद शुक्ला, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन के अध्यक्ष सुनील कुमार खैरवाल और सचिव धीरज भारती उपस्थित रहे। सीबीसी के कार्यक्रम अधिकारी अनिल दत्त शर्मा ने कहा कि आयोजन का उद्देश्य स्वच्छता, स्वास्थ्य और साफ-सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अपनाकर ही स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है। कार्यक्रम में पर्यावरण मित्रों के योगदान की सराहना करते हुए अधिकारियों ने दैनिक जीवन और कार्यस्थल पर स्वच्छता की आदतें अपनाने का आह्वान किया।

बारामूला में तैनात पिंडर घाटी के जवान का निधन, क्षेत्र में शोक

भारतेन्दु संवाददाता, थराली/देवाल। पिंडर घाटी के एक और जवान का देशसेवा करते हुए आकस्मिक निधन हो गया। विकासखंड देवाल के सुदूरवर्ती हरमल गांव निवासी 28 वर्षीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जम्मू-कश्मीर के बारामूला में तैनात थे। वह 11वीं गढ़वाल राइफल में नायब सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। बुधवार को अचानक स्वास्थ्य खराब होने से उनका निधन हो गया। जवान के निधन की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

शुक्रवार को सेना का विशेष दस्ता जवान के पार्थिव शरीर को लेकर देहरादून के नेहरू ग्राम पहुंचा, जहां उनके परिजनों ने अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पार्थिव शरीर को हरिद्वार के चंडी घाट ले जाया गया, जहां सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।



राज्यमंत्री रमेश गड़िया ने दी श्रद्धांजलि

इस दौरान दर्जाधारी राज्यमंत्री रमेश गड़िया और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी सहित कई गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। जवान के पिता देव सिंह गड़िया भी सेना से सेवानिवृत्त थे। विश्वनाथ अपने पीछे पत्नी जानकी देवी, सात वर्षीय बेटी शानवी, चार वर्षीय बेटे श्रेयांस और मां नारायणी देवी सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। विधायक भूपाल राम टम्टा सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया।

देहरादून में पीएनबी कर्मचारियों ने किया रक्तदान

भारतेन्दु संवाददाता, देहरादून। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की ओर से सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2026 के तहत जोनल कार्यालय, आईटी पार्क, सहस्त्रधारा में वाकथॉन और स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जोनल हेड अनुपम, उप जोनल प्रबंधक (डीजेडएम) राजेंद्र भाटिया और सर्कल प्रमुख अभिनंदन सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसमें बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वाकथॉन के माध्यम से प्रतिभागियों ने सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त समाज का संदेश दिया। इसके बाद आयोजित रक्तदान शिविर में बैंक कर्मचारियों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर सामाजिक जिम्मेदारी निभाई। कार्यक्रम के समापन पर बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैंकिंग कार्यों में नैतिक मूल्यों, ईमानदारी और पारदर्शिता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संस्थागत कार्यप्रणाली में सत्यनिष्ठा बनाए रखना सभी कर्मचारियों की सामूहिक जिम्मेदारी है।

सहायता | अर्धकुंभ-2027 की तैयारियों को केंद्र का सहयोग, 7,260 टन गेहूं और इतना ही चावल मिला

अर्धकुंभ के लिए 14,520 मीट्रिक टन अनाज आवंटित

अनिल थपलियाल

हरिद्वार। हरिद्वार में प्रस्तावित अर्धकुंभ मेला-2027 के सफल और सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं, साधु-संतों और अन्य लोगों को खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 14,520 मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित किया है। इसमें 7,260 मीट्रिक टन गेहूं और इतनी ही मात्रा में चावल शामिल है। केंद्र के इस निर्णय से अर्धकुंभ के दौरान खाद्य सामग्री की उपलब्धता बनाए रखने और आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन की जानकारी दी है। भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से यह आवंटन उत्तराखंड सरकार की मांग पर किया गया है। राज्य सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया था कि अर्धकुंभ मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने की संभावना को देखते हुए खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही मेले की अवधि में खाद्य सामग्री की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए पहले से आवश्यक प्रबंध किए जाएं।

हरिद्वार में आयोजित होने वाला अर्धकुंभ मेला धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण आयोजन है। इसमें देश के विभिन्न राज्यों के अलावा विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना रहती है। ऐसे बड़े आयोजन के दौरान भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन से सरकारी राशन वितरण व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही जरूरत के अनुसार गेहूं और चावल की उपलब्धता बनाए रखने में भी सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अर्धकुंभ मेले के लिए उत्तराखंड को अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस सहयोग से मेले के दौरान खाद्य सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आपूर्ति और वितरण व्यवस्था को भी सुचारु बनाए रखा जा सकेगा। राज्य सरकार अर्धकुंभ मेले के आयोजन को व्यवस्थित बनाने के लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर रही है। खाद्यान्न की उपलब्धता से जुड़ा यह निर्णय आयोजन की तैयारियों में महत्वपूर्ण सहयोग माना जा रहा है। इससे मेले के दौरान श्रद्धालुओं और अन्य जरूरतमंद लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए आवश्यक व्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी।



हरिद्वार में खाद्यान्न आपूर्ति सुचारु रखने की तैयारी

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन की जानकारी दी है। भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से यह आवंटन उत्तराखंड सरकार की मांग पर किया गया है।

धामी ने जताया आभार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अर्धकुंभ मेले के लिए उत्तराखंड को अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस सहयोग से मेले के दौरान खाद्य सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आपूर्ति और वितरण व्यवस्था को भी सुचारु बनाए रखा जा सकेगा। राज्य सरकार अर्धकुंभ मेले के आयोजन को व्यवस्थित बनाने के लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर रही है। खाद्यान्न की उपलब्धता से जुड़ा यह निर्णय आयोजन की तैयारियों में महत्वपूर्ण सहयोग माना जा रहा है। इससे मेले के दौरान श्रद्धालुओं और अन्य जरूरतमंद लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए आवश्यक व्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी।

संगरूर में खन्ना को आगे कर बादल ने खेला चुनावी दांव

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

संगरूर (विवेक सिंधवानी, सोनू)। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। इसी बीच शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने संगरूर के व्यापारियों और उद्योगपतियों को अपने पक्ष में लामबंद करने की कोशिश की। गढ़ दिवस के अवसर पर आयोजित व्यापारी मिलन समारोह में उन्होंने पूर्व विधायक अरविंद खन्ना के समर्थन में खुलकर प्रचार किया। सुखबीर बादल ने संगरूर के लोगों से खन्ना को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील करते हुए उन्हें क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम नेता बताया।

व्यापारियों को संबोधित करते हुए सुखबीर बादल ने अरविंद खन्ना की तुलना एक कुशल डॉक्टर से की। उन्होंने कहा कि उन्होंने संगरूर के लोगों और व्यापार मंडल को एक बेहतरीन डॉक्टर दिया है, जो उनकी हर समस्या का इलाज करने में सक्षम है। अब इस डॉक्टर को चुनने की जिम्मेदारी जनता की है। उनके इस बयान के जरिए उन्होंने खन्ना को क्षेत्र के लोगों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा कि खन्ना स्थानीय व्यापारियों और आम जनता की समस्याओं को समझते हैं और उनका समाधान करने की क्षमता रखते हैं।



पंजाब की सियासत और आगामी चुनावी हलचलों के बीच शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री

सुखबीर बादल ने व्यापारिक वर्ग को भरोसा दिलाते हुए कहा कि संगरूर के उद्योगपतियों और आम लोगों की करीब 90 प्रतिशत समस्याओं का समाधान अरविंद खन्ना स्वयं कर देंगे। शेष 10 प्रतिशत समस्याओं के लिए वह खुद उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने खन्ना के साथ अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि वह संगरूर के लोगों को अपना सबसे करीबी और भरोसेमंद साथी सौंप रहे हैं। बादल ने कहा कि अरविंद खन्ना अकाली दल के उन गिने-चुने नेताओं में शामिल हैं, जो रात एक बजे भी उन्हें फोन करके उठा सकते हैं। उन्होंने खन्ना को ईमानदार और संपन्न परिवार से जुड़ा व्यक्ति बताते हुए कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना है। कार्यक्रम के दौरान संगरूर के व्यापारियों और उद्योगपतियों ने कारोबार से जुड़ी समस्याओं और अपनी अपेक्षाओं को अकाली दल नेतृत्व के सामने रखा। सुखबीर बादल के आश्वासन और अरविंद खन्ना पर जताए गए भरोसे से स्थानीय व्यापारिक वर्ग में उत्साह दिखाई दिया। समारोह के माध्यम से अकाली दल ने व्यापारियों और उद्योगपतियों के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने का प्रयास किया। साथ ही अरविंद खन्ना को आगे रखकर पार्टी ने संगरूर में आगामी चुनावों के लिए अपनी रणनीति के संकेत भी दिए।

अरविंद खन्ना को उद्योग मंत्री बनाने के दिए संकेत

समारोह में संगरूर के उद्योग जगत ने भी अपनी मांगें अकाली दल नेतृत्व के सामने रखीं। इंडस्ट्री चैंबर के वरिष्ठ वाइस चेयरमैन घनश्याम कांसल ने सुखबीर बादल से आग्रह किया कि यदि राज्य में अकाली दल की सरकार बनती है तो प्रत्येक जिले के उद्योगपतियों को नई औद्योगिक नीति तैयार करने वाली मुख्य टीम में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि उद्योगों की वास्तविक समस्याओं और जरूरतों को ध्यान में रखकर ही प्रभावी नीति तैयार की जानी चाहिए। इस मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए सुखबीर बादल ने अरविंद खन्ना को भविष्य में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने के संकेत दिए। उन्होंने हंसते हुए कहा कि क्या पता, अकाली दल की सरकार बनने पर पंजाब की नई औद्योगिक नीति अरविंद खन्ना के हाथों ही तैयार करवाई जाए। उनके इस बयान को खन्ना को संभावित मंत्रिमंडल में अहम स्थान दिए जाने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। समारोह में सुखबीर बादल ने कहा कि अकाली दल की सरकार बनने पर उद्योगों को बढ़ावा देना प्राथमिकता होगी। उन्होंने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं को नीतिगत स्तर पर उठाया जाएगा और कारोबार के अनुकूल माहौल तैयार करने के प्रयास किए जाएंगे।

लुधियाना में ऑटो पार्ट्स गोदाम आग से जलकर हुआ राख

भीषण लपटों ने निगला गोदाम, करोड़ों का सामान राख होने की आशंका

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना

गिल गांव इलाके में शुक्रवार सुबह एक विशाल वेयरहाउस में अचानक भीषण आग लगने से आसपास के क्षेत्र में अफरातफरी मच गई। राधा स्वामी सत्संग घर और फास्टवे कार्यालय के पास स्थित करीब 2000 गज में फैले टेक्नो ऑटो नामक गोदाम में आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। गोदाम में रखे ऑटो स्पेयर पार्ट्स और बड़ी मात्रा में पैकेजिंग सामग्री आग की चपेट में आ गई। आग से उठते काले धुएं के गुबार दूर तक दिखाई दिए। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की करीब 15 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू कर दिया।

जानकारी के अनुसार, गिल गांव स्थित इस वेयरहाउस में टाटा कंपनी के ऑटो पार्ट्स का बड़ा स्टॉक रखा जाता है। परिसर में गोदाम के साथ कार्यालय भी बना हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सुबह गोदाम के अंदरूनी हिस्से से अचानक धुआं उठता दिखाई दिया। कुछ ही देर में आग ने तेजी से फैलना शुरू कर दिया। गोदाम में मौजूद कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, रबर और अन्य पैकेजिंग सामग्री के कारण आग ने भयावह रूप ले लिया। देखते ही देखते लपटें पूरे परिसर में फैल गईं। आग की ऊंची लपटें देखकर वहां मौजूद कर्मचारियों और आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। कर्मचारियों ने तत्काल बाहर निकलकर अपनी जान बचाई और घटना की सूचना दमकल विभाग को दी।



आग की तीव्रता को देखते हुए आसपास के फायर स्टेशनों से दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। कुछ ही समय में करीब 15 फायर टेंडर आग बुझाने के काम में जुट गए। दमकल कर्मी गोदाम के अलग-अलग हिस्सों से पानी की बौछारें कर आग पर काबू पाने का प्रयास करते रहे। गोदाम का क्षेत्रफल बड़ा होने और अंदर घना धुआं भरा होने के कारण दमकल कर्मियों को आग के केंद्र तक पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद टीमें लगातार आग को आसपास की इमारतों तक फैलने से रोकने में जुटी रहीं।

बताया जा रहा है कि गोदाम के मालिक दिल्ली में रहते हैं। आग लगने की जानकारी कर्मचारियों ने उन्हें फोन पर दी। सूचना मिलते ही मालिक दिल्ली से लुधियाना के लिए रवाना हो गए। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के माध्यम से उन्हें घटना का पता चला है। फिलहाल आग से हुए नुकसान का सही आकलन नहीं हो पाया है। मालिक के मौके पर पहुंचकर गोदाम का निरीक्षण करने के बाद ही नुकसान की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। हालांकि, शुरुआती आशंका है कि आग में करोड़ों रुपये का सामान जलकर नष्ट हो सकता है।

घटना के बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर मौजूद रहीं। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। दमकल विभाग की प्राथमिकता आग पर पूरी तरह काबू पाने और उसे आसपास के भवनों तक फैलने से रोकने की है। आग बुझने के बाद ही नुकसान और घटना के कारणों की विस्तृत जानकारी सामने आ सकेगी। इस घटना के बाद आसपास के कारोबारियों और स्थानीय निवासियों में भी चिंता का माहौल बना रहा। गोदाम में आग की लपटें और धुएं का गुबार देखकर बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल के आसपास एकत्र हो गए। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लोगों को सुरक्षित दूरी पर रहने की हिदायत दी, ताकि दमकल कर्मियों को राहत कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए। गोदाम में रखे सामान की मात्रा अधिक होने के कारण आग से नुकसान बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार, आग की लपटें काफी ऊंची थीं और धुआं दूर-दूर तक दिखाई दे रहा था। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना सामने नहीं आई है। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए विभागीय जांच की जाएगी।

चंडीगढ़ हादसे में मृत बिजलीकर्मी के परिवार को 84 लाख मुआवजा

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले यूटी बिजली विभाग के कर्मचारी रणजीत सिंह के परिवार को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ ने 84.12 लाख रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल ने मुआवजा राशि पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने के भी निर्देश दिए हैं। यह हादसा 22 मई 2024 को सेक्टर-18/19/20/21 के चौक पर हुआ था। रणजीत सिंह अपनी एक्टिवा पर सेक्टर-18 स्थित बिजली कार्यालय से सेक्टर-21 स्थित घर जा रहे थे। इसी दौरान सेना के एक ट्रक ने उनकी एक्टिवा को टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सेक्टर-16 स्थित जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। परिवार की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट ठाकुर करतार सिंह ने बताया कि याचिका में ट्रक चालक पर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाया गया था। याचिका के अनुसार, रणजीत सिंह की उम्र 59 वर्ष थी और वह यूटी बिजली विभाग में कार्यरत थे। उनकी मासिक आय करीब 1.24 लाख रुपये थी। सभी कटौतियों के बाद उन्हें लगभग 87 हजार रुपये वेतन मिलता था। परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उन्हीं पर निर्भर थी। उनके निधन के बाद परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

2027 चुनाव की तैयारी तेज, राहुल गांधी की संगरूर रैली और संगठन मजबूती पर होगी चर्चा

खरगे ने पंजाब कांग्रेस सांसदों की बुलाई बैठक, चुनावी रणनीति पर होगा मंथन

राहुल गांधी के दौरे से पहले प्रदेश संगठन को सक्रिय करने की कवायद

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य में दोबारा सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से पार्टी नेतृत्व ने अभी से चुनावी रणनीति बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज दिल्ली में पंजाब कांग्रेस के सभी सांसदों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति, संगठनात्मक तैयारियों और राज्य में पार्टी की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है।

बैठक में शामिल होने के लिए पंजाब के सभी कांग्रेस सांसदों को निर्देश दिए गए हैं। आज सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक को 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस नेतृत्व पंजाब में पार्टी की मौजूदा स्थिति का आकलन करने के साथ ही संगठन को मजबूत बनाने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की रणनीति पर विचार करेगा। इसके अलावा नेताओं के बीच तालमेल बढ़ाने, जनता के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत करने और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने पर भी चर्चा हो सकती है।


राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे की पुरानी तस्वीर

जानकारी के अनुसार, बैठक में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, पूर्व मुख्यमंत्री एवं जालंधर के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी, डॉ. अमर सिंह और डॉ. सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत पंजाब के अन्य कांग्रेस सांसदों के शामिल होने की उम्मीद है। हाईकमान सांसदों से उनके क्षेत्रों की राजनीतिक परिस्थितियों और पार्टी की गतिविधियों को लेकर भी जानकारी ले सकता है। इसके आधार पर आगामी चुनाव के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। कांग्रेस की ओर से एक नवंबर को दिल्ली में 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली आयोजित की जानी है। इसे लेकर भी पार्टी नेतृत्व विभिन्न राज्यों के सांसदों के साथ बैठक करेगा। इसमें रैली की तैयारियों और नेताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर चर्चा होगी।

आम आदमी पार्टी ने भी तेज की चुनावी तैयारी

दूसरी ओर, पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने भी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। पार्टी की ओर से शुक्रवार को दिल्ली में अहम बैठक बुलाई गई है। इसमें पंजाब के नेताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीति पर चर्चा होनी है। ऐसे में पंजाब की राजनीति में चुनावी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए संगठनात्मक स्तर पर सक्रिय हो गई हैं। कांग्रेस जहां हाईकमान के नेतृत्व में चुनावी रणनीति बनाने में जुटी है, वहीं आम आदमी पार्टी भी सत्ता बरकरार रखने के लिए तैयारियों को गति दे रही है।

जाखड़ ने पंजाब में नशा तस्करी की एनआईए जांच की मांग उठाई

लुधियाना में 150 बिसरा नमूने अटके पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना। महानगर में संदिग्ध परिस्थितियों में जान गंवाने वाले लोगों की मौत का कारण पता लगाने के लिए सुरक्षित रखे गए 150 से अधिक बिसरा सैंपल जांच के इंतजार में पड़े हैं। आरोप है कि लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस की ओर से समय पर सैंपल एकत्र नहीं किए जाने के कारण ये सिविल अस्पताल के शवगृह में लंबे समय से रखे हुए हैं। इनमें कई सैंपल एक साल से भी अधिक पुराने बताए जा रहे हैं। इस लापरवाही के चलते संदिग्ध मौतों से जुड़े मामलों की जांच प्रभावित हो रही है और मृतकों के परिजनों को भी रिपोर्ट के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।

नियमानुसार, पोस्टमार्टम के दौरान यदि किसी व्यक्ति की मौत जहरीले पदार्थ, नशीले पदार्थों की अधिक मात्रा या किसी रासायनिक तत्व के सेवन से होने की आशंका होती है तो डॉक्टर शरीर के आंतरिक अंगों के नमूने सुरक्षित रखते हैं। इन्हें बिसरा सैंपल कहा जाता है। संबंधित थाना पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वह इन नमूनों को प्राप्त कर खरड़ स्थित स्टेट केमिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजे। वहां से मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर मौत के संभावित कारणों की पुष्टि करने और जांच को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है।



रिपोर्ट लंबित रहने से जांच पर असर

बिसरा सैंपलों की जांच में देरी से संदिग्ध मौतों के मामलों में मौत का वास्तविक कारण निर्धारित करना मुश्किल हो सकता है। खासकर जहर या नशीले पदार्थों के सेवन से जुड़ी घटनाओं में रासायनिक रिपोर्ट महत्वपूर्ण साक्ष्य होती है। ऐसे में 150 से अधिक सैंपलों का लंबे समय तक जांच के लिए नहीं भेजा जाना गंभीर सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि पुलिस इन लंबित नमूनों को प्रयोगशाला भेजने और संबंधित मामलों की जांच में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाती है।

मामले का खुलासा उस समय हुआ जब एक मृतक के परिजनों ने बिसरा रिपोर्ट मिलने में हो रही देरी को लेकर पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करवाई। परिजन लंबे समय से रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। आयोग ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए लुधियाना पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने सिविल अस्पताल के रिकॉर्ड की जांच की तो पता चला कि 150 से अधिक बिसरा सैंपल अस्पताल में ही पड़े हैं। इनमें कई मामलों के नमूने लंबे समय से प्रयोगशाला नहीं भेजे गए थे। इस जानकारी के सामने आने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। सिविल अस्पताल के एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के अनुसार, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने पर पोस्टमार्टम करने वाली चिकित्सकों की टीम आवश्यक अंगों के नमूने सुरक्षित रखती है।

जालंधर आर्मी स्कूल को बम धमकी राहुल गांधी की रैली भी निशाने पर

धमकी भरे ईमेल से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, रेलवे और स्कूलों की सुरक्षा बढ़ाई गई

भारतेन्दु संवाददाता, जालंधर। जालंधर कैंट स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। स्कूल की आधिकारिक ईमेल आईडी पर सुबह 8:55 बजे धमकी भरा ईमेल भेजा गया। इसमें स्कूल परिसर में आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) के जरिए विस्फोट करने की धमकी दी गई है। ईमेल में पंजाब और खालिस्तान से जुड़े नारे भी लिखे गए हैं। धमकी मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है।

धमकी भरे ईमेल में केवल स्कूल को ही निशाना बनाने की बात नहीं कही गई, बल्कि चार नवंबर को संगरूर में होने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैली का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा पंजाब में रेल सेवाओं को निशाना बनाने की धमकी दी गई है। एक ही ईमेल में स्कूल,



राजनीतिक कार्यक्रम और रेलवे को लेकर धमकी मिलने से सुरक्षा एजेंसियां मामले को गंभीरता से ले रही हैं।

ईमेल में एक से चार नवंबर तक ट्रेनों में सफर नहीं करने की चेतावनी दी गई है। इसमें विशेष रूप से अमृतसर, लुधियाना, फिरोजपुर और बठिंडा की ओर जाने वाली ट्रेनों का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही रेलवे ट्रैक को भी निशाना बनाने की धमकी दी गई है। इस संदेश के सामने आने के बाद रेलवे और सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों के स्तर पर भी सतर्कता बढ़ाए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है।

साइबर टीम ईमेल भेजने वाले की तलाश में जुटी

मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग की साइबर टीमें सक्रिय हो गई हैं। जांच एजेंसियां ईमेल भेजने वाले की पहचान करने के लिए तकनीकी साक्ष्य जुटा रही हैं। इसके तहत ईमेल के आईपी एड्रेस और अन्य डिजिटल जानकारियों को ट्रैक करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि धमकी भेजने वाले व्यक्ति या समूह तक पहुंचा जा सके। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सुरक्षा एजेंसियां ईमेल में किए गए दावों और धमकियों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं। स्कूल, राहुल गांधी की प्रस्तावित रैली और रेलवे से जुड़े स्थलों की सुरक्षा को लेकर भी सतर्कता बरतने पर ध्यान दिया जा रहा है।

लुधियाना में आंबेडकर प्रतिमा का शीशा तीसरी बार तोड़ा, बढ़ा तनाव



भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना के जालंधर बाईपास चौक पर स्थापित भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के बाहर लगे शीशे को अज्ञात व्यक्ति ने पत्थर मारकर तोड़ दिया। इस तरह की यह तीसरी घटना बताई जा रही है। बार-बार प्रतिमा के शीशे को निशाना बनाए जाने से क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया और समाज के लोगों में रोष फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही वाल्मीकि समाज और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के कार्यकर्ता मौके पर एकत्रित होने लगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जालंधर बाईपास चौक और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। इस घटना की जानकारी एडवोकेट नरेंद्र आद्या ने अपने फेसबुक पेज पर लाइव आकर दी। उन्होंने वीडियो के माध्यम से लोगों को प्रतिमा के शीशे को नुकसान पहुंचाए जाने की जानकारी दी।

नैतिक हत्याकांड में काली शूटर का नाम आया सामने, पुलिस करेगी पूछताछ

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-22 में नाबालिग नैतिक की हत्या के मामले में अब गैंगस्टर रविंदर उर्फ काली शूटर का नाम भी सामने आया है। चंडीगढ़ पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। इस मामले में गिरफ्तार शूटर मनमेहर प्रीत सिंह और उसके छोटे भाई अर्शमेहर प्रीत सिंह से पूछताछ के दौरान हथियारों की सप्लाई को लेकर अहम जानकारी मिली है।

दोनों आरोपितों ने पुलिस को बताया कि उन्हें एक पिस्टल गैंगस्टर लक्की पटियाल और दूसरी काली शूटर ने उपलब्ध कराई थी। पुलिस अब काली शूटर से हथियारों की सप्लाई और आरोपितों के साथ उसके संपर्कों को लेकर पूछताछ करना चाहती है।

पुलिस मुठभेड़ में घायल मनमेहर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि अर्शमेहर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस दोनों भाइयों को भी प्रोडक्शन वारंट पर लाकर काली शूटर के सामने बैठाकर पूछताछ करने की तैयारी में है।


गैंगस्टर रविंदर उर्फ काली शूटर।

जांच में सामने आया कि लक्की पटियाल ने दोनों भाइयों को दो विदेशी पिस्टल उपलब्ध कराई थीं। लगातार दो वारदातों में नाकाम रहने और पिस्टल की मैगजीन गिरने के बाद उनका पटियाल से विवाद हो गया। इसके बाद एक पिस्टल उसे वापस कर दी गई।

पीयू में वाहनों की आवाजाही रोकने को छात्रों का प्रदर्शन

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) परिसर में बाहरी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग तेज हो गई है। मंगलवार को छात्रों ने प्रदर्शन कर कैंपस में चार पहिया वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द इस दिशा में कदम नहीं उठाया गया तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे और कुलपति कार्यालय का घेराव करेंगे। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि परिसर में वाहनों की बढ़ती आवाजाही से जाम, प्रदूषण और सुरक्षा संबंधी समस्याएं पैदा हो रही हैं। विशेष रूप से गेड़ी कल्चर के नाम पर कैंपस में घूमने वाली गाड़ियों से छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आरोप है कि कुछ वाहन सवार छात्राओं पर टिप्पणियां करते हैं और उनका पीछा भी करते हैं, जिससे असुरक्षा का माहौल बनता है। छात्रों के अनुसार, प्रमुख प्रवेश द्वारों पर वाहनों की भीड़ के कारण पैदल चलने वालों को भी दिक्कत होती है।

अमेरिका भेजने के अवैध नेटवर्क पर ईडी का शिकंजा

भारतेन्दु संवाददाता, जालंधर। अवैध तरीके से डंकी रूट के जरिए लोगों को अमेरिका भेजने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए ट्रेवल एजेंट तरुण खोसला को अदालत ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दिल्ली से गिरफ्तार किए गए आरोपी का सात दिन का रिमांड पूरा होने के बाद ईडी ने शुक्रवार को उसे जालंधर की अदालत में पेश किया। जिला एवं सेशन जज प्रिया सूद की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एडवोकेट अजय पठानिया पेश हुए। जांच एजेंसी ने आरोपी के रिमांड को आगे बढ़ाने की मांग नहीं की। ईडी की ओर से अदालत को बताया गया कि सात दिन की पूछताछ के दौरान मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं। एजेंसी को जांच के लिए जिन जानकारियों और तथ्यों की आवश्यकता थी, वे शुरुआती रिमांड के दौरान प्राप्त हो चुके हैं। इसके बाद अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। गौरतलब है कि डंकी रूट के जरिए भोले-भाले युवाओं को गैरकानूनी तरीके से विदेश भेजने के नेटवर्क की जांच ईडी कर रही है। एजेंसी इस मामले में अवैध अप्रवासन से जुड़े लोगों और उनकी गतिविधियों की पड़ताल कर रही है। तरुण खोसला की गिरफ्तारी के बाद उससे लगातार पूछताछ की गई। इस दौरान अवैध तरीके से विदेश भेजने और हवाला कारोबार से जुड़े संभावित पहलुओं पर जानकारी जुटाई गई।



- तरुण खोसला से पूछताछ में मिले अहम सुराग, अदालत ने भेजा जेल

आगाज कानून-व्यवस्था, नशे और बेरोजगारी पर सरकार को घेरने की तैयारी, चार नवंबर को जुटेंगे कांग्रेसी नेता

संगरूर में राहुल गांधी की इंसाफ रैली से कांग्रेस करेगी चुनावी शंखनाद

भारतेन्दु संवाददाता, पटियाला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चार नवंबर को पंजाब के संगरूर में प्रस्तावित 'इंसाफ रैली' को लेकर पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रैली के आयोजन और इसके माध्यम से उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर कांग्रेस नेताओं की ओर से बैठकों और जनसंपर्क का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इसी संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता विजयइंदर सिंगला ने कहा कि पूरी पार्टी रैली को सफल बनाने के लिए जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि रैली के माध्यम से पंजाब के मौजूदा हालात, कानून-व्यवस्था, नशे, बेरोजगारी और आर्थिक स्थिति से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। कांग्रेस इस आयोजन को वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की शुरुआत के रूप में भी देख रही है।

विजयइंदर सिंगला ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश की सरकार दिल्ली से संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब का सचिवालय भी 39 नंबर की कोठियों से चलाया जा रहा है। उनके अनुसार, राज्य की संस्कृति, परंपराओं और जमीनी परिस्थितियों की पर्याप्त समझ नहीं रखने वाले लोग पंजाब के प्रशासनिक फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इसके कारण प्रदेश में डर और असुरक्षा का माहौल बन रहा है।


राहुल गांधी और विजय इंद्र सिंगला।

कानून-व्यवस्था और निवेश का मुद्दा उठाया

सिंगला ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था और आर्थिक स्थिति पर सवाल उठते हुए कहा कि राज्य में कारोबारी और उद्योगपति नया निवेश करने से हिचक रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गोलीबारी और आपराधिक घटनाओं की आशंका के कारण व्यापारियों तथा उद्योग संचालकों में असुरक्षा की भावना है। उनका कहना था कि जब कारोबारी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो प्रदेश में नए उद्योग और रोजगार के अवसर पैदा करना मुश्किल होगा। उन्होंने बेरोजगारी को भी गंभीर मुद्दा बताते हुए सरकार से जवाब मांगा। नशे के कारोबार को लेकर भी कांग्रेस नेता ने राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और उनकी आवाज दबाने की कोशिश हो रही है।

केंद्र सरकार की नीतियों पर भी उठाए सवाल

सिंगला ने सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पंजाब में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का अधिकार क्षेत्र 50 किलोमीटर तक बढ़ाया गया है, लेकिन गुजरात सीमा के रास्ते नशीले पदार्थों की कथित तस्करी रोकने की जिम्मेदारी पर भी केंद्र को जवाब देना चाहिए। उन्होंने पंजाब पर बढ़ते कर्ज और वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप भी लगाया। सिंगला ने कहा कि राहुल गांधी चार नवंबर को संगरूर पहुंचकर 'इंसाफ रैली' के माध्यम से पंजाब के मुद्दों को उठाएंगे।

दरबार मूव से जम्मू में बढ़ेगा यातायात दबाव, ट्रैफिक पुलिस ने किए विशेष प्रबंध

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। दो नवंबर से जम्मू में दरबार मूव कार्यालयों का कामकाज शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही शहर में वाहनों की आवाजाही और यातायात का दबाव बढ़ने की संभावना है। मंत्रियों, नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के जम्मू पहुंचने से सरकारी कार्यालयों, प्रमुख मार्गों और बाजारों के आसपास वाहनों की संख्या में इजाफा होगा। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न जिलों से सरकारी कामकाज के सिलसिले में जम्मू आने वाले लोगों की आवाजाही भी बढ़ेगी। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने शहर में यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए विशेष योजना तैयार की है। दरबार मूव के दौरान वीआईपी काफिलों और सरकारी वाहनों की आवाजाही बढ़ने के कारण कुछ प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव अधिक रह सकता है। इससे निपटने के लिए वीआईपी रूटों के साथ शहर के व्यस्त चौराहों, बाजारों और अधिक आवाजाही वाले स्थानों पर अतिरिक्त ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती की जाएगी। वीआईपी मूवमेंट के दौरान यातायात को नियंत्रित करने और आम लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। पुलिस कर्मियों को प्रमुख स्थानों पर तैनात कर वाहनों की आवाजाही पर नजर रखी जाएगी। दरबार मूव के दौरान शहर में नो पार्किंग नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। सड़क किनारे, बाजारों के आसपास और प्रतिबंधित स्थानों पर वाहन खड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस का प्रयास रहेगा कि गलत तरीके से पार्क किए गए वाहनों के कारण सड़कों पर जाम की स्थिति न बने और आपातकालीन वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित न हो। वाहन चालकों से निर्धारित पार्किंग स्थलों का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। दरबार मूव से संबंधित व्यवस्थाओं के तहत 31 अक्टूबर और एक नवंबर को जम्मू से श्रीनगर की ओर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। इस दौरान दरबार मूव से जुड़ी सरकारी फाइलों और अन्य सामान को श्रीनगर से जम्मू लाने के लिए ट्रकों का संचालन किया जाएगा।

वीआईपी मार्गों पर अतिरिक्त जवान तैनात, नो पार्किंग उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

इंद्री पतन पुल से परगवाल के विकास को मिलेगी नई उड़ान

गांवों को मिलेगा बारहमासी संपर्क, आवागमन के साथ कारोबार को भी मिलेगी नई गति

भारतेंदु संवाददाता, परगवाल



चिनाब पर बन रहे 206 करोड़ रुपए के पुल का निरीक्षण करते उपमुख्यमंत्री।

पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा और चिनाब नदी के बीच स्थित सीमावर्ती परगवाल क्षेत्र के करीब 30 हजार लोगों के लिए इंद्री पतन चिनाब पुल महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। लगभग 206 करोड़ रुपये की लागत से बन रही इस परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र की संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी। खासकर बरसात और बाढ़ के दौरान आवागमन में आने वाली परेशानियों से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

पुल निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेने के लिए उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने वीरवार को इंद्री पतन पहुंचकर परियोजना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित निर्माण कंपनी के अधिकारियों से काम की स्थिति और अब तक हुई प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने और परियोजना को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अखनूर विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहन लाल भगत भी मौजूद रहे।

इंद्री पतन चिनाब पुल को परगवाल क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजना माना जा रहा है। वर्तमान में चिनाब नदी के कारण क्षेत्र के कई हिस्सों का संपर्क प्रभावित होता है। बरसात और बाढ़ के समय लोगों को आवागमन में विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पुल बनने से क्षेत्र को वर्षभर बेहतर संपर्क सुविधा मिलने की उम्मीद है। इससे स्थानीय लोगों की दूसरे क्षेत्रों तक पहुंच आसान होगी।

पुल के निर्माण से विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थानों तक पहुंचने में आसानी होगी। वहीं, मरीजों को अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचने के लिए बेहतर रास्ता मिलेगा। किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में सुविधा होगी। व्यापारियों और रोजमर्रा के काम से दूसरे क्षेत्रों में जाने वाले लोगों का समय भी बचेगा। इसके अलावा बेहतर संपर्क सुविधा से स्थानीय व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

निरीक्षण के दौरान उपमुख्यमंत्री ने निर्माण एजेंसी को गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए काम में तेजी लाने को कहा।

जम्मू में बदलते मौसम से वायरल डेंगू और निमोनिया का बढ़ा प्रकोप



अस्पतालों की ओपीडी में बढ़ी मरीजों की भीड़, चिकित्सकों ने सावधानी बरतने की दी सलाह

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। बदलते मौसम और कई इलाकों में मच्छरों के पनपने से जम्मू संभाग में मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। जम्मू शहर के साथ डोडा, सांबा और अन्य क्षेत्रों में भी बुखार, जुकाम, डेंगू और निमोनिया के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। स्थिति यह है कि कई घरों में लोग बुखार और वायरल संक्रमण से पीड़ित हैं। अस्पतालों की ओपीडी में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जम्मू संभाग के सबसे बड़े राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मेडिसिन विभाग की ओपीडी में आने वाले करीब 40 प्रतिशत मरीज बुखार, डेंगू और मौसम से जुड़ी अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं। वहीं, श्री महाराजा गुलाब सिंह (एसएमजीएस) अस्पताल की ओपीडी में रोजाना लगभग 50 से 70 मरीज पहुंच रहे हैं। इनमें 60 प्रतिशत से अधिक बच्चे तेज बुखार की शिकायत लेकर आ रहे हैं। अस्पताल में पिछले कुछ दिनों के दौरान बच्चों में डेंगू के मामलों में कमी आई है, लेकिन वायरल फीवर, निमोनिया और टाइफाइड के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। जम्मू के गांधीनगर और सरवाल अस्पतालों में भी मौसमी बीमारियों के मरीज पहुंच रहे हैं। इस बार डोडा जिले में भी डेंगू के कई मामले सामने आए हैं। जीएमसी जम्मू के मेडिसिन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. जेबी सिंह के अनुसार, मौसम में बदलाव के दौरान वायरल फीवर के मामले सामने आना सामान्य है, लेकिन इस बार निमोनिया और डेंगू के मरीज भी बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं। विशेष रूप से डोडा जिले से कई मरीज जीएमसी जम्मू में उपचार के लिए आए हैं। डॉ. जेबी सिंह ने बताया कि वायरल संक्रमण से बचने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना जरूरी है। बाहर से आने और भोजन करने से पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए। खांसी और बुखार से पीड़ित लोगों से उचित दूरी बनाए रखें। खांसते और छींकते समय मुंह तथा नाक को रूमाल या टिश्यू से ढकें।

लद्दाख में शराब नीति विरोधी आंदोलन स्थगित, मांगों पर बनी सहमति

भारतेंदु संवाददाता, लेह



लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की नई शराब नीति के खिलाफ महिला संगठनों की ओर से चलाया जा रहा विरोध प्रदर्शन अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने बताया कि प्रशासन ने महिला संगठनों की सभी मांगों को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है। समझौते को औपचारिक रूप देने के लिए प्रशासन ने एक सप्ताह का समय मांगा है।

लद्दाख में पिछले सप्ताह चार महिला संगठनों के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग थी कि हाल ही में लागू शराब नीति को पूरी तरह वापस लिया जाए और लद्दाख को शराब मुक्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाए। संगठनों ने नई नीति के तहत बार लाइसेंस और शराब की दुकानों की अनुमति दिए जाने पर आपत्ति जताई थी।

वांगचुक ने गुरुवार को इंटरनेट मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि महिला नेताओं ने प्रशासन के आश्वासन के बाद अपना विरोध प्रदर्शन रोक दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रशासन महिला संगठनों के भरोसे और विश्वास का सम्मान करते हुए अपने वादे को पूरा करेगा। यह धरना 29 अक्टूबर से पांच नवंबर तक प्रस्तावित था, लेकिन लिखित आश्वासन मिलने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया।

प्रशासन की ओर से 29 अक्टूबर को गृह विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी किया था। विशेष सचिव ताशी डोलमा के हस्ताक्षर वाले पत्र में महिला संगठनों की ओर से रखी गई मांगों और सुझावों को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने की बात कही गई है।

लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन महिला विंग, अंजुमन-ए-इमामिया महिला विंग, अंजुमन मोइन-उल-इस्लाम महिला विंग और ईसाई समुदाय महिला विंग इस आंदोलन में शामिल थे। संगठनों ने कहा कि प्रशासन को सहमत बिंदुओं को लिखित रूप में अंतिम रूप देने का अवसर देने के लिए धरना अस्थायी तौर पर रोका गया है।

जम्मू-कश्मीर में पर्यटन पर लगेगी नियंत्रित पाबंदी

अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या होगी तय, निर्माण पर भी लगेगी रोक

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर



जम्मू-कश्मीर के संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रों को प्राकृतिक आपदाओं और बढ़ते पर्यटन दबाव से बचाने के लिए नई सतत पर्वतीय विकास नीति तैयार की गई है। इसमें प्रमुख पर्यटन स्थलों और धार्मिक यात्रा मार्गों पर प्रतिदिन पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करने, अनियंत्रित निर्माण पर रोक लगाने और हिमनदों के संरक्षण के लिए विशेष उपाय करने का प्रस्ताव है। नीति का उद्देश्य हिमालयी क्षेत्रों के पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखते हुए पर्यटन गतिविधियों को व्यवस्थित करना है।

यह नीति शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कश्मीर और नई दिल्ली स्थित इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव (आइएमआइ) ने तैयार की है। इसके मसौदे में विश्वविद्यालय के कुलपति सहित कम से कम आठ प्राध्यापकों का योगदान रहा है। इसकी समीक्षा शिमला स्थित भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, गुजरात के अटल बिहारी वाजपेयी नीति अनुसंधान एवं अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान, उत्तराखंड के जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान और ब्रिटेन की संस्था सिस्टमइक ने की है।

गुलमर्ग, पहलगाम समेत प्रमुख स्थलों की पर्यावरणीय क्षमता का होगा वैज्ञानिक आकलन

विश्वविद्यालय के अधिकारियों के अनुसार, नीति के मसौदे को आम जनता की राय और सुझावों के लिए सार्वजनिक किया जा रहा है। इसमें जम्मू-कश्मीर को प्रायोगिक मॉडल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है, ताकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, सिक्किम और पूर्वोत्तर के अन्य हिमालयी राज्य भी इससे सीख लेकर ऐसी नीतियां अपना सकें। प्रस्तावित नीति को तीन चरणों में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले 100 दिनों में शुरुआती कदम उठाए जाएंगे। एक वर्ष के भीतर कानूनी और संस्थागत ढांचा तैयार करने तथा पांच वर्षों में मापने योग्य बदलाव लाने का लक्ष्य है। नीति के अनुसार, नदी-नालों के तल, जल निकासी मार्गों, हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों और भूस्खलन के अत्यधिक जोखिम वाले लाल संकेतित क्षेत्रों में शिविर, लंगर, तंबू और दुकानें लगाने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है।

जम्मू-कश्मीर में अग्निशमन ढांचे की होगी पड़ताल, हाईकोर्ट ने तलब किया पूरा हिसाब

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू



फायर स्टेशनों की उपलब्धता और जरूरत का तुलनात्मक विवरण मांगा 17 नवंबर को सुनवाई

जम्मू-कश्मीर में आगजनी की घटनाओं से निपटने की तैयारियों और अग्निशमन ढांचे की स्थिति को लेकर हाईकोर्ट ने प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने प्रदेश में मौजूदा फायर स्टेशनों की संख्या, निर्धारित मानकों के अनुसार आवश्यक स्टेशनों और विभिन्न क्षेत्रों में आग लगने के जोखिम के आधार पर उपलब्ध सुविधाओं का पूरा ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही प्रशासन को मौजूदा व्यवस्था और निर्धारित जरूरतों के बीच अंतर स्पष्ट करना होगा।

चीफ जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस यशपाल बौरनी की खंडपीठ ने यह निर्देश अग्निशमन नीति को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किए जाने के आरोपों से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए। याचिका एडवोकेट मोहम्मद राहूफ खान ने दायर की है और वह स्वयं भी मामले में पेश हुए। सुनवाई के दौरान प्रशासन की ओर से वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता मोनिका कोहली ने गृह मंत्रालय के अधीन स्थायी अग्निशमन सलाहकार परिषद की ओर से निर्धारित दिशा-निर्देशों का हवाला दिया।

अदालत को बताया गया कि फायर स्टेशन स्थापित करने के लिए केवल आबादी को आधार नहीं बनाया जाता, बल्कि क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों, आग लगने की आशंका, आबादी के घनत्व और घटनास्थल तक अग्निशमन वाहन के पहुंचने में लगने वाले समय को भी ध्यान में रखा जाता है। इन मानकों के तहत क्षेत्रों को उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम, कम जोखिम तथा ग्रामीण या अपेक्षाकृत कम जोखिम वाली श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में अग्निशमन सेवाओं को तीन मिनट के भीतर पहुंचना चाहिए। शहरी क्षेत्रों के मध्यम और कम जोखिम वाले इलाकों के लिए यह समय पांच मिनट निर्धारित है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 20 मिनट के भीतर अग्निशमन सेवा उपलब्ध कराने का मानक बताया गया है।

नौशेरा में सुरक्षा चौकी को टक्कर मारकर भागा चालक, गिरफ्तार

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू-राजौरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर नियमित जांच के दौरान सुरक्षा चौकी को कार से टक्कर मारकर भागने की कोशिश करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। घटना नौशेरा के लांबेरी इलाके में हुई, जहां चालक ने जांच के लिए रोके जाने पर वाहन भगाने का प्रयास किया और इस दौरान बैरिकेड्स को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने कार को जब्त कर उसके मालिक मोहम्मद असलम को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों के अनुसार, यह घटना 27 और 28 अक्टूबर की दरमियानी रात की है। जम्मू-राजौरी राजमार्ग पर लांबेरी क्षेत्र में सुरक्षा जांच के लिए चौकी स्थापित की गई थी। इसी दौरान एक कार को जांच के लिए रुकने का संकेत दिया गया। आरोप है कि चालक ने वाहन रोकने के बजाय वहां से भागने की कोशिश की और कार से बैरिकेड्स को टक्कर मार दी। इससे सुरक्षा चौकी को नुकसान पहुंचा। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और वाहन की पहचान करने के लिए विशेष टीम गठित की। टीम को कार का पता लगाने और घटना में शामिल लोगों की पहचान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। पुलिस ने जांच के दौरान संबंधित वाहन का पता लगा लिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। वाहन को जब्त करने के बाद उसके मालिक मोहम्मद असलम को गिरफ्तार कर लिया गया।

कश्मीर की मिट्टी में मिला सेब के दुश्मन कीटों का प्राकृतिक विनाशक



प्रयोगशाला में आर-1 सूक्ष्म कृमि ने दिखाई सर्वाधिक प्रभावशीलता, बागवानों को मिलेगी राहत

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। सेब के पेड़ों को खोखला कर उनकी पैदावार और गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाने वाले तना छेदक कीट से निपटने का प्राकृतिक उपाय कश्मीर की मिट्टी में ही मिला है। कश्मीर के विज्ञानियों के एक शोध में मिट्टी में पाए जाने वाले पांच स्थानीय सूक्ष्म कृमियों की पहचान की गई है, जो सेब के तना छेदक कीट एओलोस्थीज सार्टा के लार्वा को मारने में सक्षम हैं। प्रयोगशाला में किए गए परीक्षणों के उत्साहजनक परिणामों से उम्मीद जगी है कि भविष्य में सेब उत्पादकों की महंगे रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम हो सकती है। यह कीट जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सेब बागानों में गंभीर नुकसान पहुंचाता है। इसके लार्वा पेड़ों के तनों और शाखाओं में छेद कर अंदर तक पहुंच जाते हैं और उन्हें खोखला कर देते हैं। इससे पेड़ कमजोर होने लगते हैं और उनकी शाखाएं टूटने का खतरा बढ़ जाता है। अधिक संक्रमण होने पर पेड़ सूख भी सकते हैं। इसका सीधा असर फलों की पैदावार और गुणवत्ता पर पड़ता है। कीट से बचाव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रासायनिक कीटनाशक बागवानों का खर्च बढ़ाते हैं। इनके अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर भी चिंता बनी रहती है। ऐसे में स्थानीय मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों के माध्यम से कीट नियंत्रण की संभावना महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह शोध इजिप्शियन जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल में प्रकाशित हुआ है। नुसरत फातिमा के नेतृत्व में नौ शोधकर्ताओं की टीम ने कुपवाड़ा, बांडीपोरा और बारामुला जिलों के सेब बागानों से मिट्टी के 450 नमूने एकत्र किए। इन नमूनों की जांच के दौरान पांच में ऐसे सूक्ष्म कृमियों की पहचान हुई, जिनमें कीट के लार्वा को नष्ट करने की क्षमता पाई गई। शोधकर्ताओं ने प्रयोगशाला में इन पांचों किस्मों की प्रभावशीलता का परीक्षण किया। परीक्षण में आर-1 किस्म सबसे प्रभावी साबित हुई। प्रयोग के दौरान प्रति लार्वा एक हजार सूक्ष्म कृमियों के इस्तेमाल से शुरुआती अवस्था के 50 प्रतिशत लार्वा को मारने में लगभग 66 घंटे लगे। वहीं, इनकी संख्या बढ़ाकर चार हजार करने पर इतना ही प्रभाव करीब 26 घंटे में देखने को मिला। हालांकि, बड़े लार्वा पर इनका असर अपेक्षाकृत धीमा रहा। ये सूक्ष्म कृमि कीट के शरीर में प्रवेश करते हैं और अपने साथ मौजूद लाभकारी बैक्टीरिया की मदद से उसे नष्ट कर देते हैं। इस प्राकृतिक प्रक्रिया का इस्तेमाल भविष्य में जैविक कीट नियंत्रण के विकल्प के रूप में किया जा सकता है।

शोपियां में आतंकी फंडिंग नेटवर्क का पर्दाफाश, दस गिरफ्तार

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर



तबादलों में पारदर्शिता पर जोर, उपराज्यपाल के पास रहेगा अंतिम निर्णय

जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में पुलिस ने आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने और उसे आगे पहुंचाने के आरोप में सक्रिय एक वित्तीय नेटवर्क का पता लगाया है। पुलिस ने मामले में अब तक दस लोगों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और उससे जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) की गतिविधियों के लिए कथित तौर पर धन जुटा रहे थे। पुलिस के अनुसार, इस नेटवर्क के तार अलग-अलग जेलों में बंद आतंकियों और उनके सहयोगियों से भी जुड़े हो सकते हैं।

शोपियां पुलिस ने संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों की जांच और विभिन्न डिजिटल भुगतान माध्यमों से हुए लेनदेन का विश्लेषण करने के बाद इस मॉड्यूल का खुलासा किया। इस संबंध में शोपियां पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी संख्या 231/2026 दर्ज की गई है। आरोपियों के खिलाफ कानून की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस की प्रारंभिक जांच के मुताबिक, संदिग्धों ने विभिन्न भुगतान प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन किए। इन लेनदेन की पड़ताल में धन के हस्तांतरण से जुड़ी कई कड़ियों का पता चला। जांच एजेंसियों को संदेह है कि आरोपियों का एक संगठित नेटवर्क था, जो अलग-अलग माध्यमों से धन एकत्र कर उसे आतंकी गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराता था।

पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क में शामिल लोगों के संपर्क जेलों में बंद आतंकियों और उनके सहयोगियों से होने की आशंका है। जांच के दौरान सामने आए वित्तीय लेनदेन और आपसी संपर्कों के आधार पर आरोपियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है।

जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी कथित तौर पर आम लोगों से गुप्त तरीके से धन एकत्र करते थे। इसके बाद स्थापित वित्तीय माध्यमों के जरिए इस रकम को लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ की गतिविधियों के लिए भेजने का प्रयास किया जाता था। पुलिस को आशंका है कि इस धन का इस्तेमाल आतंकी नेटवर्क को आर्थिक मदद देने के साथ-साथ उनके लिए जरूरी संसाधन और अन्य सुविधाएं जुटाने में किया जा रहा था।

अखनूर में ट्यूबवेल की छत पर उगे पेड़, विभाग बेखबर



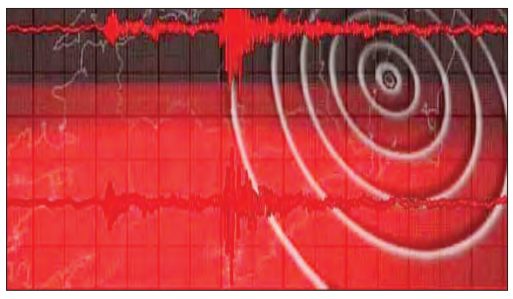
जर्जर ढांचे पर मंडराया खतरा स्थानीय लोगों ने विभाग से तत्काल मरम्मत की उठाई मांग

भारतेंदु संवाददाता, अखनूर। जम्मू जिले के अखनूर स्थित चंदिया इलाके में ट्यूबवेल की इमारत की छत पर घास, झाड़ियां और छोटे पेड़ उगने का मामला सामने आया है। छत पर उगे पेड़ों की जड़ें धीरे-धीरे फैल रही हैं, जिससे भवन के ढांचे को नुकसान पहुंचने की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय लोगों ने इस स्थिति को लेकर संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और जल्द सफाई व मरम्मत करवाने की मांग की है।

ट्यूबवेल की इमारत क्षेत्र के लोगों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में इसकी नियमित देखरेख और रखरखाव जरूरी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि छत पर लंबे समय से उगी घास और झाड़ियों की सफाई नहीं की गई। अब वहां छोटे पेड़ भी उग आए हैं। इनकी जड़ें छत के भीतर फैलने से सीलन और दरारें पड़ने का खतरा बना हुआ है। यदि समय रहते इनकी सफाई नहीं करवाई गई तो इमारत को अधिक नुकसान हो सकता है। स्थानीय निवासी सूबेदार मिलखी राम ने बताया कि चंदिया अखनूर इलाके में ट्यूबवेल की बिल्डिंग की छत पर घास और पेड़ उग आए हैं। पेड़ों की जड़ें छत में फैल रही हैं, जिससे भवन की मजबूती प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग को इस समस्या का तुरंत संज्ञान लेना चाहिए।

स्थानीय लोगों ने मांग की है कि विभागीय अधिकारी मौके का निरीक्षण करें और छत से घास, झाड़ियों तथा पेड़ों को हटाने के लिए उचित कदम उठाएं। साथ ही भवन की स्थिति की जांच कर आवश्यक मरम्मत करवाई जाए।

कुलगाम में भूकंप के झटकों से मची दहशत, घरों से बाहर निकले लोग



3.6 तीव्रता के झटके महसूस हुए, जानमाल का नुकसान नहीं

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में शुक्रवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.6 मापी गई। अचानक धरती हिलने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई और कई लोग एहतियातन अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि, भूकंप की तीव्रता कम होने के कारण किसी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। प्रशासन के अनुसार, जिले और आसपास के क्षेत्रों में स्थिति सामान्य बनी हुई है।

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, भूकंप शुक्रवार तड़के एक बजकर 46 मिनट पर आया। इसका केंद्र कुलगाम जिले में जमीन के भीतर लगभग 10 किलोमीटर की गहराई पर दर्ज किया गया। भूकंप का केंद्र 33.628 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 74.922 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था।

रात के समय अचानक धरती हिलने से लोग घबरा गए। कई लोगों ने घरों से बाहर निकलकर खुले स्थानों पर शरण ली। कुलगाम और आसपास के इलाकों में कुछ देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। हालांकि, झटके हल्के होने के कारण किसी बड़ी घटना की जानकारी सामने नहीं आई।

प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार, भूकंप के बाद स्थिति पर नजर रखी गई। अब तक किसी भी क्षेत्र से मकानों, सार्वजनिक संपत्ति या अन्य ढांचों को नुकसान पहुंचने की सूचना नहीं मिली है। किसी के घायल होने या जान गंवाने की भी खबर नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक, फिलहाल स्थिति पूरी तरह सामान्य है।

जल उपयोग शुल्क रद्द होने से जम्मू-कश्मीर को हजार करोड़ की चपत की आशंका

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के नेता और पुलवामा के विधायक वहीदउर रहमान पारा ने जम्मू-कश्मीर को जलविद्युत परियोजनाओं पर जल उपयोग शुल्क से जुड़े मामले में करीब 1,000 करोड़ रुपये के संभावित राजस्व नुकसान की आशंका जताई है। उन्होंने इस मामले में प्रशासन की कानूनी तैयारियों और पैरवी पर सवाल उठाते हुए कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले से प्रदेश के वित्तीय हितों को नुकसान पहुंच सकता है। दरअसल, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर जल संसाधन (नियमन एवं प्रबंधन) अधिनियम, 2010 के उन प्रावधानों को रद्द कर दिया है, जिनके तहत जलविद्युत परियोजनाओं पर जल उपयोग शुल्क लगाया जाता था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह का शुल्क बिजली उत्पादन पर कर लगाने के समान है और यह तत्कालीन जम्मू-कश्मीर विधानमंडल की विधायी क्षमता के दायरे से बाहर था। न्यायालय ने संबंधित प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करते हुए इनके आधार पर जारी वर्ष 2010 के मांग नोटिस भी रद्द कर दिए। अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पारा ने कहा कि वर्ष 2010 के मांग नोटिस रद्द होने से इस मामले में प्रशासन की ओर से की गई कानूनी पैरवी पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने करीब दो वर्षों से एडवोकेट जनरल की अनुपस्थिति का मुद्दा भी उठाया। पारा ने कहा कि विधि विभाग मुख्यमंत्री के अधीन है, ऐसे में जम्मू-कश्मीर के वित्तीय और कानूनी हितों की रक्षा के लिए प्रशासन को प्रभावी तैयारी करनी चाहिए थी। पारा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया में सवाल किया कि यदि प्रशासन इस तरह प्रदेश के हितों की रक्षा करता है तो राज्य का दर्जा बहाल होने के मामले में उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? उन्होंने फैसले के बाद प्रदेश को होने वाले संभावित आर्थिक नुकसान और प्रशासन की जवाबदेही को लेकर चिंता जताई। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद जल उपयोग शुल्क की वसूली से जुड़े प्रावधानों पर रोक लग गई है। इससे जम्मू-कश्मीर के राजस्व पर पड़ने वाले असर को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

युवा आक्रोश में छिपे संदेश को समझे सत्ता



एआई निर्मित चित्र।

देश में युवाओं के आंदोलनों ने एक बार फिर लोकतंत्र, जनभागीदारी और सरकार की जवाबदेही से जुड़े सवालों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अलग-अलग तारीखों पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों और लगातार उठती आवाजों से स्पष्ट है कि युवाओं के बीच कई मुद्दों को लेकर असंतोष है। सरकार, पुलिस और प्रदर्शनकारी युवाओं के बीच टकराव की स्थिति बन रही है। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन यह भी जरूरी है कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहें और आम लोगों के जीवन तथा कारोबार को अनावश्यक नुकसान न पहुंचे। लगातार प्रदर्शनों का असर दिल्ली के सदर बाजार, कनॉट प्लेस, जनपथ और नई दिल्ली के अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहा है। त्योहारी सीजन में कारोबारियों की चिंता स्वाभाविक है। ऐसे में आंदोलनकारियों को अपनी मांगों और आम जनता की परेशानियों के बीच संतुलन बनाना होगा।

दूसरी ओर विपक्ष भी इन आंदोलनों के माध्यम से सरकार को घेरने का अवसर तलाश रहा है। कई बार मूल मुद्दों की जगह राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप हावी हो जाते हैं। इससे जनता के सामने यह समझना कठिन हो जाता है कि किस पक्ष की बात तथ्यों पर आधारित है और कौन राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। लोकतंत्र में सरकार की आलोचना और विपक्ष की भूमिका दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनका उद्देश्य जनता से जुड़े सवालों का समाधान होना चाहिए। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, उसकी निष्पक्षता और आयुक्तों के बीच असहमति जैसे विषयों पर भी पारदर्शी तरीके से जानकारी सामने आनी चाहिए। संस्थाओं की विश्वसनीयता लोकतंत्र की मजबूती का आधार है।

इन आंदोलनों के बीच कुछ ऐसे मुद्दे भी सामने आए हैं, जिन्हें किसी भी राजनीतिक दृष्टिकोण से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्कूलों की बदहाल स्थिति, अस्पतालों में सुविधाओं की कमी और राशन वितरण व्यवस्था में अनियमितताएं सीधे आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित करती हैं। स्कूल सुधार अभियान के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था की कमियां सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। कई सरकारी स्कूलों में भवन, शौचालय, पेयजल, शिक्षकों और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे सवाल उठे हैं। इन मुद्दों पर चर्चा के बाद सरकारों की ओर से बजट स्वीकृत किया जाना इस बात का संकेत है कि जनदबाव से प्रशासन का ध्यान जरूरी समस्याओं की ओर आकर्षित किया जा सकता है। यदि किसी आंदोलन के कारण बच्चों को बेहतर शिक्षा, मरीजों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं और गरीबों को उचित राशन मिलने का रास्ता बनता है तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की सकारात्मक उपलब्धि है।



डा दमन आहूजा

इसी तरह धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था से जुड़े विषयों के साथ भ्रष्टाचार तथा चुनावी निष्पक्षता के सवालों पर भी निष्पक्ष जांच की मांग करना नागरिकों का अधिकार है। किसी भी संस्था या व्यक्ति को जांच से ऊपर नहीं माना जा सकता। हालांकि, आरोपों को प्रमाणित तथ्यों से अलग रखना भी जरूरी है। आंदोलन का उद्देश्य केवल विरोध करना नहीं, बल्कि व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस परिणाम हासिल करना होना चाहिए। सोनम वांगचुक जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयासों और उनके उठाए सवालों को भी इसी संतुलित दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। किसी व्यक्ति या आंदोलन का मूल्यांकन केवल राजनीतिक समर्थन अथवा विरोध के आधार पर नहीं होना चाहिए।

एआई निर्मित चित्र।

देश में विकास के मोर्चे पर हुई उपलब्धियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सड़क और एक्सप्रेसवे नेटवर्क का विस्तार, सस्ते इंटरनेट की उपलब्धता, रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण, हवाई संपर्क में सुधार और सामरिक बुनियादी ढांचे का विकास महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं। पूर्वोत्तर में पुलों और रेल संपर्क का विस्तार तथा ब्रह्मपुत्र पर बने बड़े पुल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उदाहरण हैं। इसी तरह यूपीआई ने डिजिटल भुगतान को आम लोगों तक पहुंचाया है। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने, चिनाब रेल पुल और वंदे भारत जैसी परियोजनाओं ने भी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा पैदा की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की सुरक्षा और सामरिक तैयारियों पर भी व्यापक विमर्श हुआ। इन उपलब्धियों के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा और रोजगार जैसी चुनौतियों पर भी गंभीरता से ध्यान देना आवश्यक है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

यदि पुलिस सतर्क हो, तो कोई बच्चों के हाथ से खिलौना नहीं छीन सकता

बच्चों का बचपन सुरक्षित रखना पूरे समाज की जिम्मेदारी है। बच्चे किसी भी राष्ट्र और समाज का भविष्य होते हैं। उनके चेहरों की मुस्कान, हाथों में खिलौने और आंखों में पलते सपने एक सुरक्षित और खुशहाल समाज की पहचान हैं। बचपन जीवन का सबसे अनमोल समय होता है, जिसमें बच्चे खेलते-कूदते, पढ़ते और नई चीजें सीखते हुए अपने भविष्य की नींव तैयार करते हैं। लेकिन जब अपराधियों की नजर उनकी मासूमियत पर पड़ती है, तो उनका बचपन खतरे में पड़ जाता है। ऐसे में पुलिस की सतर्कता और समय पर की गई कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। पुलिस की मुस्तैदी से न केवल अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है, बल्कि बच्चों के जीवन और भविष्य को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। यहां खिलौने का अर्थ केवल खेलने की वस्तु नहीं, बल्कि बच्चों का बचपन, उनकी खुशियां, अधिकार, विश्वास और सुरक्षित भविष्य है।

आज बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध समाज के सामने गंभीर चुनौती बनकर खड़े हैं। अपहरण, बाल मजदूरी, शोषण और मानव तस्करी जैसी घटनाएं बच्चों के जीवन को प्रभावित करती हैं। कई बार अपराधी उनकी मासूमियत और भरोसे का फायदा उठाकर उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं। वहीं, जागरूकता की कमी, लापरवाही और समय पर सूचना नहीं मिलने के कारण भी अपराधियों को अपने मंसूबों में सफल होने का अवसर मिल जाता है। ऐसी परिस्थितियों में पुलिस की जिम्मेदारी केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपराध को रोकने के लिए पहले से प्रभावी कदम उठाना भी जरूरी है।



एआई निर्मित चित्र।

पुलिस यदि अपने क्षेत्रों में नियमित गश्त करे, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखे और स्कूलों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों तथा अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर निगरानी बढ़ाए, तो बच्चों के खिलाफ होने वाले कई अपराधों को रोका जा सकता है। लापता बच्चों की शिकायतों को भी प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। शुरुआती समय में की गई खोजबीन और उचित कदम किसी बच्चे को बड़े खतरे से बचा सकते हैं। इसके साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।



विजय शर्मा

हालांकि, बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल पुलिस प्रशासन की नहीं है। माता-पिता, शिक्षक, स्थानीय प्रशासन और आम नागरिकों को भी इसमें सक्रिय भूमिका निभानी होगी। अभिभावकों को बच्चों को अनजान लोगों से सावधान रहने, किसी परेशानी में भरोसेमंद व्यक्ति को जानकारी देने और बिना बताए किसी के साथ कहीं न जाने जैसी जरूरी बातें समझानी चाहिए। बच्चों को यह भी बताया जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति के गलत व्यवहार या असहज स्थिति का सामना करने पर वे बिना डर के अपने माता-पिता अथवा शिक्षक को इसकी जानकारी दें। स्कूलों में बच्चों को उनके अधिकारों और सुरक्षा से संबंधित जानकारी देना भी जरूरी है।

इस दिशा में पुलिस और मीडिया की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। पुलिस द्वारा समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाकर बच्चों और अभिभावकों को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। वहीं, मीडिया को बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के प्रति समाज को संवेदनशील बनाने और सुरक्षा संबंधी जानकारी पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। पुलिस और मीडिया के बीच बेहतर समन्वय से लोगों तक समय पर जरूरी सूचनाएं पहुंचाई जा सकती हैं। स्थानीय स्तर पर पुलिस और समुदाय के बीच विश्वास का मजबूत रिश्ता भी अपराधों की रोकथाम में मददगार साबित हो सकता है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

पुश्तैनी जमीन बेचकर कौन सी अमीरी दिखा रहे हैं वारिस?

विरासत बेचकर बने कंगाल, लालची लाल



एआई निर्मित चित्र।



नरेंद्र भारती

यदि किसी व्यक्ति को बीमारी के इलाज, बच्चों की पढ़ाई, कर्ज चुकाने या बहन-बेटी की शादी जैसी कोई बड़ी मजबूरी हो, तो पुश्तैनी जमीन बेचने के फैसले को कुछ हद तक समझा जा सकता है। लेकिन जब कोई मजबूरी न हो, अच्छी नौकरी हो, नियमित वेतन मिलता हो और फिर भी केवल अधिक पैसा कमाने तथा दिखावे की जिंदगी जीने के लालच में बाप-दादाओं की अनमोल जमीन बेच दी जाए, तो यह बेहद चिंताजनक स्थिति है। जिस जमीन को बुजुर्गों ने अपने खून-पसीने से सींचा, भूखे रहकर और कठिनाइयाँ सहकर संभालकर रखा, उसे अगली पीढ़ी ने चंद रुपयों के लालच में एक हस्ताक्षर करके बेच दिया। यह केवल जमीन का सौदा नहीं, बल्कि अपनी विरासत और पूर्वजों की मेहनत के प्रति जिम्मेदारी को भूलने जैसा है।

आज पुश्तैनी जमीन बेचकर मिले पैसे से कुछ लोग बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, महंगे मोबाइल और कपड़े पहन रहे हैं, चारधाम यात्राएँ कर रहे हैं और महंगे होटलों में घूमने-फिरने पर पैसा खर्च कर रहे हैं। समाज में अपना रुतबा दिखाने की होड़ लगी है। लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि वास्तविक अमीरी गाड़ी, महंगे कपड़ों और दिखावे से नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने से आती है। बड़े आदमी वे बुजुर्ग थे, जिन्होंने सीमित साधनों में रहकर जमीन जोड़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिए संपत्ति बनाई। आज उसी संपत्ति को बेचकर शान दिखाना कोई उपलब्धि नहीं है।

सबसे बड़ी बात यह है कि जमीन केवल संपत्ति का टुकड़ा नहीं होती, बल्कि परिवार की पहचान, सम्मान और भविष्य का आधार होती है। खेतों से अनाज मिलता है, बगीचों से फल मिलते हैं और जमीन आने वाली पीढ़ियों को आर्थिक सुरक्षा देती है। इसके विपरीत, जमीन बेचकर मिला पैसा धीरे-धीरे खर्च हो जाता है। आज गाड़ी खरीदी है तो कल उसके रखरखाव और पेट्रोल का खर्च उठाना पड़ेगा। आज महंगे होटलों में भोजन कर रहे हैं, लेकिन कल आमदनी का साधन समाप्त होने पर वही जीवन बोझ लगने लगेगा। पैसा खर्च करना आसान है, लेकिन उसे दोबारा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है।

पुश्तैनी संपत्ति बेचने से पहले यह भी सोचना चाहिए कि बुजुर्गों ने कितने संघर्षों के बाद उसे बचाकर रखा होगा। उन्होंने अपनी इच्छाओं को दबाया, कठिन परिस्थितियों का सामना किया और परिवार के भविष्य के लिए जमीन को सुरक्षित रखा। क्या उनकी मेहनत का यही सम्मान होना चाहिए? यदि जमीन का उपयोग नहीं हो रहा था, तो उसे बेचने के बजाय लीज पर दिया जा सकता था, उस पर मकान बनाकर किराये की आमदनी प्राप्त की जा सकती थी या किसी अन्य रोजगार के लिए उसका उपयोग किया जा सकता था।

लालच में लिया गया फैसला कई बार पूरे परिवार के भविष्य को प्रभावित करता है। आज जो पैसा हाथ में है, वह कुछ वर्षों में समाप्त हो सकता है, लेकिन एक बार बिकी हुई जमीन आसानी से वापस नहीं मिलती। इसके साथ परिवार की जड़ें, सामाजिक पहचान और आने वाली पीढ़ियों का एक बड़ा सहारा भी छिन जाता है। बच्चों को भी यह समझाना जरूरी है कि विरासत केवल बेचकर खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि संभालकर आगे बढ़ाने के लिए होती है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

शिक्षा के मंदिरों में मूल्य आधारित शिक्षा की बहुत आवश्यकता



एआई निर्मित चित्र।

शिक्षा को मानव जीवन का आधार माना गया है। विद्यालय और महाविद्यालय केवल पढ़ाई करने के स्थान नहीं होते, बल्कि इन्हें 'शिक्षा के मंदिर' कहा जाता है, क्योंकि यहीं से व्यक्ति के व्यक्तित्व, सोच और संस्कारों का निर्माण होता है।

आज के आधुनिक और प्रतिस्पर्धात्मक युग में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अक्सर केवल अंक प्राप्त करना, नौकरी पाना और आर्थिक सफलता तक सीमित होता जा रहा है। ऐसे समय में शिक्षा के मंदिरों में मूल्य आधारित शिक्षा की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है।

मूल्य आधारित शिक्षा का अर्थ ऐसी शिक्षा से है, जो विद्यार्थियों को केवल पुस्तकीय ज्ञान ही न दे, बल्कि उनमें नैतिकता, अनुशासन, ईमानदारी, दया, सहिष्णुता, जिम्मेदारी, सहयोग और मानवता जैसे गुणों का भी विकास करे। यह शिक्षा विद्यार्थियों को एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में प्रेरित करती है। यदि शिक्षा केवल ज्ञान देने तक सीमित रह जाए और उसमें नैतिक मूल्यों का समावेश न हो, तो समाज में शिक्षित व्यक्ति तो होंगे, लेकिन चरित्रवान नागरिकों की कमी महसूस होगी।

आज समाज में बढ़ती हिंसा, भ्रष्टाचार, असहिष्णुता, नशे की प्रवृत्ति, अनुशासन हीनता और सामाजिक विघटन जैसे कई संकट देखने को मिल रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण नैतिक मूल्यों का ह्रास भी है। जब विद्यार्थी बचपन और युवावस्था में अच्छे संस्कारों से वंचित रह जाते हैं, तब आगे चलकर समाज पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए विद्यालयों में ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है, जो बच्चों को सही और गलत में अंतर समझाने के साथ-साथ समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व का भाव भी सिखाए। मूल्य आधारित शिक्षा विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, सहनशीलता और सकारात्मक सोच विकसित करती है। यह उन्हें दूसरों का सम्मान करना, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होना, सत्य का पालन करना और कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्ग चुनने की प्रेरणा देती है। एक मूल्यवान विद्यार्थी न केवल अपने परिवार और समाज का नाम रोशन करता है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।



केशव शर्मा 'रसिक'

शिक्षकों की भूमिका इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक केवल पाठ पढ़ाने वाले नहीं, बल्कि समाज के मार्गदर्शक भी होते हैं। यदि शिक्षक अपने व्यवहार, आचरण और शिक्षण पद्धति में नैतिक मूल्यों को शामिल करें, तो विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से उनसे प्रेरित होंगे। विद्यालयों में प्रार्थना सभा, प्रेरणादायक प्रसंग, सामाजिक सेवा गतिविधियां, योग, पर्यावरण जागरूकता कार्य, म और नैतिक शिक्षा से जुड़े आयोजन विद्यार्थियों में अच्छे संस्कार विकसित करने में सहायक हो सकते हैं।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

कविता

...ये जो है जिंदगी!

मुमुक्षु के. ठाकुर
ओबड़ी मोहल्ला, चंबा टाउन

उचित नहीं है बिलकुल भी,
जीवन की चुनौतियों के नाम पर
चीखना-चिल्लाना,
और उपद्रव करना,
जीवन संघर्ष का बनाकर बहाना।
ऐसी परिस्थितियां आती ही हैं,
संसार के सभी व्यक्तियों की जिंदगी में।
कभी न कभी अवश्य ही,
जब बहुत बड़ी सफलता मानी जा सकती है।
केवल और केवल इस मानुष शरीर में होना
और सिर्फ जिंदा बने रहना भी।
कितना ही अद्भुत धैर्य और साहस चाहिए,
जीवन के वास्तविक संघर्ष में।
कितनी ही बड़ी करनी होती है प्रतीक्षा।
बीज के बोने,
उसके अंकुरित होकर पलने-बढ़ने तक।
फिर जो मिलता है
उसके पश्चात सफल जिंदगी में,
उस सफलता के समक्ष न्यूनतम और नागण्य।
मालूम पड़ते हैं
उसको पाने के लिए किए गए प्रयास और संघर्ष।
शोलों में तप-तपकर जिंदगी निखरती ही गई,
जितना नाराज हुई,
और उतना संवरती ही गई।

संपादकीय

जुड़ेंगी नई गाथाएं

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की ओर से हाल ही में कक्षा नौ की सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्यपुस्तक 'अंडरस्टैंडिंग सोसायटी एंड बियांड, भाग-2' जारी की गई है। इसे भारतीय इतिहास के पुनर्पाठ और उसे व्यापक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा सकता है। लंबे समय से इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में दिल्ली और उसके आसपास केंद्रित राजनीतिक घटनाओं तथा सल्तनत और मुगल शासकों को प्रमुखता मिलती रही है। इसके मुकाबले देश के विभिन्न हिस्सों में विकसित हुए साम्राज्यों, राजवंशों, सांस्कृतिक परंपराओं और विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध हुए संघर्षों को अपेक्षाकृत कम स्थान मिला। नई पुस्तक इस दायरे को विस्तृत करने का प्रयास करती है।

भारत का इतिहास केवल दिल्ली के शासकों और सत्ता परिवर्तन की घटनाओं तक सीमित नहीं है। यह विभिन्न क्षेत्रों में विकसित सभ्यताओं, शासन व्यवस्थाओं, सामाजिक संरचनाओं और सांस्कृतिक उपलब्धियों का विस्तृत वृत्तांत है। अहोम, मेवाड़, मराठा और विजयनगर जैसे साम्राज्यों ने भारतीय इतिहास को अलग-अलग स्तरों पर प्रभावित किया। अहोम साम्राज्य ने लगभग छह शताब्दियों तक असम में अपनी सत्ता बनाए रखी और मुगल विस्तार का विरोध किया। मेवाड़ के शासकों ने स्वाधीनता और स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया। मराठा शक्ति ने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जबकि विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण भारत में कला, साहित्य, स्थापत्य और व्यापार को नई ऊंचाइयां प्रदान कीं। इसके अतिरिक्त चोल, चालुक्य, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और काकतीय राजवंशों का योगदान भी इतिहास में पर्याप्त विस्तार से सामने आना चाहिए।

इतिहास का उद्देश्य केवल विजयों और पराजयों का विवरण देना नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों और शक्तियों को समझना भी है, जिन्होंने भारत की सभ्यतागत निरंतरता बनाए रखी। विदेशी आक्रमणों के बावजूद यहां की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं किस प्रकार जीवित रहीं, यह अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय है। इसके लिए राजनीतिक संघर्षों के साथ-साथ सामाजिक संगठनों, धार्मिक संस्थाओं, स्थानीय शासकों और सांस्कृतिक आंदोलनों की भूमिका को भी समझना आवश्यक है। नई पाठ्यपुस्तक में महाराणा प्रताप, दिवेर के युद्ध, सरायघाट में लचित बरफुकन के नेतृत्व में मुगलों की पराजय, मराठों के स्वराज और सिख गुरुओं के बलिदान को स्थान देना इसी व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है।

भारतीय इतिहास में महिलाओं के योगदान को भी लंबे समय तक अपेक्षित महत्व नहीं मिल पाया। रानी नायकी देवी, रानी रुद्रमा देवी और रानी अब्बक्का जैसी वीरांगनाओं ने विदेशी आक्रमणों और विस्तारवादी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए साहस और नेतृत्व का परिचय दिया। उनके योगदान को नई पीढ़ी के सामने लाना इसलिए जरूरी है, ताकि इतिहास का अध्ययन केवल पुरुष शासकों और सेनानायकों तक सीमित न रहे। देश के अलग-अलग क्षेत्रों में महिलाओं की राजनीतिक, सामाजिक और सैन्य भूमिका को भी उचित स्थान मिल सके।

इतिहास लेखन में धार्मिक आस्थाओं, परंपराओं और सांस्कृतिक प्रतीकों का अध्ययन भी महत्वपूर्ण है। भारतीय समाज में देवी-देवताओं से जुड़ी मान्यताओं, धार्मिक प्रतीकों और लोक परंपराओं ने विभिन्न कालखंडों में लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का काम किया है। देवी दंतेश्वरी, भवानी और दुर्गा से जुड़ी परंपराएं अनेक क्षेत्रों के सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा रही हैं। इसी प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज और अन्य ऐतिहासिक शासकों से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं का अध्ययन उनके समय के सामाजिक परिवेश को समझने में मदद कर सकता है। हालांकि ऐसी परंपराओं का उल्लेख करते समय ऐतिहासिक प्रमाणों, साहित्यिक संदर्भों और लोकविश्वासों के बीच अंतर स्पष्ट रखना भी जरूरी है। इतिहास को न तो आस्था से पूरी तरह अलग किया जा सकता है और न ही किंवदंतियों को बिना प्रमाण ऐतिहासिक तथ्य माना जा सकता है।

मंदिरों के विध्वंस और उनके पुनर्निर्माण का प्रसंग भी भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विभिन्न कालखंडों में मंदिरों को धार्मिक आस्था के केंद्र के साथ-साथ कला, शिक्षा, स्थापत्य और सामाजिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में भी देखा जाता रहा है। राजा टोडरमल, राजा मान सिंह और देवी अहिल्याबाई होलकर जैसे व्यक्तित्वों के योगदान से मंदिरों के संरक्षण और पुनर्निर्माण की परंपरा को समझा जा सकता है। देवी अहिल्याबाई होलकर ने देश के अनेक प्रमुख तीर्थस्थलों और मंदिरों के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं सूरदास, तुलसीदास, कबीर और मीराबाई जैसे संतों तथा चैतन्य महाप्रभु के भक्ति आंदोलनों ने सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत किया। इन आंदोलनों ने भाषा, साहित्य और लोकजीवन के माध्यम से व्यापक समाज को प्रभावित किया। नई पाठ्यपुस्तक में भारतीय शासन परंपराओं, प्राचीन गणराज्यों और कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों को भी महत्व दिया गया है। भारतीय राजनीतिक चिंतन और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अध्ययन आधुनिक लोकतंत्र तथा संवैधानिक संस्थाओं के विकास को समझने में सहायक हो सकता है। 'सत्यमेव जयते' जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों और संसद के नए भवन में स्थापित सेंगोल का उल्लेख भी इसी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संदर्भ को सामने लाता है।

- शिवांश धाकड़

आज की प्रमुख हस्ती

भारत के लौह पुरुष

सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। उनका पूरा नाम वल्लभभाई झावेरभाई पटेल था। वह स्वतंत्रता सेनानी, कुशल अधिवक्ता और महान राजनेता थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान और आजादी के बाद देश की एकता एवं अखंडता स्थापित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण उन्हें 'लौह पुरुष' के नाम से जाना जाता है। उनका निधन 15 दिसंबर 1950 को हुआ था।



सरदार वल्लभभाई पटेल
जन्म : 31 अक्टूबर 1875

सरदार पटेल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुजरात में प्राप्त की और बाद में कानून की पढ़ाई कर सफल वकील बने। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर वह स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने खेड़ा, बोरसद और बारडोली में किसानों को संगठित कर अंग्रेजी शासन के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाए। बारडोली सत्याग्रह की सफलता के बाद उन्हें 'सरदार' की उपाधि मिली। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में शामिल हुए और संगठन को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई। वर्ष 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। इस दौरान मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीतियों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए।

वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरदार पटेल ने मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया और लोगों से अंग्रेजी शासन के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। उनके भाषण ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की। देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने के बाद वह भारत के पहले उपप्रधानमंत्री और गृहमंत्री बने। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने की थी। उस समय देश में लगभग 565 रियासतें थीं। सरदार पटेल ने वीपी मेनन के सहयोग से इन रियासतों के शासकों से बातचीत कर अधिकांश को भारत में विलय के लिए राजी किया। इस कार्य ने स्वतंत्र भारत की राजनीतिक एकता की नींव रखी।

'भारतेन्दु शिखर'

प्रकाशक, मुद्रक, संपादक एवं स्वामी शिवांश धाकड़ द्वारा शर्मा भवन, न्यू रणजीत नगर, एप्पल फ्रूट मंडी, नजदीक ढली टनल, शिमला (हि.प्र.) 171006 से प्रकाशित एवं बायोसर्ट इंटरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नंबर 8, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि.प्र.), पिन नंबर-176047 से मुद्रित। समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद शिमला न्यायालय के अधीन होंगे।

आरएनआई संदर्भ संख्या-HPHIN/2000/02437
ई-मेल : bhartendunewsmedia@gmail.com, फोन नंबर : 88946-77702

टांडा मेडिकल कॉलेज में दवाओं की किल्लत मरीजों को बाहर से खरीदनी पड़ रहीं महंगी दवाएं

दवाओं की अनुपलब्धता पर मरीजों ने अस्पताल प्रशासन के प्रति जताया रोष

आशीष दमीर, भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। प्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में शामिल डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में दवाओं की उपलब्धता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अस्पताल में उपचार करवाने पहुंच रहे मरीजों और उनके तीमारदारों का आरोप है कि चिकित्सकों द्वारा लिखी गई कुछ दवाएं अस्पताल की डिस्पेंसरी में उपलब्ध नहीं हो रही हैं। इसके चलते उन्हें बाजार से महंगी दवाएं खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।



दवाएं उपलब्ध न होने से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की परेशानी बढ़ गई है। हमीरपुर से अपने रिश्तेदार का उपचार करवाने टांडा पहुंचे प्रशांत कुमार ने बताया कि चिकित्सकों ने उपचार के बाद कुछ दवाएं लिखीं। इसके बाद वह अस्पताल की डिस्पेंसरी में दवाएं लेने पहुंचे, जहां उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। नंबर आने पर डिस्पेंसरी में बताया गया कि लिखी गई दवाएं उपलब्ध नहीं हैं।

उन्होंने बताया कि अस्पताल के बाहर दवाओं की कीमत पता करने पर वे काफी महंगी निकलीं। ऐसे में उनके लिए सभी दवाएं खरीद पाना संभव नहीं था। प्रशांत कुमार ने कहा कि एक ओर प्रदेश सरकार सरकारी अस्पतालों में मरीजों को आवश्यक दवाएं उपलब्ध करवाने के दावे करती है, वहीं दूसरी ओर अस्पताल में दवाएं न मिलने से इन दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार पहले ही उपचार के खर्च से परेशान रहते हैं।

ऐसे में अस्पताल से दवाएं न मिलने पर उन्हें अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। उन्होंने मांग की कि अस्पताल में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि मरीजों को बाजार से महंगी दवाएं न खरीदनी पड़ें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो लोग अस्पताल प्रशासन और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने को मजबूर होंगे।

सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की कमी से मरीज परेशान

इस मामले को लेकर मरीजों और तीमारदारों में नाराजगी बढ़ रही है। उनका कहना है कि सरकारी अस्पतालों में उपचार के साथ आवश्यक दवाएं उपलब्ध करवाना भी स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदारी है। यदि मरीजों को चिकित्सकों द्वारा लिखी गई दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ें तो सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली सुविधाओं का उद्देश्य प्रभावित होता है। खासकर दूरदराज के क्षेत्रों से उपचार के लिए आने वाले लोगों को दवाओं की कमी के कारण अतिरिक्त परेशानी झेलनी पड़ती है। उन्हें अस्पताल आने-जाने के खर्च के साथ महंगी दवाओं का खर्च भी उठाना पड़ता है। वहीं, अस्पताल प्रशासन का कहना है कि कुछ दवाओं की उपलब्धता में कमी है, जिसे जल्द दूर कर लिया जाएगा। ऐसे में मरीजों को उम्मीद है कि प्रशासन जल्द आवश्यक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा, ताकि उन्हें उपचार के बाद दवाओं के लिए भटकना न पड़े।

पीएम .किसान योजना से अब तक 4 .47 लाख करोड़ से अधिक राशि वितरित : अनुराग ठाकुर

सुरेंद्र कटोच, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी किए जाने का स्वागत करते हुए इसे देश के अन्नदाताओं के लिए दीपावली पर समृद्धि का उपहार बताया। इस किस्त के तहत देशभर के 9.34 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,690 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई है। उन्होंने कहा कि किसानों का सम्मानए उनकी आर्थिक मजबूती और उनके कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता भारतीय जनता पार्टी की मूल पहचान है। उन्होंने कहा कि दीपावली से पहले किसानों को मिली यह आर्थिक सहायता कृषि परिवारों को संबल प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि पीएम.किसान योजना ने देश के कृषि क्षेत्र में आर्थिक सहायता का एक नया और प्रभावी मॉडल स्थापित किया है। योजना की शुरुआत से अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। नवीनतम किस्त जारी होने के साथ ही विभिन्न किस्तों के माध्यम से किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4.47 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गई है। यह सहायता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और कृषि परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।



उन्होंने कहा कि किसानों का सशक्तिकरण विकसित भारत के संकल्प का एक महत्वपूर्ण आधार है। पीएम.किसान जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों को खेती से जुड़ी आवश्यकताओं और कृषि निवेश की लागत पूरी करने में आर्थिक सहयोग मिल रहा है। केंद्र सरकार का लक्ष्य किसानों को आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनाना हैए ताकि वे देश की प्रगति और खुशहाली में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहें।

न्यूज ब्रीफ

उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित

भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। उपायुक्त डॉ. अमित शर्मा की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इसमें सड़क हादसों की रोकथाम और यातायात नियमों की अनुपालना की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने बताया कि नशे में वाहन चलाने वाले चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। उन्होंने पुलिस और परिवहन विभाग को ओवरलोडिंग, तेज रफ्तार, बिना हेलमेट और असुरक्षित ढंग से सामान ढोने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही स्कूल बसों की जांच और दुर्घटना संभावित स्थलों पर सुधार करने को कहा।

युवाओं को खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ें : डॉ. अमित शर्मा

भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। उपायुक्त डॉ. अमित शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय नारकोटिक्स समन्वय केंद्र समिति की बैठक हुई। इसमें नशा तस्करी, एनडीपीएस मामलों और अवैध भांग-अफीम की खेती रोकने की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने 28 अति संवेदनशील पंचायतों में नशा निवारण समितियों की नियमित बैठकें करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूलों में एंटी चिट्टा जागरूकता अभियान, शपथ और विशेषज्ञों के व्याख्यान आयोजित करने को कहा। साथ ही अवैध खेती की पहचान कर नष्ट करने और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए।

जोगिंदरनगर में भाजपा का कुनबा बढ़ा, 60 से अधिक लोगों ने थामा दामन

भारतेन्दु संवाददाता, जोगिंदरनगर। यहां 30 अक्टूबर को एसआईआर और लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ विषय पर प्रबुद्धजन संगोष्ठी आयोजित की गई। इसमें भाजपा प्रदेश सचिव प्रियंता शर्मा मुख्य वक्ता रहीं, जबकि विधायक प्रकाश राणा विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान करीब 60 लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इनमें विभिन्न महिला मंडलों के सदस्य भी शामिल रहे। विधायक ने सभी से संगठन की मजबूती के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। भाजपा जिला महामंत्री कर्ण कोंडल ने सभी का आभार जताया। उन्होंने बताया कि 4 नवंबर को मंडी में होने वाली पदयात्रा में जोगिंदरनगर से 1500 कार्यकर्ता भाग लेंगे।

जोगिंद्रनगर की निहिता ठाकुर ने बोर्ड मेरिट सूची में हासिल किया दसवां स्थान

भारतेन्दु संवाददाता, जोगिंद्रनगर। सरस्वती विद्या मंदिर उच्च विद्यालय बालकरूपी की छात्रा निहिता ठाकुर ने बोर्ड की संशोधित मेरिट सूची में दसवां स्थान हासिल किया है। उन्होंने 700 में से 690 अंक प्राप्त किए। 28 अक्टूबर को जारी संशोधित मेरिट सूची में नाम शामिल होने से विद्यालय में खुशी का माहौल है। विद्यालय के जिला उपाध्यक्ष कांशीराम, प्रबंधक अश्विनी सूद और प्रधानाचार्य नवीन कुमार ने निहिता और उनके परिवार को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

कैंसर दवाओं की कीमतों में कटौती का भाजपा प्रवक्ता पंकज जमवाल ने किया स्वागत

भारतेन्दु संवाददाता, जोगिंद्रनगर। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता पंकज जमवाल ने कैंसर की 137 श्रेणियों की 543 ब्रांडेड दवाओं की कीमतों में कटौती के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन 30 प्रतिशत तक सीमित करने से मरीजों को आर्थिक राहत मिलेगी। जमवाल ने आयुष्मान भारत योजना की सराहना करते हुए हिमाचल की सुक्खू सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने हिमकेयर के लंबित भुगतान चुकाने, डॉक्टरों की नियुक्ति और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की।

व्यापारियों को जीएसटी नियमों का पालन करने की सलाह, उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना

भारतेन्दु संवाददाता, जोगिंद्रनगर। व्यापार मंडल जोगिंद्रनगर की आबकारी एवं कराधान अधिकारी रजनीश ठाकुर के साथ बैठक हुई। इसमें व्यापारियों को जीएसटी नियमों की जानकारी देते हुए उनका पालन करने की सलाह दी गई। अधिकारी ने दुकानों के बाहर जीएसटी नंबर प्रदर्शित करने, गोदामों की जानकारी विभाग में दर्ज करवाने और खरीद-बिक्री के उचित बिल रखने के निर्देश दिए। उन्होंने चेताया कि अंडर बिलिंग, बिना बिल माल रखने और नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। व्यापार मंडल ने भी सदस्यों से नियमों का पालन करने की अपील की।

थापकौर में तीन नवंबर को वॉलीबॉल अकादमी का होगा भव्य उद्घाटन

भारतेन्दु संवाददाता, अशोक ठाकुर , इंदौरा। क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गुरु राजीव वशिष्ठ वॉलीबॉल एवं फिजिकल फिटनेस अकादमी का शुभारंभ तीन नवंबर को गांव थापकौर में होगा। इस अवसर पर वॉलीबॉल टूर्नामेंट के साथ जिला कांगड़ा की जूनियर वॉलीबॉल टीम के चयन के लिए लड़के और लड़कियों के ट्रायल भी होंगे। हिमाचल प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में होने वाली द्वितीय जूनियर राज्य स्तरीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए आयोजित ट्रायल में एक जनवरी 2009 या उसके बाद जन्मे खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। चयनित खिलाड़ी 14 से 16 नवंबर तक बंगाणा में होने वाली प्रतियोगिता में जिला कांगड़ा का प्रतिनिधित्व करेंगे। अकादमी संचालक राजीव वशिष्ठ ने बताया कि ग्रामीण प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण और मंच देना अकादमी का मुख्य उद्देश्य है। ट्रायल में आने वाले खिलाड़ियों को आधार कार्ड, जन्मतिथि प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो लाना अनिवार्य होगा।

नगर निगम पालमपुर एवं स्थानीय विधायक ने की वादाखिलाफी : प्रवीन कुमार पूर्व विधायक

भारतेन्दु संवाददाता, पालमपुर। पुराने बस अड्डे के परिसर में पर्यटन विभाग की ओर से निर्माणाधीन भवन के कारण प्रभावित दुकानदारों, टैक्सी और ऑटो ऑपरेटरों की समस्याओं को लेकर पूर्व विधायक प्रवीन कुमार ने नगर निगम और स्थानीय विधायक पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रभावित लोगों के पुनर्वास की प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की।



प्रवीन कुमार ने कहा कि पुराने बस अड्डे पर वर्षों से दुकानदार, टैक्सी और ऑटो ऑपरेटर मेहनत से रोजी-रोटी कमाकर परिवारों का पालन-पोषण कर रहे थे। निर्माण कार्य के चलते अब उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने सवाल किया कि पुनर्वास को लेकर बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए फैसलों को अब तक लागू क्यों नहीं किया गया। पूर्व विधायक ने बताया कि गत 25 नवंबर को पुराने बस अड्डे पर हुई बैठक में स्थानीय विधायक आशीष बुटेल, गोपाल नाग, नगर निगम की अतिरिक्त आयुक्त राधा सूद, दिलबाग, ठाकुर राज कुमार और संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव सोनी सहित अन्य लोग मौजूद थे। बैठक में प्रभावित दुकानदारों के पुनर्वास पर सहमति बनी थी।

प्रस्ताव के अनुसार, निर्माणाधीन भवन का पहला लैंटर पड़ते ही नई दुकानों का निर्माण शुरू होना था। नई दुकानें पुरानी दुकानों से बड़ी बनाई जानी थीं, जबकि किराया पहले जितना ही रखने और दुकानदारों से अतिरिक्त खर्च न लेने का निर्णय हुआ था। दुकानों में बिजली-पानी की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जानी थी। प्रवीन कुमार ने कहा कि भवन के तीन लैंटर पड़ चुके हैं और चौथे की तैयारी है, लेकिन दुकानदारों को दुकानें नहीं मिली हैं। उन्होंने टैक्सी-ऑटो ऑपरेटरों की समस्याओं का भी स्थायी समाधान करने की मांग उठाई।

गुरदासपुर में तिरंगे कूड़े में फेंकने पर भड़के लोग

भारतेन्दु संवाददाता,गुरदासपुर। गुरदासपुर-कलानौर रोड पर डी-मार्ट के सामने कूड़े के डंप में भारी संख्या में राष्ट्रीय ध्वज पड़े मिलने से स्थानीय निवासियों और समाजसेवियों में रोष फैल गया। सूचना मिलने पर समाजसेवी मौके पर पहुंचे और तिरंगों को पूरे सम्मान के साथ उठाकर सुरक्षित रख लिया। रिक्की महंत, वरुण मिद्ढ, राजू महाजन, प्रवीण कुमार और शिव दुग्गल ने घटना पर नाराजगी जताते हुए इसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि तिरंगे की आन-बान और शान की रक्षा के लिए सैनिकों और शहीदों ने कुर्बानियां दी हैं। ऐसे में इन्हें कूड़े में फेंकना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजसेवियों ने मामले की लिखित शिकायत डीसी और एसएसपी को देने तथा निष्पक्ष जांच की मांग की है।

पठानकोट-अमृतसर हाईवे पर स्कूटी अज्ञात वाहन से टकराई, अमृतसर निवासी की मौत



भारतेन्दु संवाददाता, पठानकोट। पठानकोट-अमृतसर नेशनल हाईवे पर सरना ओवरब्रिज के समीप एक पैलेस के सामने सड़क हादसे में स्कूटी सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान लखविंदर सिंह (42) निवासी गांव जंड, अमृतसर के रूप में हुई है। वह अपने बीमार पिता की दवा लेने पठानकोट आ रहा था। इस दौरान उसकी स्कूटी किसी अज्ञात वाहन के पीछे जा टकराई। हादसे की सूचना मिलते ही थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के पास मिले दस्तावेजों और मोबाइल के आधार पर परिजनों को सूचित किया गया। मृतक की पत्नी मनवीर कौर ने पुलिस को बताया कि लखविंदर अपने पिता जगीर सिंह की दवा लेने स्कूटी पर निकले थे। सरना ब्रिज के पास हादसे में उनके सिर पर गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी मौत हो गई।

मनवीर कौर ने बताया कि जब उन्होंने पति के मोबाइल पर फोन किया तो पुलिस कर्मचारी ने हादसे की जानकारी दी। लखविंदर के परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं। सूचना मिलने पर परिजन पठानकोट पहुंचे। उन्होंने मामले में कानूनी कार्रवाई करवाने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया।

जोगिंद्रनगर के रोशन का नया गीत छुणकिए हुआ लॉन्च

जितेंदर कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, जोगिंद्रनगर। हिमाचल की लोक संस्कृति और पहाड़ी संगीत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गीतकार रोशन ठाकुर ने गुरुवार को अपना नया पहाड़ी गीत 'छुणकिए' लॉन्च किया। 'लाल लाल हेरे सेवे रा दाना' बोलों से सजे इस गीत में हिमाचली लोक परंपराओं और संस्कृति को संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। गीत को प्रसिद्ध गायक संजय बग्वाल ने आवाज दी है। इसके बोल रोशन ठाकुर ने लिखे हैं, जबकि संगीत अभय ठाकुर ने तैयार किया है। गीत में सुनीता देवी और नाग पाल ने अभिनय किया है। रोशन ठाकुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुम्मा में इतिहास प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं। शिक्षण कार्य के साथ वह पहाड़ी भाषा और लोक संगीत को बढ़ावा देने में भी जुटे हैं। वह अब तक आठ पहाड़ी गीत लिख चुके हैं। देव पशाकोट पर आधारित उनका गीत काफी लोकप्रिय रहा है।

लाहौल-स्पीति में भाजपा का बढ़ता कुनबा, कांग्रेस और विकास मंच छोड़ कई परिवार पार्टी में शामिल

भारतेन्दु संवाददाता, केलांग। लाहौल-स्पीति जिले में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में उदयपुर मंडल में कांग्रेस और विकास मंच से जुड़े रहे छह प्रमुख परिवारों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रवि ठाकुर ने पार्टी में शामिल हुए सभी लोगों का स्वागत किया और उन्हें संगठन में उचित मान-सम्मान देने का भरोसा दिलाया।

भाजपा की ओर से जारी जानकारी के अनुसार तलजोंण से लोक निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी लाल चंद बेलवा, जुण्डा से पूर्व प्रधान के पति चमन लाल और वन विभाग के सेवानिवृत्त सुपरिंटेंडेंट शेर लाल भाजपा में शामिल हुए। इसके अलावा उदयपुर से पूर्व प्रधान मायादास, जहालमा से राजेंद्र और कमरिंग से विनोद कुमार ने भी अपने परिवारों सहित पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।



◆ उदयपुर मंडल में छह परिवारों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की

इस अवसर पर रवि ठाकुर ने कहा कि नए सदस्यों के पार्टी से जुड़ने से उदयपुर मंडल में संगठन को नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा में प्रत्येक कार्यकर्ता को उचित मान-सम्मान और जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य जनसेवा के साथ संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना है। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सभी नए और पुराने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया, ताकि लाहौल-स्पीति में भाजपा को और मजबूत बनाया जा सके।

पार्टी में नए सदस्यों को जोड़ने और संगठनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में कई कार्यकर्ताओं ने योगदान दिया। इनमें किशोरी रावत, जगदीश ठाकुर जहालमा, सुनील सिंधवाड़ी, जगदीश थिरोट, रणजीत तिबोग, देवी सिंह उदयपुर, उदयपुर मंडल विस्तारक नवल ठाकुर, पूर्व प्रधान शेर सिंह थिरोट, राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी राम लाल, हितेश बारिंग, सरोज, जसरथ और धर्मपाल शामिल रहे।

जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में केलांग में 15 दिनों तक होंगी गतिविधियां

◆ विद्यार्थियों और युवाओं की भागीदारी पर रहेगा विशेष जोर

भारतेन्दु संवाददाता, केलांग। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस के तहत लाहौल एवं स्पीति जिले में पहली से 15 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान का मुख्य समारोह 15 नवंबर को केलांग में होगा। आयोजन की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को उपायुक्त निवेदिता नेगी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक का संचालन पीओ (आईटीडीपी) अश्वनी कुमार ने किया। इसमें एसडीएम कुनिका एकर्स सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में अभियान के तहत प्रस्तावित गतिविधियों और कार्ययोजना की समीक्षा की गई। अधिकारियों को बताया गया कि कार्यक्रमों का कैलेंडर तैयार किया गया है। इसके तहत 'धरती आबा योजना' से जुड़े गांवों में विभिन्न गतिविधियां अनिवार्य रूप से आयोजित होंगी। विद्यार्थियों और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पेंटिंग, भाषण, कला, हस्तशिल्प और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। जनजातीय संस्कृति, कला और परंपराओं को दर्शाने वाले कार्यक्रम भी आयोजित होंगे।

एनएसएस, एनसीसी और 'माई भारत पोर्टल' के माध्यम से युवाओं को इन गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। अभियान के तहत स्वच्छता और पौधारोपण कार्यक्रम भी होंगे। इन्हें सरकार के 'स्कूल एडॉप्शन कार्यक्रम' से जोड़ा जाएगा। इसके अंतर्गत अधिकारी अपने गोद लिए स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों से संवाद करेंगे और उन्हें रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे। वहीं, 'रिफॉर्म उत्सव' के तहत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और जनजातीय भाषाओं के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए विशेष कार्यक्रम होंगे।

लोकतंत्र बचाने का ढोंग करने कर रही भाजपा वोट का अधिकार छीनने पर चुप्पी क्यों : मल्ली

सनी महाजन, भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता पुनीत मल्ली ने भाजपा की ओर से धर्मशाला में निकाली गई 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा को ढोंग करार दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि पात्र मतदाताओं के मताधिकार की रक्षा की जिम्मेदारी कौन निभाएगा।



शुक्रवार को जारी बयान में मल्ली ने कहा कि लोकतंत्र केवल रैलियों, नारों और भाषणों से मजबूत नहीं होता, बल्कि निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र संस्थाओं और पारदर्शी प्रक्रियाओं से इसकी मजबूती सुनिश्चित होती है। प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने या फर्जी प्रविष्टियां हटाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन यह प्रक्रिया निर्धारित कानूनी प्रावधानों, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ होनी चाहिए। एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाना अराजकता नहीं, बल्कि नागरिकों के अधिकारों के प्रति जिम्मेदारी है। मल्ली ने भाजपा से पूछा कि यदि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से कट जाता है, तो उसे दोबारा मताधिकार दिलाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? गरीबों, बुजुर्गों, प्रवासी श्रमिकों और दूरदराज के लोगों को दस्तावेज जुटाने या प्रक्रिया पूरी करने में परेशानी होने पर क्या व्यवस्था होगी?

उन्होंने कहा कि भाजपा सांसदों, विधायकों और नेताओं को नारों के बजाय महंगाई, बेरोजगारी और ग्रामीण समस्याओं पर जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष का काम सवाल उठाना है, जबकि सरकार और संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी तथ्यों के साथ जवाब देना है।

जलक्रांति विभिन्न योजनाओं के तहत क्षेत्र में अब तक करीब 350 करोड़ रुपए खर्च

जल शक्ति योजनाओं पर 500 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य: मुकेश अग्निहोत्री

भारतेन्दु संवाददाता, हरोली। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में पानी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए जल शक्ति विभाग की विभिन्न योजनाओं पर 500 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से करीब 350 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। पेयजल आपूर्ति मजबूत करने और किसानों के खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को उन्होंने 36 करोड़ रुपये की विभिन्न पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। इसके साथ ही टाहलीवाल सीवरेज योजना की आधारशिला भी रखी।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हरोली में पेयजल उपलब्धता और सिंचाई लंबे समय से बड़ी चुनौती रही है। इसे ध्यान में रखते हुए भविष्य की जरूरतों के अनुरूप योजनाएं तैयार की जा रही हैं। करीब 101 करोड़ रुपये की योजना के तहत 136 पुराने ट्यूबवेलों की री-



ड्रिलिंग की जा रही है। साथ ही लगभग 50 नए जल भंडारण टैंकों के निर्माण और पाइपलाइन बिछाने का प्रावधान है।

75 करोड़ से बीत क्षेत्र की जमीन होगी सिंचित: उप मुख्यमंत्री ने बताया कि बीत क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर करीब 75 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इससे बीत क्षेत्र के अलावा पालकवाह और कर्मपुर से भटकलां तक की जमीन को सिंचाई सुविधा मिलेगी। पालकवाह-कर्मपुर के आसपास मुख्य पंप हाउस बनाया जा रहा है। योजना में सौर ऊर्जा के उपयोग की व्यवस्था भी होगी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में अब तक 88 जल भंडारण टैंक तैयार किए जा चुके हैं, जबकि 50 अन्य टैंक बनाए जाएंगे। करीब 100 करोड़ रुपये की एक अन्य योजना स्वीकृति के करीब है, जिससे पंडोगा क्षेत्र को लाभ मिलेगा।

प्रदेश के वित्तीय हितों पर भाजपा ने नहीं दिया साथ: मुकेश: मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने में सहयोग नहीं किया। आरडीजी, जीएसटी मुआवजे और केंद्र से मिलने वाली अन्य वित्तीय सहायता में कमी का प्रदेश के संसाधनों पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि राज्यों को करों में निर्धारित हिस्सा मिलना उनका अधिकार है, खैरात नहीं।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता विकास कार्यों का श्रेय लेने का प्रयास करते हैं। उनके अनुसार हरोली में 18 पुलों का निर्माण किया जा रहा है और छूटे हुए संपर्क मार्गों को जोड़ने का काम जारी है। पंडोगा-त्यूड़ी पुल सहित विभिन्न परियोजनाओं पर श्रेय लेने की राजनीति हो रही है, जबकि केंद्र से मिलने वाली धनराशि में प्रदेश का निर्धारित हिस्सा भी शामिल रहता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में सभी जनप्रतिनिधियों की सकारात्मक भूमिका जरूरी है। सरकार जनहित की योजनाओं को आगे बढ़ाने और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।

पूर्व सैनिकों को एम्स में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी : त्रिलोक

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को अब ईसीएचएस (एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम) के तहत कैशलेस इलाज करवाने के लिए चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। थल सेना, वायुसेना, नौसेना और असम राइफल्स के पूर्व सैनिक अब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बिलासपुर में भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।



पूर्व सैनिकों की लंबे समय से लंबित मांग पूरी होने पर बिलासपुर सदर के विधायक त्रिलोक जमवाल ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने एम्स में ईसीएचएस सुविधा शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का आभार जताया। विधायक त्रिलोक जमवाल ने कहा कि पहले हिमाचल के पूर्व सैनिकों को ईसीएचएस के तहत कैशलेस इलाज के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ता था। खासकर दूरदराज के जिलों में रहने वाले पूर्व सैनिकों के लिए वहां पहुंचना काफी मुश्किल होता था। इस दौरान उन्हें किराये पर काफी पैसा खर्च करना पड़ता था और समय भी बर्बाद होता था।

एम्स बिलासपुर बनने के बाद से ही पूर्व सैनिक यहां ईसीएचएस सुविधा शुरू करने की मांग उठा रहे थे। अब केंद्र सरकार के फैसले से उनकी यह मांग पूरी हो गई है। इससे पूर्व सैनिकों को अपने प्रदेश में ही उपचार की सुविधा मिलेगी और चंडीगढ़ आने-जाने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। त्रिलोक जमवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने कैंसर की दवाइयों की कीमतों में भी लगभग 93 प्रतिशत तक की कमी की है। इससे कैंसर मरीजों को उपचार के दौरान बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।

धर्मबीर भांगरोला ने संभाला सीनियर डिप्टी मेयर का पदभार

भारतेन्दु संवादाता, **गुरुग्राम।** गुरुग्राम नगर निगम के नवनिर्वाचित सीनियर डिप्टी मेयर धर्मबीर भांगरोला ने शुक्रवार को विधिवत रूप से अपना पदभार ग्रहण कर लिया। नगर निगम कार्यालय में आयोजित समारोह में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर समर्थकों और पार्षदों ने धर्मबीर भांगरोला का फूल-मालाओं से स्वागत किया और उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी।

कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने सीनियर डिप्टी मेयर को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गुरुग्राम का समग्र विकास प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार शहर की बुनियादी ढांचागत समस्याओं को दूर करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। विकास योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और उन्हें रोजमर्रा की परेशानियों से राहत मिले। मंत्री ने स्पष्ट किया

◆ गुरुग्राम के विकास कार्यों में तेजी लाने पर दिया जोर

कि शहर में विकास कार्यों को लेकर किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और समस्याओं के समाधान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। शहर की सफाई व्यवस्था और कूड़ा निस्तारण भी प्राथमिकता के प्रमुख मुद्दे रहेंगे। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम तेजी से विकसित हो रहा है और यहां की बढ़ती आबादी के अनुरूप बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना जरूरी है। नगर निगम को सफाई, सड़क, जल निकासी और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे। धर्मबीर भांगरोला के पदभार संभालने के साथ ही शहरवासियों को नगर निगम से विकास कार्यों में तेजी और स्थानीय समस्याओं के बेहतर समाधान की उम्मीद है।

धर्मबीर भांगरोला ने शहर के विकास को बताया अपनी प्राथमिकता

पदभार ग्रहण करने के बाद सीनियर डिप्टी मेयर धर्मबीर भांगरोला ने कहा कि वह शहर के विकास और लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी जिम्मेदारी से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्षदों, अधिकारियों और आम नागरिकों के साथ समन्वय बनाकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। वार्डों में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं की पहचान कर उनके समाधान के लिए प्राथमिकता तय की जाएगी। उन्होंने सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और कूड़े के नियमित उठान पर विशेष ध्यान देने की बात कही। भांगरोला ने कहा कि नगर निगम से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत करना उनकी प्राथमिकताओं में रहेगा। शहरवासियों की शिकायतों को गंभीरता से सुनकर संबंधित अधिकारियों के माध्यम से उनका समाधान करवाने का प्रयास किया जाएगा।

बिलासपुर-कुलाना मार्ग के चौड़ीकरण पर खर्च होंगे 555 करोड़

परियोजना के तहत पटौदी में फ्लाईओवर और हेली मंडी में चारलेन आरओबी बनाया जाएगा

भारतेन्दु संवादाता, चंडीगढ़। हरियाणा में सड़क आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दी है। गुरुग्राम जिले के बिलासपुर से झज्जर जिले के कुलाना तक सड़क को फोरलेन बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 555.83 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद दोनों जिलों के बीच सड़क संपर्क को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही मार्ग पर यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए पटौदी शहर में फ्लाईओवर का निर्माण भी किया जाएगा।

लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने बताया कि बिलासपुर से कुलाना तक सड़क को चार लेन का बनाने की परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत



सड़क के चौड़ीकरण के साथ कुछ महत्वपूर्ण निर्माण कार्य भी किए जाएंगे। परियोजना में पटौदी शहर में फ्लाईओवर बनाने का प्रविधान किया गया है। इसके अलावा हेली मंडी में मौजूदा रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) को भी दो लेन से बढ़ाकर चार लेन का किया जाएगा। परियोजना के तहत हेली मंडी में रेलवे क्रासिंग संख्या 45-ए पर बने मौजूदा दो लेन के रेलवे ओवरब्रिज को चार लेन का किया जाएगा। इससे संबंधित मार्ग पर सड़क की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। अभी यहां दो लेन का आरओबी मौजूद है, जिसे

सड़क फोरलेन होने से आवागमन होगा सुगम

इसके साथ ही परियोजना के लिए 555.83 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी मिलने से निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। लोक निर्माण विभाग की ओर से इस परियोजना को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा। सड़क के फोरलेन होने से बिलासपुर, पटौदी और कुलाना के बीच आवागमन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वहीं, पटौदी में फ्लाईओवर और हेली मंडी में आरओबी के चार लेन का होने से मार्ग के प्रमुख यातायात बिंदुओं पर सुविधा बढ़ने की उम्मीद है।

परियोजना के तहत विस्तारित करने की योजना बनाई गई है। इस कार्य को बिलासपुर-कुलाना सड़क फोरलेन परियोजना का हिस्सा बनाया गया है।

रेलवे ओवरब्रिज का विस्तार इस परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। सड़क को फोरलेन करने के साथ रेलवे क्रासिंग पर यातायात के लिए बेहतर व्यवस्था विकसित करने की दिशा में भी काम किया जाएगा। इससे इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को सुविधा मिलने की उम्मीद है।

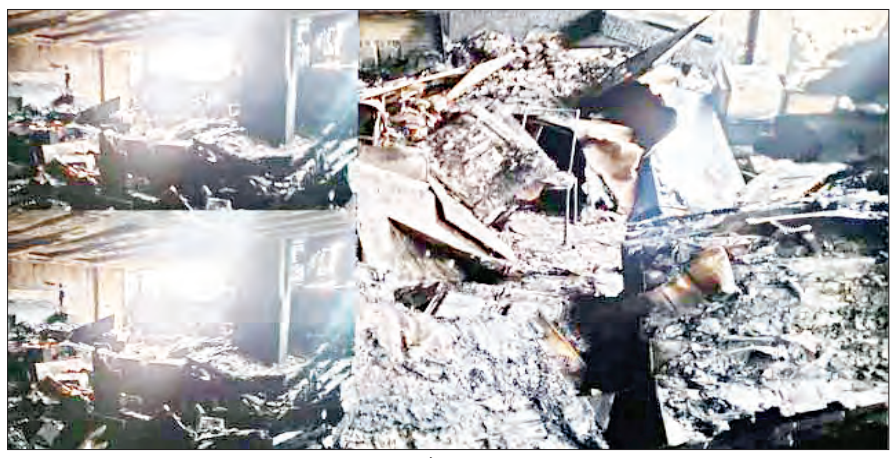
बिलासपुर से कुलाना तक सड़क को फोरलेन करने के साथ पटौदी शहर में फ्लाईओवर का निर्माण भी प्रस्तावित है। शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इसे परियोजना में शामिल किया गया है। फ्लाईओवर बनने से संबंधित मार्ग पर वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाने में मदद मिल सकती है।

पलवल के इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में लगी भीषण आग, करोड़ों का सामान जलकर राख

पांच घंटे की मशक्कत के बाद दमकलकर्मियों ने आग पर पाया काबू

भारतेन्दु संवादाता, पलवल। शहर के व्यस्त रेलवे रोड स्थित एमएस इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में शुक्रवार को अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते शोरूम में रखा इलेक्ट्रॉनिक सामान इसकी चपेट में आ गया। इस हादसे में करोड़ों रुपये का सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया। गनीमत रही कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। शोरूम रेलवे रोड पर होली चिल्ड्रन स्कूल के सामने स्थित है।

आग लगने के बाद शोरूम की दूसरी मंजिल से धुएं का घना गुबार उठने लगा। कुछ ही देर में आग की लपटें दिखाई देने लगीं। धुएं और आग को देखकर आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। व्यस्त सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आग की भयावहता को देखते हुए दमकल विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। आग इतनी भीषण थी कि इसे नियंत्रित करने में



दमकलकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

करीब पांच घंटे तक लगातार प्रयास करने के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान दमकलकर्मियों ने आग को और फैलने से रोकने का प्रयास किया। आग के कारण शोरूम में रखे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य सामान को भारी नुकसान पहुंचा। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, करोड़ों रुपये का सामान जलकर नष्ट हो गया है। शोरूम में आग लगने से हुए नुकसान का वास्तविक आकलन किया जा रहा है।

राहत की बात यह रही कि घटना के समय किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं मिली। हालांकि, आग की ऊंची लपटों और धुएं के कारण आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों में चिंता बनी रही। रेलवे रोड जैसे व्यस्त क्षेत्र में आग लगने से काफी देर तक लोगों का ध्यान घटनास्थल पर लगा रहा। फिलहाल आग लगने के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है। संबंधित विभाग की ओर से घटना की जांच और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रशासन और दमकल विभाग की ओर से आग लगने के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है। जांच के बाद ही आग लगने की वजह स्पष्ट हो सकेगी। शोरूम संचालकों को हुए नुकसान का आकलन भी किया जाएगा।

हर खेत की उर्वरता का बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड, एआई से घटेगी खेती की लागत

भारतेन्दु संवादाता, करनाल। खेती में अब अनुमान की बजाय विज्ञान और आंकड़ों की भूमिका बढ़ेगी। हरियाणा के छह जिलों में मिट्टी की डिजिटल ग्रिड मैपिंग शुरू की गई है। इसके तहत खेतों की उर्वरता और उनमें मौजूद पोषक तत्वों का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इस जानकारी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक से जोड़कर किसानों को फसल और मिट्टी की जरूरत के अनुसार सलाह दी जाएगी। डिजिटल ग्रिड मैपिंग के माध्यम से खेतों की मिट्टी का वैज्ञानिक आकलन किया जाएगा। इससे पता चल सकेगा कि किस खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और अन्य पोषक तत्वों की कितनी मात्रा मौजूद है। साथ ही यह जानकारी भी मिल सकेगी कि बेहतर उत्पादन के लिए मिट्टी में किस पोषक तत्व की कितनी जरूरत है। इससे किसान बिना जरूरत खाद डालने से बच सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य खेती को अधिक वैज्ञानिक और प्रभावी बनाना है। अभी कई बार किसान सामान्य जानकारी या पुराने अनुभव के आधार पर खेतों में खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं। इससे खेती की लागत बढ़ने के साथ मिट्टी की सेहत पर भी असर पड़ सकता है। डिजिटल आंकड़ों और एआई आधारित विश्लेषण से किसानों को खेत के हिसाब से सलाह मिलने की उम्मीद है। इस तकनीक से उर्वरकों का संतुलित इस्तेमाल बढ़ेगा और अनावश्यक खर्च कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने और कृषि उत्पादन में सुधार की दिशा में भी लाभ मिल सकता है।

◆ छह जिलों में शुरू हुई मिट्टी की उर्वरता जांच की पहल

दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत का दबदबा कायम, भाजपा तलाश रही नया नेतृत्व



भारतेन्दु संवादाता, चंडीगढ़। दक्षिण हरियाणा की राजनीति में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का प्रभाव लगातार बना हुआ है। अहीरवाल क्षेत्र में उनका मजबूत जनाधार और समर्थकों का व्यापक नेटवर्क उन्हें भाजपा के भीतर एक प्रभावशाली राजनीतिक नेता के रूप में स्थापित करता है। चुनावी राजनीति से लेकर संगठनात्मक गतिविधियों तक उनकी सक्रियता का असर साफ दिखाई देता है। राव इंद्रजीत सिंह की राजनीतिक ताकत केवल उनके व्यक्तिगत जनाधार तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके साथ खड़े समर्थक विधायकों की संख्या भी उनकी स्थिति को मजबूत बनाती है। सार्वजनिक मंचों पर बेबाकी से अपनी बात रखने की शैली उन्हें पार्टी के भीतर अलग पहचान देती है।

दूसरी ओर, भाजपा दक्षिण हरियाणा में उनके समानांतर एक नया नेतृत्व तैयार करने की कोशिश में जुटी है। पार्टी की रणनीति क्षेत्र में नेतृत्व का दायरा बढ़ाने और नए चेहरों को आगे लाने की मानी जा रही है। इसी बीच राव इंद्रजीत सिंह ने समर्थक विधायकों के साथ चाय पार्टी आयोजित कर अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया।

इस मुलाकात को दक्षिण हरियाणा में उनके प्रभाव और सियासी सक्रियता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, भाजपा के लिए क्षेत्र में मजबूत वैकल्पिक नेतृत्व खड़ा करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। पार्टी नेतृत्व के सामने चुनौती है कि क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखते हुए नए नेताओं को पर्याप्त राजनीतिक अवसर दिए जाएं।

हरियाणा में एसआईआर की समयसीमा बढ़ी, अब 30 नवंबर को अंतिम सूची

निर्वाचन आयोग ने हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर लिया फैसला

भारतेन्दु संवादाता, चंडीगढ़। हरियाणा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने समयसीमा बढ़ा दी है। आयोग की ओर से जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, अब दावे और आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख 20 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है।

वहीं, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 नवंबर 2026 को किया जाएगा। इस फैसले से एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करने के लिए संबंधित अधिकारियों को अतिरिक्त समय मिल गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने 29



हरियाणा में एसआईआर की समयसीमा बढ़ाई गई।

अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किया। आयोग के अवर सचिव संदीप कुमार की ओर से हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे गए पत्र में संशोधित कार्यक्रम की जानकारी दी गई है। पत्र के अनुसार, हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। इसी अनुरोध पर विचार करने के बाद आयोग ने कार्यक्रम में बदलाव किया है। संशोधित कार्यक्रम के तहत अब दावे और आपत्तियों के निपटारे के लिए 20 नवंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। इस अवधि के दौरान मतदाता सूचियों से संबंधित प्राप्त दावों और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। इसके बाद सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर अंतिम मतदाता सूची तैयार की जाएगी।

पहले निर्धारित कार्यक्रम में बदलाव के बाद अब अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख भी आगे बढ़ा दी गई है। नई व्यवस्था के अनुसार, हरियाणा की अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर 2026 को प्रकाशित होगी। इससे पहले सूची के अंतिम प्रकाशन के लिए अलग तारीख निर्धारित थी। विशेष गहन पुनरीक्षण निर्वाचन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

जयपुर हाईवे पर दो क्षतिग्रस्त डंपरों से टकराई रोडवेज बस

भारतेन्दु संवादाता, रेवाड़ी। दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे-48 पर शुक्रवार सुबह बारिश के दौरान एक सड़क हादसा हो गया। बावल के गांव रूघ स्थित फ्लाईओवर पर पहले दो डंपर दुर्घटनाग्रस्त होकर क्षतिग्रस्त हो गए। इसी दौरान पीछे से आ रही राजस्थान रोडवेज की बस भी इन डंपरों से टकरा गई। हादसे के समय बस में करीब 27 यात्री सवार थे। टक्कर में कई यात्रियों को चोटें आईं, जबकि राहत की बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई। प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार, सुबह बारिश के कारण हाईवे पर दृश्यता कम थी। ऐसे में सड़क पर पहले से दुर्घटनाग्रस्त और क्षतिग्रस्त पड़े डंपर बस चालक को समय रहते दिखाई नहीं दिए। बस की टक्कर इतनी तेज थी कि उसका अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने घायलों की मदद की और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाने में सहयोग किया। सूचना मिलने के बाद घायलों को बावल के जैन अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उनका उपचार किया गया। हादसे में चोटिल यात्रियों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई।

दीवाली से पहले हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने दो दिवसीय हड़ताल का किया एलान

पांच और छह नवंबर को प्रदेशभर में बस सेवाएं प्रभावित होने की आशंका

भारतेन्दु संवादाता, चंडीगढ़। हरियाणा में दीवाली से पहले रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा ने 5 और 6 नवंबर को प्रदेशव्यापी दो दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। इस दौरान बस सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है, जिससे त्योहार से पहले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।



हड़ताल की तैयारियों के तहत प्रदेश के सभी डिपो में गेट मीटिंग आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों के माध्यम से कर्मचारियों को आंदोलन में शामिल होने और एकजुट रहने का आह्वान किया जा रहा है। यूनियन के वरिष्ठ नेता निशान सिंह, जयबीर घणघस और अनूप लाठर ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

यूनियन नेताओं के अनुसार कर्मचारियों की सात सूत्रीय मांगों में स्थायी भर्ती का मुद्दा प्रमुख है। इसके अलावा रोडवेज के निजीकरण और ठेके पर बसें चलाने की व्यवस्था का भी विरोध किया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकारी परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, ताकि आम लोगों को सस्ती और बेहतर यातायात सुविधा मिल सके। यूनियन नेताओं ने कहा कि यह आंदोलन केवल कर्मचारियों के हितों तक सीमित नहीं है।

रोडवेज में स्थायी भर्ती की मांग तेज

बल्कि इसके माध्यम से आम यात्रियों को सस्ती यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुरक्षित रखने की मांग भी उठाई जा रही है। यूनियन नेताओं का कहना है कि रोडवेज में स्थायी भर्ती होने से न केवल बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि बसों के संचालन और यात्रियों को दी जाने वाली सेवाओं में भी सुधार होगा। कर्मचारियों ने ठेके पर बसें चलाने की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे सरकारी परिवहन व्यवस्था कमजोर हो सकती है। उन्होंने सरकार से मांगों पर गंभीरता से विचार करने और कर्मचारियों के हित में उचित निर्णय लेने की अपील की है।

गुरुग्राम में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना, तापमान गिरा, प्रदूषण घटा

पटौदी में सर्वाधिक 80 एमएम बारिश, फरुखनगर में 51 एमएम वर्षा दर्ज

भारतेन्दु संवादाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में बृहस्पतिवार शाम से शुरू हुई बारिश का सिलसिला शुक्रवार सुबह तक जारी रहा। रातभर हुई वर्षा के बाद शुक्रवार सुबह भी कई इलाकों में रुक-रुककर बारिश होती रही। लगातार बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। वहीं, बारिश के बाद वायु गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिला है।

आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार क्षेत्र में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना बनी हुई है। वर्षा के कारण जिले के लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम ठंडा और सुहाना हो गया



◆ बारिश के बाद मानेसर का एक्यूआई 86 दर्ज किया गया

है। लंबे समय से गर्मी और उमस का सामना कर रहे लोगों को बदले मौसम से राहत मिली है। जिले में सबसे अधिक वर्षा पटौदी तहसील में दर्ज की गई, जहां 80 एमएम बारिश हुई। इसके अलावा फरुखनगर में 51 एमएम, सोहना में 42 एमएम, वजीराबाद में 39 एमएम और बादशाहपुर में 38 एमएम वर्षा दर्ज की गई।

मानेसर का एक्यूआई 86 पर पहुंचा

इसके अलावा गुरुग्राम तहसील में 27 एमएम, जबकि कादीपुर और हरसरू में 26-26 एमएम बारिश दर्ज की गई। मानेसर में सबसे कम 18 एमएम वर्षा हुई। बारिश के कारण जिले के तापमान में गिरावट आई है और मौसम ठंडा हो गया है। वहीं, वायु गुणवत्ता में भी सुधार दर्ज किया गया है। मानेसर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 86 तक पहुंच गया, जो बारिश के बाद प्रदूषण के स्तर में कमी को दर्शाता है। लगातार वर्षा से वातावरण में मौजूद धूल और प्रदूषक कणों में कमी आई है।

घोटाला एसीबी जांच में खरीद और कार्य आवंटन की अनियमितताएं उजागर

4.87 करोड़ के प्रोजेक्ट में गड़बड़ी, 11 पर एफआईआर

भारतेन्दु संवादाता, गुरुग्राम। नगर परिषद सोहना में करीब एक दशक पहले हुए स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट में वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने प्राथमिक जांच के बाद इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इनमें तत्कालीन चीफ इंजीनियर, एसडीओ, नगर परिषद के दो तत्कालीन सचिव और तीन ठेकेदार शामिल हैं।

आरोप है कि अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से सरकारी खजाने को 80 लाख रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाया गया। वर्ष 2014-15 में नगर परिषद की ओर से करीब 4.87 करोड़ रुपये की लागत से स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट कराया गया था। इस परियोजना के तहत क्षेत्र



एआई चित्र।

में स्ट्रीट लाइट से संबंधित सामान की खरीद और काम आवंटित किया गया था। एसीबी को शुरुआती जांच में परियोजना के दौरान वित्तीय और प्रशासनिक स्तर पर कई अनियमितताएं होने के संकेत मिले हैं। इसके बाद संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जांच में स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट के लिए खरीदी गई सामग्री की कीमतों पर गंभीर सवाल उठे हैं। आरोप है कि बाजार में उपलब्ध दरों की तुलना में करीब 20 से 25 प्रतिशत अधिक कीमत पर सामान खरीदा गया। इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा। जांच एजेंसी के अनुसार, खरीद प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया और इस पूरे मामले में अधिकारियों तथा ठेकेदारों की भूमिका संदिग्ध पाई गई। प्राथमिक जांच में केवल सामान की खरीद ही नहीं, बल्कि परियोजना के कार्य आवंटन को लेकर भी सवाल उठे हैं। आरोप है कि काम देने की प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई। अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच कथित मिलीभगत के कारण सरकारी धन का उचित तरीके से इस्तेमाल नहीं हो सका।

पुराने रिकॉर्ड खंगालेगी एसीबी

इस मामले में एसीबी की कार्रवाई के बाद नगर परिषद के पुराने रिकॉर्ड और परियोजना से जुड़े दस्तावेज जांच के दायरे में आ गए हैं। एजेंसी की ओर से खरीद प्रक्रिया, सामान की दरों, भुगतान और कार्य आवंटन से संबंधित रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। इसके साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि परियोजना के दौरान किन अधिकारियों ने खरीद और भुगतान को मंजूरी दी थी तथा ठेकेदारों को काम देने में निर्धारित नियमों का पालन किया गया था या नहीं। मामले में नामजद अधिकारियों और ठेकेदारों की भूमिका की भी पड़ताल होगी। जांच के दौरान यह स्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा कि कथित अनियमितताएं किन परिस्थितियों में हुईं और सरकारी खजाने को हुए नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है। करीब दस साल पुराने इस प्रोजेक्ट में एसीबी की कार्रवाई से नगर परिषद के कामकाज और सरकारी परियोजनाओं में वित्तीय पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठे हैं।

दिल्ली में रैली से दीपावली कारोबार प्रभावित होने की आशंका, व्यापारी चिंतित

सीटीआई ने सोनिया गांधी से रैली टालने का किया आग्रह, बाजारों पर मंडराया नुकसान का खतरा

एजेंसी, नई दिल्ली

दीपावली से पहले दिल्ली में राजनीतिक रैली को लेकर व्यापारिक संगठनों ने चिंता जताई है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को पत्र लिखकर एक नवंबर को रामलीला मैदान में प्रस्तावित पार्टी की विशाल रैली स्थगित करने का अनुरोध किया है। संगठन का कहना है कि रैली के कारण राजधानी के 20 प्रमुख बाजारों में करीब 10 हजार करोड़ से 12 हजार करोड़ रुपये तक का कारोबार प्रभावित हो सकता है। व्यापारियों ने आशंका जताई है कि रैली के चलते यातायात व्यवस्था प्रभावित होने और सुरक्षा प्रबंधों के कारण बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही कम हो सकती है।

सीटीआई के अनुसार, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की प्रस्तावित रैली ऐसे समय आयोजित की जा रही है, जब दिल्ली के बाजारों में दीपावली की खरीदारी चरम पर पहुंचने वाली है। धनतेरस छह नवंबर और दीपावली आठ नवंबर को है। ऐसे में एक नवंबर का दिन त्योहार से संबंधित



सामान की खरीदारी, माल की आपूर्ति और परिवहन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। व्यापारियों का कहना है कि इस दौरान बाजारों में ग्राहकों की संख्या अधिक रहती है और दुकानदार पूरे साल के कारोबार के बड़े हिस्से की उम्मीद इसी त्योहारी अवधि से करते हैं।

संगठन ने पत्र में कहा है कि रामलीला मैदान के आसपास रैली होने से मध्य दिल्ली और आसपास के प्रमुख बाजारों में यातायात प्रभावित हो सकता है। बड़ी संख्या में लोगों के जुटने से सड़कों पर जाम लगने और वाहनों की आवाजाही बाधित होने की आशंका है। इसका सीधा असर उन ग्राहकों पर पड़ सकता है, जो त्योहार की खरीदारी के लिए बाजार पहुंचना चाहते हैं। मालवाहक वाहनों को भी दुकानों तक सामान पहुंचाने में परेशानी हो सकती है।

व्यापारियों ने बताई आजीविका पर असर की आशंका

व्यापारिक संगठनों का कहना है कि दीपावली के दौरान केवल बड़े बाजार ही नहीं, बल्कि छोटी दुकानों, रेहड़ी-पटरी संचालकों, थोक विक्रेताओं और परिवहन से जुड़े लोगों का कारोबार भी बढ़ता है। यदि रैली के कारण बाजारों तक पहुंचने में लोगों को परेशानी होती है, तो इसका असर पूरे व्यापारिक तंत्र पर पड़ सकता है। व्यापारियों ने स्पष्ट किया है कि उन्हें किसी राजनीतिक कार्यक्रम से आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके आयोजन का समय ऐसा होना चाहिए, जिससे आम लोगों और कारोबारियों को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े। सीटीआई ने सोनिया गांधी से आग्रह किया है कि वह व्यापारियों की चिंताओं को देखते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करें। संगठन के अनुसार, रैली को दीपावली के बाद आयोजित करने से राजनीतिक कार्यक्रम भी हो सकेगा और व्यापारियों के त्योहारी कारोबार पर संभावित असर से भी बचा जा सकेगा।

दिल्ली में एक नवंबर से वाहनों की आवाजाही पर सख्ती

बीएस-छह मानक से कम वाहन प्रतिबंधित, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

एजेंसी, नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए यातायात पुलिस ने वाहनों के प्रवेश को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत एक नवंबर 2026 से दिल्ली में वाहनों की आवाजाही पर सख्ती की जाएगी। इसके तहत केवल निर्धारित उत्सर्जन मानकों को पूरा करने वाले बीएस-6, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा नियमों के तहत छूट प्राप्त आवश्यक श्रेणी के वाहन भी राजधानी में आ सकेंगे।

दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण का स्तर बढ़ने और हवा की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि वे दिल्ली की यात्रा करने से पहले अपने वाहन की पात्रता और उससे संबंधित दस्तावेजों की जांच कर लें। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को प्रवेश से रोका जा सकता है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े प्रावधानों का पालन करना सभी वाहन चालकों के लिए जरूरी होगा।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से



जारी एडवाइजरी के अनुसार, बीएस-6 उत्सर्जन मानक वाले वाहन, सीएनजी से चलने वाले वाहन और इलेक्ट्रिक वाहनों को राजधानी में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा नियमों के तहत छूट प्राप्त आवश्यक श्रेणी के वाहन भी प्रवेश कर सकेंगे। वाहन चालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका वाहन निर्धारित मानकों के अनुरूप हो और सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध हों।

प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) के बिना चलने वाले वाहनों पर भी सख्ती की जाएगी। जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नहीं होगा, उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही बीएस-6 मानकों के अनुरूप नहीं होने वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। नियमों का पालन नहीं करने वाली अंतरराज्यीय बसों को भी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

गैर जरूरी ट्रकों को पेरीफेरल एक्सप्रेसवे से गुजरना होगा

दिल्ली से होकर दूसरे राज्यों की ओर जाने वाले गैर जरूरी ट्रकों को राजधानी के भीतर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसे वाहनों को ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करना होगा। इससे दिल्ली की सड़कों पर भारी वाहनों का दबाव कम करने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। हालांकि, दिल्ली में सामान पहुंचाने वाले वाहनों और अन्य छूट प्राप्त श्रेणियों पर संबंधित नियम लागू होंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे एक नवंबर से लागू होने वाले प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं। वाहन की श्रेणी, उत्सर्जन मानक और पीयूसीसी की वैधता पहले ही जांच लें, ताकि रास्ते में किसी तरह की परेशानी न हो। यातायात संबंधी जानकारी और सहायता के लिए पुलिस हेल्पलाइन नंबर 011-25844444 और 1095 पर संपर्क किया जा सकता है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू किए जा रहे इन प्रतिबंधों का उद्देश्य दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार करना और सड़कों पर प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या कम करना है। खासकर सर्दियों में वाहनों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण की समस्या को गंभीर बना देता है। ऐसे में निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश मार्गों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे प्रतिबंधों से संबंधित जानकारी पहले ही प्राप्त कर लें और नियमों के अनुरूप ही यात्रा करें। किसी भी तरह की लापरवाही से न केवल यात्रा प्रभावित हो सकती है, बल्कि संबंधित वाहन के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकती है।

त्योहारी सीजन से पहले दिल्ली में अवैध पटाखों का बड़ा जखीरा बरामद, दस मामले हुए दर्ज

एजेंसी, नई दिल्ली

त्योहारों के मौसम को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने अवैध पटाखों की बिक्री, भंडारण और कब्जे के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में उत्तरी जिला पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर विभिन्न इलाकों से 1,073.426 किलोग्राम पटाखे जब्त किए हैं। पुलिस ने इस संबंध में 10 प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। यह अभियान भीड़भाड़ वाले बाजारों और रिहायशी क्षेत्रों में आगजनी की घटनाओं को रोकने तथा लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।

◆ **बाजारों और रिहायशी इलाकों में छापेमारी, पुलिस ने जब्त किए एक हजार किलो से अधिक पटाखे**



उत्तरी जिला पुलिस की टीमों ने लाहौरी गेट, बुराड़ी, कोतवाली, बाड़ा हिंदू राव और सब्जी मंडी थाना क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की। इनमें सबसे अधिक पटाखे सब्जी मंडी इलाके से बरामद किए गए। यहां तीन मामलों में गली मंदिर वाली, आर्य मंदिर के पास और पुल बंगश स्थित रोशनआरा रोड से कुल 622.88 किलोग्राम पटाखे जब्त किए गए इसी तरह बाड़ा हिंदू राव थाना क्षेत्र के महावीर बाजार से तीन मामलों में 178.50 किलोग्राम पटाखे बरामद हुए। कोतवाली थाना क्षेत्र में अंगूरी बाग फूल वाला रोड और चांदनी चौक स्थित मोती सिनेमा के पास से दो मामलों में 107.600 किलोग्राम पटाखे जब्त किए गए। लाहौरी गेट थाना क्षेत्र में सर शोभा सिंह पॉलीक्लीनिक के पास से 88.916 किलोग्राम और बुराड़ी थाना क्षेत्र के हिमगिरी स्थित गली नंबर 11 से 75.530 किलोग्राम पटाखे बरामद किए गए।

पुलिस ने सभी मामलों में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और विस्फोटक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। उत्तरी जिले की उपायुक्त पुलिस निहारिका भट्ट ने बताया कि भीड़भाड़ वाले बाजारों और रिहायशी इलाकों में पटाखों का अवैध भंडारण तथा असुरक्षित रखरखाव गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। इससे आग लगने और जान-माल के नुकसान की आशंका रहती है। पुलिस का उद्देश्य नियमों का पालन सुनिश्चित करना और किसी भी संभावित हादसे को रोकना है।

दिल्ली में बम धमकी देने वाला यूपीएससी अभ्यर्थी कानपुर से किया गिरफ्तार

एजेंसी, बाहरी दिल्ली। दिल्ली के मुखर्जी नगर में बम विस्फोट की धमकी देकर दहशत फैलाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 23 वर्षीय युवक यूपीएससी अभ्यर्थी है। उसने फोन पर खुद को पाकिस्तान के लाहौर स्थित एक संगठन से जुड़ा बताया था और दिल्ली में बम विस्फोट करने की धमकी दी थी। पुलिस की तकनीकी जांच और अंतरराज्यीय समन्वय से महज 48 घंटे में मामले का पर्दाफाश हो गया। आरोपी को कानपुर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, 27 अक्टूबर की रात इंद्रा विकास कॉलोनी में रहने वाले सिविल सेवा अभ्यर्थियों को एक अज्ञात लैंडलाइन नंबर से धमकी भरा फोन आया था। कॉल करने वाले ने दावा किया कि वह लाहौर स्थित एक संगठन से जुड़ा है। उसने दिल्ली में बम विस्फोट करने की धमकी देने के साथ कुछ राजनीतिक व्यक्तियों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की थीं। इस कॉल के बाद अभ्यर्थियों ने पुलिस को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की और 29 अक्टूबर को मुखर्जी नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। उत्तर-पश्चिम जिला पुलिस ने कॉल से जुड़े तकनीकी साक्ष्यों, डिजिटल फुटप्रिंट और अन्य जानकारियों का विश्लेषण किया। जांच के दौरान कॉल करने वाले की पहचान कानपुर निवासी 23 वर्षीय युवक के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस की एक टीम कानपुर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया।

◆ **मुखर्जी नगर में धमकी से मचा हड़कंप, पूर्व रूममेट को परेशान करने की थी साजिश**

जंतर-मंतर बनेगा इंडिया बिएनाले 2026 का प्रमुख केंद्र, सजेगी कला की महफिल

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली का ऐतिहासिक जंतर-मंतर अब विरोध प्रदर्शनों के बजाय कला, वास्तुकला और डिजाइन के बड़े आयोजन का प्रमुख केंद्र बनने जा रहा है। केंद्र सरकार ने इंडिया आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बिएनाले 2026 के प्रमुख स्थलों में जंतर-मंतर को शामिल किया है। संस्कृति मंत्रालय की परिकल्पना पर आयोजित यह कार्यक्रम चार दिसंबर 2026 से शुरू होकर 21 मार्च 2027 तक चलेगा। इसके माध्यम से देश-विदेश की कला और सांस्कृतिक विरासत को एक मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा।

बिएनाले के दौरान राजधानी के करीब एक दर्जन ऐतिहासिक स्मारकों और प्रमुख सांस्कृतिक स्थलों पर प्रदर्शनियां, कार्यक्रम और कला से जुड़े विभिन्न अनुभव प्रस्तुत किए जाएंगे। इनमें लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, अग्रसेन की बावली, हौज खास, लोधी गार्डन, सफदरजंग का मकबरा और फिरोजशाह कोटला शामिल हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा

◆ **दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों में 108 दिनों तक कला, संस्कृति और वास्तुकला की दिखेगी झलक**



और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जैसे संस्थान भी आयोजन का हिस्सा बनेंगे।

फ्रांस, इटली, हंगरी, स्विट्जरलैंड और श्रीलंका सहित नौ देश अब तक आयोजन में भागीदारी की पुष्टि कर चुके हैं। बिएनाले में भारत समेत 20 से अधिक देशों की कला, वास्तुकला और डिजाइन को प्रदर्शित करने की योजना है। इसका पहला संस्करण वर्ष 2023 में लाल किले में आयोजित किया गया था। इस बार आयोजन को अधिक व्यापक स्वरूप दिया जा रहा है। आयोजकों के अनुसार, 108 दिनों तक दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारक, संग्रहालय, कला दीर्घाएं और सार्वजनिक स्थल कला एवं संस्कृति से जुड़े संवाद के केंद्र बनेंगे।

जंतर-मंतर तीन दशक से अधिक समय तक दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के प्रमुख स्थलों में शामिल रहा है। संसद और महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों के निकट होने के कारण यहां प्रदर्शनों को लेकर लंबे समय से चिंताएं भी जताई जाती रही हैं। हाल ही में सरकार ने इसे प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित किए जाने संबंधी व्यवस्था रद्द कर दी थी। इसके कुछ ही दिनों बाद बिएनाले के प्रमुख आयोजन स्थलों में इसे शामिल करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में जंतर-मंतर का यह नया स्वरूप राजधानी के ऐतिहासिक स्थलों के सांस्कृतिक उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर लगा लंबा जाम

पटपड़गंज, विकास मार्ग और मंडावली में जलभराव से लोगों की आवाजाही प्रभावित

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर में बृहस्पतिवार रात से रुक-रुककर हो रही बारिश के कारण यमुनापार के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। शुक्रवार को भी रुक-रुककर वर्षा होने से सड़कों पर पानी जमा रहा और लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर वाहनों की लंबी कतारें लगने से जाम की स्थिति बन गई।

पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज, लक्ष्मी नगर के विकास मार्ग और मंडावली सहित कई इलाकों में बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया। इससे इन मार्गों से गुजरने वाले वाहन चालकों को धीमी गति से सफर करना पड़ा। कई जगहों पर जलभराव के कारण यातायात प्रभावित हुआ। दफ्तर और अन्य जरूरी कामों के लिए निकले लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में



बारिश से दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर लगा लंबा जाम।

दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी बारिश के बीच लंबा जाम लगने से वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई। एक्सप्रेसवे पर वाहनों की कतारें लगने के कारण यात्रियों को काफी देर तक जाम में फंसे रहना पड़ा। यमुनापार के अन्य प्रमुख मार्गों पर भी यातायात की रफ्तार धीमी रही। बारिश के कारण सड़कों पर पानी जमा होने से दोपहिया वाहन चालकों को विशेष परेशानी हुई। जलभराव वाले हिस्सों से गुजरते समय उन्हें सावधानी बरतनी पड़ी। वहीं, पैदल चलने वाले लोगों को भी सड़क पार करने और आवाजाही में दिक्कत हुई। बृहस्पतिवार रात से जारी बारिश ने एक बार फिर शहर की जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जल निकासी व्यवस्था पर उठे सवाल

बारिश के कारण कई इलाकों में लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई। खासकर सुबह और दोपहर के समय घर से निकलने वाले लोगों को जलभराव और जाम के चलते अतिरिक्त समय लगाना पड़ा। वाहन चालकों को सड़कों पर जमा पानी के बीच से गुजरना पड़ा, जबकि कुछ स्थानों पर धीमी रफ्तार के कारण वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिलीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान जलभराव की समस्या बार-बार सामने आती है। ऐसे में जल निकासी के पुख्ता इंतजाम किए जाने की जरूरत है। लगातार वर्षा के कारण निचले इलाकों में पानी जमा होने से लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है।

यमुना में तैराकी को लेकर मनोज तिवारी और रिजिजू आमने-सामने

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली में यमुना नदी की सफाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी के बीच भाजपा सांसद मनोज तिवारी का नदी में स्नान और तैराकी करने का वीडियो चर्चा में है। दिल्ली के पूर्व भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने यमुना में डुबकी लगाने के साथ आचमन भी किया। उनका यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मनोज तिवारी को यमुना में तैराकी प्रतियोगिता करने का प्रस्ताव दिया। रिजिजू ने लिखा कि क्या यमुना का पानी बेहतर होने पर दोनों के बीच तैराकी प्रतियोगिता हो सकती है? उनके इस जवाब के बाद मामला और चर्चा में आ गया है।

मकान में आग के दौरान गैस सिलेंडर विस्फोट, दमकलकर्मी अस्पताल में भर्ती

एजेंसी, नई दिल्ली

जहांगीरपुरी के ई-ब्लॉक में शुक्रवार को एक मकान में लगी आग बुझाने के दौरान गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। इसकी चपेट में आने से दमकलकर्मी अंकित झुलस गए। उन्हें उपचार के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस आग लगने के कारणों और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को जहांगीरपुरी के ई-ब्लॉक स्थित एक मकान में आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया।

दमकलकर्मी मकान में लगी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान मकान में रखे गैस सिलेंडर में अचानक विस्फोट हो गया। विस्फोट के कारण दमकलकर्मी अंकित झुलस गए। घटना के तुरंत बाद घायल दमकलकर्मी को उपचार के लिए ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया, जहां उन्हें भर्ती कराया गया है। आग बुझाने के दौरान सिलेंडर में हुए विस्फोट ने राहत और बचाव कार्य में जुटी टीम के सामने भी चुनौती खड़ी कर दी। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार घटना में दमकलकर्मी अंकित के घायल



होने की पुष्टि हुई है। इस मामले में एक और पहलू सामने आया है। बताया जा रहा है कि मकान में रहने वाले एक युवक ने घटना से पहले खुद को आग लगाने की धमकी दी थी।

हालांकि, युवक की धमकी और मकान में लगी आग के बीच क्या संबंध है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घटना के कारणों का पता लगाने के लिए सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है। यह भी जांच की जा रही है कि मकान में आग किन परिस्थितियों में लगी और गैस सिलेंडर में विस्फोट कैसे हुआ। युवक की ओर से दी गई कथित धमकी को भी जांच में शामिल किया गया है।

बेमौसम बारिश से दिल्ली में धान की फसल खेतों में बिछी, किसान मुआवजे की मांग पर अड़े

एजेंसी, नई दिल्ली

राजधानी दिल्ली और उससे सटे एनसीआर के ग्रामीण इलाकों में दो दिनों से हो रही बेमौसम बारिश ने किसानों की सालभर की मेहनत पर पानी फेर दिया है। लगातार वर्षा और खेतों में जलभराव के कारण कटाई के लिए तैयार धान की फसल जमीन पर बिछ गई है। वहीं, हाल ही में बोई गई सरसों की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। प्रभावित किसान दिल्ली सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं।

दिल्ली देहात में धान की खेती मुख्य रूप से उन्हीं इलाकों में होती है, जहां सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध है। यमुना नदी के किनारे बसे खादर क्षेत्र के गांवों के अलावा नजफगढ़ नाले के आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी धान की अच्छी पैदावार होती है। इन क्षेत्रों में इस बार किसानों को फसल से बेहतर उत्पादन की उम्मीद थी, लेकिन बारिश ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। बुराड़ी और अलीपुर सहित यमुना खादर क्षेत्र के गांवों में बारिश के कारण खेतों में खड़ी पकी धान की फसल गिर गई है। वहीं, ढांसा,



झटीकरा, कांगनहेड़ी और नानकहेड़ी जैसे गांवों में भी जलभराव से फसल प्रभावित हुई है। खेतों में पानी भरने के कारण धान की बालियों में दाने सड़ने लगे हैं। इससे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों पर असर पड़ने की आशंका है।

बेमौसम बारिश ने किसानों की बढ़ाई चिंता

इसके अलावा हाल ही में सरसों की बुवाई करने वाले किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। लगातार बारिश और खेतों में नमी के कारण सरसों के बीज सड़ने लगे हैं। इससे पौधों के अंकुरित होने की संभावना प्रभावित हो रही है और किसानों को दोबारा बुवाई करनी पड़ सकती है। किसानों का कहना है कि धान की फसल तैयार होने के समय बारिश होने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं, सरसों की फसल खराब होने से अगली पैदावार पर भी असर पड़ सकता है। प्रभावित किसानों ने दिल्ली सरकार से खेतों में हुए नुकसान का सर्वे करवाने और उचित मुआवजा देने की मांग की है, ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके।

पेशी अदालत ने अगली सुनवाई पर दोनों की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य की

आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 19 नवंबर को पेश होंगे राबड़ी-तेजस्वी

एजेंसी, नई दिल्ली

आईआरसीटीसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की वरिष्ठ नेता राबड़ी देवी और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने दोनों नेताओं को 19 नवंबर को उपस्थित रहने के लिए कहा है। इस दिन मामले में औपचारिक रूप से आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।



भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) से संबंधित इस मामले में अदालत की ओर से अगली तारीख पर दोनों की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य की गई है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें अगली सुनवाई के लिए निर्देश जारी किए। आज की सुनवाई में उन्हें मिली छूट के बाद अब 19 नवंबर को अदालत के समक्ष उपस्थित होना होगा। मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया न्यायिक कार्यवाही का महत्वपूर्ण चरण है। इस दौरान अदालत आरोपितों के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर औपचारिक रूप से विचार करेगी। इसके बाद मामले की आगे की सुनवाई और संबंधित कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख नेताओं में शामिल हैं। आईआरसीटीसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का नाम भी जुड़ा हुआ है। इस मामले की सुनवाई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही है। अदालत के ताजा निर्देश के बाद अब सभी की निगाहें 19 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर रहेंगी।

राउज एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई पर होगी अहम कार्रवाई

अगली सुनवाई में अदालत आरोप तय करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। इसके लिए राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी होगी। अदालत की इस कार्रवाई के दौरान मामले से जुड़े आरोपों पर औपचारिक रूप से विचार किया जाएगा। इसके बाद न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की सुनवाई का रास्ता साफ होगा। आईआरसीटीसी से जुड़े इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव का नाम भी शामिल है। मामले की सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही है। 30 अक्टूबर को हुई सुनवाई में दोनों नेताओं को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी गई थी, लेकिन अगली तारीख पर उन्हें अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। अब 19 नवंबर की सुनवाई को इस मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

न्यूज ब्रीफ

एलआईसी में महिला करियर एजेंट के 500 पदों पर भर्ती, 3 से 6 नवंबर तक होंगे साक्षात्कार

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की मंडी शाखा ने महिला करियर एजेंट के 500 पद जिला रोजगार कार्यालय को अधिसूचित किए हैं। जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने बताया कि इन पदों के लिए 3 से 6 नवंबर, 2026 तक साक्षात्कार आयोजित होंगे। उन्होंने बताया कि 3 नवंबर को नेरचौक, 4 नवंबर को जोगिंदर नगर, 5 नवंबर को बालीचौकी और 6 नवंबर को जिला रोजगार कार्यालय मंडी में सुबह 10:30 से दोपहर 2 बजे तक साक्षात्कार होंगे। इन पदों के लिए 18 से 70 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। 30 से 60 वर्ष की महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। चयनित अभ्यर्थियों को पहले वर्ष 7,000, दूसरे वर्ष 6,000 और तीसरे वर्ष 5,000 रुपए मासिक वजीफा मिलेगा। इसके अतिरिक्त कमीशन भी दिया जाएगा। इच्छुक महिलाएं शैक्षणिक प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, फोटो और रोजगार पंजीकरण पत्र लेकर पहुंचें। अधिक जानकारी के लिए 01905-235508 पर संपर्क करें।

विद्यार्थियों को बताए करियर के विभिन्न विकल्प



भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। जिला रोजगार कार्यालय व मॉडल करियर सेंटर मंडी की ओर से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय किलिंग में 'भविष्य सेतु कार्यक्रम' के तहत करियर काउंसलिंग व व्यावसायिक मार्गदर्शन शिविर आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों को रोजगार, स्वरोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने दसवीं और बारहवीं के बाद उपलब्ध करियर विकल्पों तथा सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं के बारे में बताया। उन्होंने विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सुमन भारती ने किशोरावस्था में शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के महत्व की जानकारी दी। कृषि विकास अधिकारी सोहन लाल ने कृषि और बागवानी में करियर विकल्प बताए। वहीं, पीएनबी के आदर्श राणा ने आरसेटी के निशुल्क स्वरोजगार प्रशिक्षण और बैंक ऋण सुविधाओं की जानकारी दी। विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश सैनी ने सभी विशेषज्ञों का आभार जताया।

कैंची मोड़ पर एचआरटीसी बस में 7.23 ग्राम चिट्टे के साथ मंडी का युवक गिरफ्तार



भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिलासपुर पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम ने कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर कैंची मोड़ के पास एचआरटीसी बस में सवार एक युवक से 7.23 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर नशीला पदार्थ जब्त कर लिया है। आरोपी की पहचान हितेंद्र (34) पुत्र बीरी सिंह निवासी गांव सांडला, तहसील सदर, जिला मंडी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम ने कैंची मोड़ पर नाकाबंदी के दौरान एचआरटीसी बस को जांच के लिए रोका था। सवारियों की तलाशी के दौरान युवक के कब्जे से चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस थाना स्वारघाट में 28 अक्तूबर 2026 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर नशे की खेप के स्रोत और सप्लाई नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है।

एसडीएम ने बाल गृह भरनाल और ढलवान बाजार का किया औचक निरीक्षण

भारतेन्दु संवाददाता, सरकाघाट। एसडीएम सरकाघाट राजेंद्र कुमार गौतम ने बाल गृह भरनाल का औचक निरीक्षण कर बच्चों को उपलब्ध करवाई जा रही शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने बच्चों को पौष्टिक भोजन, नियमित स्वास्थ्य जांच, बेहतर शिक्षा और खेलकूद की सुविधाएं देने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अध्ययन कक्ष, पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्ष, भोजनालय और शयन कक्ष का भी निरीक्षण किया। बाल गृह प्रभारी प्रेम सिंह ने संस्थान की व्यवस्थाओं की जानकारी दी। एसडीएम ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ढलवान में बच्चों से मुलाकात कर उन्हें पढ़ाई और जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया। दिवाली के मद्देनजर एसडीएम ने ढलवान बाजार में मिठाई की दुकानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और लाइसेंस जांचे। उन्होंने बताया कि मिठाइयों के नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए। दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए।

दिल्ली की महारैली में धर्मपुर से भाग लेंगे माकपा कार्यकर्ता : भूपेंद्र सिंह

भारतेन्दु संवाददाता, सरकाघाट। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी धर्मपुर व सरकाघाट लोकल कमेटी के सचिव भूपेंद्र सिंह ने कहा कि 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित इंडिया गठबंधन की महारैली में धर्मपुर क्षेत्र से माकपा कार्यकर्ता बढ़-चढ़कर भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं, संविधान और नागरिकों के मताधिकार की रक्षा के लिए सामूहिक आवाज उठाना जरूरी है। इंडिया गठबंधन की ओर से आयोजित इस रैली का उद्देश्य लोकतंत्र बचाने, कथित वोट चोरी के मुद्दे और निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता को लेकर आवाज उठाना है। भूपेंद्र सिंह ने बताया कि रैली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग भी उठाई जाएगी। उन्होंने धर्मपुर क्षेत्र के लोगों से रैली में भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र और संविधान से जुड़े मुद्दों पर जनभागीदारी आवश्यक है।

टीहरा स्कूल में सात दिवसीय एनएसएस शिविर का समापन, विद्यार्थियों ने सीखे समाजसेवा के गुर

भारतेन्दु संवाददाता, सरकाघाट। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टीहरा में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई की ओर से आयोजित सात दिवसीय विशेष शिविर का शुक्रवार को समापन हुआ। 24 से 30 अक्तूबर तक चले इस शिविर में विद्यार्थियों ने विभिन्न सामाजिक एवं रचनात्मक गतिविधियों में भाग लिया। शिविर का शुभारंभ टीहरा पंचायत प्रधान निर्मला देवी ने किया था। शिविर के दौरान स्वयंसेवियों ने प्रतिदिन प्रभात फेरी, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्ति जागरूकता गतिविधियों में हिस्सा लिया। इसके अलावा खेलकूद, भजन-संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने विद्यार्थियों को सामाजिक दायित्वों की जानकारी दी। एनएसएस के आदर्श वाक्य 'मैं नहीं, बल्कि आप' के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम अधिकारी प्रवीण राणा और महिला अधिकारी कुलवेश ठाकुर ने शिविर के सफल आयोजन में योगदान दिया। शिविर से विद्यार्थियों में सेवा भावना, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का संदेश दिया गया।

11 नवंबर से शुरू होगी धर्मपाल मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता, 32 टीमें लेंगी भाग



भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। अर्जुन खेल मैदान कोटली में स्व. धर्मपाल ठाकुर की स्मृति में आयोजित होने वाली धर्मपाल मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता इस वर्ष 11 से 22 नवंबर तक खेली जाएगी। प्रतियोगिता में 32 टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता के संस्थापक संजय ठाकुर ने बताया कि युवाओं को नशे से दूर रखने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता की विजेता टीम को 55,555 रुपए और उपविजेता को 33,333 रुपएका नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा बेस्ट बल्लेबाज, गेंदबाज और विकेटकीपर को 1,111 रुपए व ट्रॉफी तथा मैन ऑफ द सीरीज को 2,222 रुपए व ट्रॉफी मिलेगी। प्रतियोगिता केवल अर्की विधानसभा क्षेत्र की पंचायत स्तरीय टीमों के लिए होगी। सफेद लेदर बॉल से खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में प्रोफेशनल खिलाड़ी भाग नहीं ले सकेंगे। प्रवेश शुल्क 4,444 रुपए रखा गया है। इच्छुक टीमें 5 नवंबर तक आधार कार्ड

साढ़े तीन करोड़ के दावे से दुर्घटना तक, सवालों पर सवाल में उलझता दिखने लगा संस्थान

पहले संस्थान उपलब्धि का श्रेय लेने में आगे, अब सत्यापन और जवाबदेही में दिखा पीछे

सुरेंद्र कटोच, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। हमीरपुर स्थित बहुतकनीकी संस्थान में छात्र द्वारा तीसरी मंजिल से कूदने के बाद ड्रोन विकसित करने के मामले में जिस साढ़े तीन करोड़ की राशी का जिक्र किया जा रहा है, उसके सत्यापन करने या न कर पाने को लेकर अब संस्थान कथित सवालों के कटघरे में भी खड़ा होता दिखने लगा है, जब रक्षा अनुदान की उपलब्धि का प्रचार हुआ, तो संस्थान ने इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ने में देर नहीं लगाई।

फॉलोअप

सर्वेश ने डीआईओ को जवाब में पहले ही बताया कथित धोखाधड़ी का शिकार

सर्वेश ने पहले ही 27 अक्तूबर को डीआईओ को भेजे जवाब में खुद को कथित धोखाधड़ी का शिकार बताया है। उनका कहना है कि कुछ लोगों ने ऑनलाइन संपर्क कर उन्हें साढ़े तीन करोड़ रुपए का फर्जी स्वीकृति पत्र भेजा। दस्तावेजों को वास्तविक मानकर उन्होंने रुद्राएज एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की। डीआईओ के सत्यापन के बाद उन्होंने आईडीईएक्स.डीआईओ से जुड़े दावों और गतिविधियों को रोकने की बात कही तथा कथित स्वीकृति पत्र जांच के लिए भेजने की जानकारी दी।

वहीं, जब रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा नवाचार संगठन ने इस दावे की प्रामाणिकता पर जब सवाल खड़े कर ईमेल भेजा तो संस्थान के होश उड़ते दिखने लगे। संस्थान के सर्वेश शर्मा से जुड़ा यह प्रकरण अब केवल कथित फर्जी अनुदान पत्र का मामला नहीं, बल्कि संस्थान की कार्यप्रणाली और सत्यापन व्यवस्था की भी परीक्षा बन गया है। 28 अक्तूबर को दोपहर एक बजकर 10 मिनट 49 सेकंड पर डीआईओ के कार्यक्रम प्रबंधक अंशुल सिंह का ईमेल संस्थान को मिला। इसमें सर्वेश की शिकायत का हवाला देते हुए वेबसाइट पर प्रकाशित संबंधित खबरों और दावों को हटाने का अनुरोध किया गया। साथ ही मामले को हिमाचल सरकार और राज्यपाल के संज्ञान में लाने की बात कही गई। यह कोई सोशल मीडिया की टिप्पणी नहीं, बल्कि रक्षा नवाचार संगठन की ओर से संस्थान को भेजा गया आधिकारिक पत्राचार था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या संस्थान की जिम्मेदारी केवल उपलब्धियों का श्रेय लेने तक सीमित रह सकती है। डीआईओ का ईमेल आने के बाद संस्थान में आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोपहर के बाद सर्वेश तीसरी मंजिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।

सर्वेश की दुर्घटना के बाद संस्थान के प्रधानाचार्य की शिकायत पर साइबर ठगी का मामला जरूर दर्ज हुआ है, लेकिन यहां भी संस्थान की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। सवाल यह है कि जब संस्थान को 28 अक्तूबर को ही पूरे प्रकरण की जानकारी मिल गई थी, तो एफआईआर दर्ज करवाने में देरी क्यों हुई। हालांकि, घटना के दिन संस्थान ने पूरे मामले की जिम्मेदारी सर्वेश के सिर डालते हुए खुद को अनभिज्ञ बताया और ग्रांट से जुड़ी किसी भी पुष्टि से खुद को अलग कर लिया।

> **संस्थान** के प्रींसीपल चंद्र शेखर का कहना है कि सर्वेश ने रक्षा मंत्रालय का हबाला देकर किसी को इस प्रोजेक्ट के बारे नहीं बताता था। 28 अक्तूबर को डीआईओ की मेल संस्थान की आफिसियल ईमेल पर आई तो हमने मामले की गंभीरता को देखते हुए 29 को एफआईआर दर्ज करवाई है। 28 को हमने सर्वेश को सुबह 11 बजकर 20 मिनट पर बुलाया था उससे इस विषय पर थोड़ी बात हुई उसके बाद वह चला गया उस समय सब ठीक था, लेकिन दोपहर बाद यह दुर्घटना हो गई।

डीसी ने लुहणू क्रिकेट मैदान में अंडर-19 इंडियन वुमेन चैलेंजर कप का किया शुभारंभ



अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। लुहणू क्रिकेट मैदान में शुक्रवार को अंडर-19 इंडियन वुमेन चैलेंजर कप-2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर उपायुक्त बिलासपुर किरण भड़ाना ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की तथा बेल रिंगिंग सेरेमनी के माध्यम से प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया।

महिला क्रिकेट को प्रोत्साहन देने और बेटियों को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित इस प्रतियोगिता की थीम गुलाबी रखी गई है। प्रतियोगिता की टैगलाइन 'छोटे कदम, बड़े अरमान, बेटियां बनेंगी भारत की शान' रखी गई है, जो महिला सशक्तीकरण और खेलों में बेटियों की बढ़ती भागीदारी का संदेश देती है। इसी थीम के अनुरूप लुहणू क्रिकेट मैदान के प्रवेश द्वार सहित पूरे परिसर को गुलाबी रंग से सजाया गया है। इस अवसर पर डीसी ने कहा कि खेल बेटियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का सशक्त माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि बेटियां आज प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और क्षमता का परिचय दे रही हैं। ऐसे आयोजनों से ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों की प्रतिभाशाली लड़कियों को भी अपनी खेल प्रतिभा निखारने और आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिलते हैं। जिला क्रिकेट संघ के सचिव विशाल जगोता ने बताया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का उद्देश्य देश के दूरदराज क्षेत्रों में भी महिला क्रिकेट को प्रोत्साहित करना तथा अधिक से अधिक लड़कियों को क्रिकेट से जोड़ना है। इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों को भारतीय टीम में चयन का अवसर मिलेगा। चयनित खिलाड़ी आगामी एशिया कप और विश्व कप जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। प्रतियोगिता में इंडिया-ए, इंडिया-बी, इंडिया-सी और इंडिया-डी की टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 5 नवंबर को खेला जाएगा।

लोकतंत्र के हत्यारों को 'लोकतंत्र बचाओ' का नारा शोभा नहीं देता : देवेंद्र जग्गी

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। धर्मशाला के पूर्व महापौर देवेंद्र जग्गी ने भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ' रैली पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाली भाजपा को पहले अपने राजनीतिक आचरण और अतीत का जवाब देना चाहिए।



उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के हत्यारों को लोकतंत्र बचाने का नारा शोभा नहीं देता। जग्गी ने सवाल उठाया कि जब जंतर-मंतर पर छात्रों पर कथित रूप से लाठियां बरसाई जा रही थीं, तब भाजपा नेता कहां थे? उस समय छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थन में उनकी आवाज क्यों नहीं उठी? उन्होंने कहा कि लोकतंत्र केवल रैलियों और नारों तक सीमित नहीं है, बल्कि जनता के अधिकारों और जनादेश का सम्मान करना इसका वास्तविक अर्थ है। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवालों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि जब विपक्ष चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और वोट चोरी के मुद्दे उठाता है, तब भाजपा निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन करने के बजाय चुनाव आयोग के बचाव में खड़ी दिखाई देती है। पूर्व महापौर ने हालिया एमएलसी चुनावों का उल्लेख करते हुए कहा कि मतपत्रों से हुए मतदान में भाजपा को कई स्थानों पर हार का सामना करना पड़ा है।

प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में भी भाजपा की हार जनता के बदलते रुख का संकेत है। जग्गी ने कहा कि देश की जनता भाजपा की कथनी और करनी के अंतर को समझ चुकी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की आवाज का सम्मान होना चाहिए और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सवालों का जवाब पारदर्शी जांच के माध्यम से दिया जाना चाहिए।

बद्दी पुलिस ने भटोलीकलां में किया जागरूक

भारतेन्दु संवाददाता, बद्दी। हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार 26 अक्तूबर से 1 नवंबर 2026 तक मनाए जा रहे विजिलेंस अवेयरनेस सप्ताह के तहत बद्दी पुलिस का जन-जागरूकता अभियान जारी है। इसी कड़ी में पुलिस थाना बरोटीवाला की टीम ने ग्राम पंचायत भटोलीकलां में जागरूकता व्याख्यान आयोजित किया। इस दौरान उपस्थित लोगों को विजिलेंस अवेयरनेस सप्ताह के उद्देश्य और महत्व की जानकारी दी गई। पुलिस टीम ने लोगों को ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता के महत्व से अवगत करवाते हुए भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने दैनिक जीवन में नैतिक मूल्यों और ईमानदारी को प्राथमिकता देनी चाहिए। बद्दी पुलिस ने बताया कि भ्रष्टाचार के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने और समाज में नैतिक मूल्यों को मजबूत करने के उद्देश्य से इस तरह के कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे।

अर्की में अंडर-19 छात्र वर्ग की राज्य स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का शुभारंभ, मंडी ने तीन स्पर्धाओं में मारी बाजी



भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। अर्की में अंडर-19 छात्र वर्ग की राज्य स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का शुक्रवार को शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता के पहले दिन प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे विद्यार्थियों ने पांच सांस्कृतिक स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। दिनभर चली प्रतियोगिताओं के बाद परिणाम घोषित किए गए और विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया।

पहले दिन संस्कृत सुभाषितानि, संस्कृत गीतिका, शास्त्रीय गायन, सुगम संगीत और समूहगान प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। संस्कृत सुभाषितानि में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धुंदन (सोलन) ने प्रथम तथा राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अम्बोया (सिरमौर) ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। संस्कृत गीतिका में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ककीरा (चंबा) प्रथम और धुंदन स्कूल द्वितीय स्थान पर रहा। शास्त्रीय गायन प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जरोड़ (मंडी) ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि एचएपीएस विकासनगर (हमीरपुर) दूसरे स्थान पर रहा। सुगम संगीत में भी जरोड़ स्कूल ने बाजी मारी और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय आनी (कुल्लू) ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। समूहगान प्रतियोगिता में जरोड़ स्कूल प्रथम तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ककीरा (चंबा) द्वितीय स्थान पर रहा।

इस प्रकार मंडी जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जरोड़ ने पहले ही दिन शास्त्रीय गायन, सुगम संगीत और समूहगान सहित तीन प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। प्रतियोगिताओं के बाद आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त विशेष अतिथि भुवनेश्वर ठाकुर और भारतेंदु शर्मा ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में निरंतर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर पीएमश्री एससीवीटी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अर्की के प्रधानाचार्य हेमराज गौड़, एडीपीओ सोलन हेमराज सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। प्रतियोगिताओं के सफल संचालन के लिए संयुक्त निदेशक जगदीश चंद नेगी को प्रतियोगिता पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

पीएम-किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी होने पर मंडी जिला भाजपा किसान मोर्चा ने जताया पीएम मोदी का आभार

भारतेन्दु संवाददाता, जोगिंद्रनगर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी होने पर मंडी जिला भाजपा किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष शांति स्वरूप शर्मा, जिला महामंत्री नवीन गुलेरिया व सुरेंद्र ठाकुर तथा जिला मीडिया प्रभारी विनोद कुमार शर्मा ने संयुक्त बयान जारी कर केंद्र सरकार के कदम की सराहना की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। देश के 9.40 करोड़ किसानों को जारी 24वीं किस्त के साथ फरवरी 2019 से अब तक कुल 4.66 लाख करोड़ रुपये सीधे बैंक खातों में हस्तांतरित किए जा चुके हैं। हिमाचल के किसानों को भी 3600 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता मिली है। उन्होंने कहा कि यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए बड़ा आर्थिक सहारा बनी है। डीबीटी के माध्यम से राशि मिलने से पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है। इससे किसानों को बीज, खाद और कृषि उपकरण खरीदने में मदद मिल रही है। उन्होंने कांग्रेस पर किसानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार किसानों के हित में लगातार ठोस कदम उठा रही है।



बच्चों के सर्वांगीण विकास में वार्षिक समारोह निभाते हैं अहम भूमिका : अजय

भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। राजल। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला राजल में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया।



समारोह में एचआरटीसी उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय के अध्यापकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों को वार्षिक समारोह की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अजय वर्मा ने कहा कि वार्षिक समारोह विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए बेहतर मंच प्रदान करते हैं। शिक्षा के साथ सांस्कृतिक एवं अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ-साथ खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है, ताकि बच्चों को अपनी प्रतिभा निखारने के पर्याप्त अवसर मिल सकें। इससे पूर्व विद्यालय के प्रधानाचार्य विजय शर्मा ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने विद्यालय की शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियों तथा उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दी। समारोह में विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित अतिथियों और अभिभावकों का मन मोह लिया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि अजय वर्मा ने विद्यालय को 11 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने के साथ दो सोलर लाइटें और एक कंप्यूटर भी भेंट किया। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस सचिव नवनीत शर्मा, जिला परिषद सदस्य ईशांत चौधरी, प्रधान नीलम, प्रधान संजीव कुमार, प्रधान कुलदीप सिंह, उपप्रधान मदन लाल, पूर्व प्रधान बरियाम सिंह सहित विद्यालय के शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

सरकाघाट में रविवार को बिजली रहेगी बंद

भारतेन्दु संवाददाता, सरकाघाट। सरकाघाट में रविवार, 1 नवंबर को 11 केवी फीडर की मरम्मत के चलते सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता निशांत शर्मा ने बताया कि इस दौरान लोअर बाजार, अपर बाजार, डबरोग, बेहद, अस्पताल, कुनालग, जमसाई, रामनगर, लाका और कराड़ी सहित आसपास के क्षेत्र प्रभावित होंगे। उन्होंने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील करते हुए आवश्यक कार्य पहले निपटाने का आग्रह किया है। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।

कांगड़ा में बुजुर्ग महिला से एटीएम कार्ड बदलकर 38 हजार रुपए ठगे

भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। कांगड़ा के वीरता गांव में पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम बूथ में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। शातिर युवक ने मदद करने के बहाने एक बुजुर्ग महिला का एटीएम कार्ड बदलकर उसके खाते से 38 हजार रुपये निकाल लिए। पूरी वारदात एटीएम बूथ में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार, कांगड़ा बस अड्डे के समीप पेट्रोल पंप के सामने स्थित पीएनबी के एटीएम में बुजुर्ग महिला पैसे निकालने पहुंची थी। इसी दौरान बाहर मौजूद एक युवक ने मदद करने के बहाने उसका एटीएम कार्ड बदल लिया। इसके बाद आरोपी ने खाते से 38 हजार रुपए निकाल लिए। ठगी का पता चलने पर महिला ने तुरंत पंजाब नेशनल बैंक और पुलिस को सूचना दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत युवाओं को मिलेगा रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण



भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के तत्वावधान में जिला स्तरीय कौशल समिति की बैठक अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर चर्चा की गई। एडीसी ने बताया कि योजना के तहत 31 मार्च, 2027 तक हिमाचल प्रदेश में 2,400 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। इनमें 1,080 युवाओं को अल्पकालिक और 1,320 युवाओं को दीर्घकालिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पर्यटन, आतिथ्य सत्कार, हरित ऊर्जा, जल प्रबंधन, प्लंबिंग और स्वास्थ्य सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्राकृतिक एवं जैविक खेती को भी योजना में शामिल करने का सुझाव दिया गया। उन्होंने संबंधित विभागों को पात्र युवाओं की पहचान कर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंचाने तथा आपसी समन्वय से निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

दिल्ली की महारैली में हमीरपुर से भी शामिल होंगे हजारों लोग : सुनील

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली कांग्रेस की महारैली में हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आम लोग भाग लेंगे। यह जानकारी ब्लॉक कांग्रेस हमीरपुर के अध्यक्ष सुनील कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि महारैली में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पार्टी की ओर से विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू भी लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क कर रहे हैं, ताकि हमीरपुर से अधिक से अधिक लोग दिल्ली पहुंच सकें। सुनील ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली और मतदाता सूचियों से नाम हटाए जाने के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने यह महारैली आयोजित की है। उन्होंने दावा किया कि इन मुद्दों पर जनता में नाराजगी है और राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाए जा रहे आंदोलन को समर्थन मिल रहा है।

अच्छा नागरिक ही रख सकता है देश के मजबूत भविष्य की नींव : डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा



भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। न्यू गुरुकुल पब्लिक स्कूल, गोपाल नगर में आज सात दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) शिविर का शुभारंभ वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा ने रिबन काटकर किया।

इस शिविर में लगभग सौ विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के प्राचार्य रविंद्र पुरी एवं स्टाफ सदस्यों ने डॉ. वर्मा

न्यूज ब्रीफ

निर्धन बच्चों की मदद के लिए नगरोटा बगवां कॉलेज में दिवाली सामग्री की बिक्री शुरू



भारतेन्दु संवाददाता, नगरोटा बगवां। राजकीय महाविद्यालय नगरोटा बगवां में 'अर्न व्हाइल यू लर्न' योजना के तहत विद्यार्थियों द्वारा तैयार की गई दिवाली पूजन व घर की सजावट की सामग्री की बिक्री शुरू हो गई है। इस पहल के तहत विद्यार्थियों ने आकर्षक व सुगंधित मोमबत्तियों सहित विभिन्न सजावटी वस्तुएं तैयार की हैं। बिक्री से प्राप्त धनराशि निर्धन व जरूरतमंद बच्चों की सहायता पर खर्च की जाएगी। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र सोनी के मार्गदर्शन तथा वनस्पति विज्ञान विभाग की सहायक आचार्य डॉ. शिखा के निर्देशन में आयोजित इस गतिविधि में विद्यार्थियों ने निर्माण, सजावट, पैकेजिंग और बिक्री में भाग लिया। इससे उन्हें रचनात्मकता, विपणन और स्वरोजगार के व्यावहारिक अनुभव मिल रहे हैं। कृति, मुस्कान, ऐश्वर्या, तन्वी और मनदीप सहित अन्य विद्यार्थियों ने इसमें योगदान दिया। प्राचार्य ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियां विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता, उद्यमशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करती हैं।

बद्दी के ऋषभ ने राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में जीते दो गोल्ड मेडल



भारतेन्दु संवाददाता, बद्दी। बद्दी के होनहार एथलीट ऋषभ गुप्ता ने धर्मशाला में आयोजित 67वीं अंडर-19 राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए दो स्वर्ण पदक हासिल किए। 26 से 28 अक्तूबर तक आयोजित प्रतियोगिता में ऋषभ ने डिस्कस थ्रो और शॉटपुट में प्रथम स्थान प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। ऋषभ ने डिस्कस थ्रो में 37.60 मीटर चक्का फेंककर तथा शॉटपुट में 14.64 मीटर गोला फेंककर गोल्ड मेडल जीता। इससे पहले वह जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भी दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक हासिल कर चुका है। ऋषभ के पिता राकेश गुप्ता ने इस सफलता का श्रेय बेटे की मेहनत और नियमित अभ्यास को दिया। वहीं ऋषभ ने अपनी उपलब्धि का श्रेय पिता राकेश गुप्ता और दादी माया गुप्ता को दिया, जिन्होंने उसे अभ्यास के लिए लगातार प्रेरित किया, अब ऋषभ जनवरी में होने वाली राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगा। उसका लक्ष्य वहां भी स्वर्ण पदक जीतना है।

अर्की के विभिन्न क्षेत्रों में 31 अक्तूबर से 5 नवंबर तक बिजली रहेगी बंद

भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। बिजली उपमंडल अर्की के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में 31 अक्तूबर से 5 नवंबर तक अलग-अलग दिनों में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। बिजली विभाग द्वारा 11 केवी डुमैहर और 33 केवी अर्की फीडर की मरम्मत तथा बिजली लाइनों के आसपास पेड़ों की टहनियों की कटाई के लिए शटडाउन निर्धारित किया गया है। विभाग के अनुसार 31 अक्तूबर को पपलोटा, स्थारी, देवरा, जमना, कोट, सुन्नी, जघाना, बलेरा, जयनगर और भूमति सहित आसपास के क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी। 1 नवंबर को सानन, शिवघाटी, सरोग सेरी और बखालग प्रभावित रहेंगे। वहीं, 2, 4 और 5 नवंबर को अर्की, बातल, मंझयाट, मांजू, बथालंग, गलोग, शालाघाट, कोलका, घलोथ, घुमारी और दधोगी में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता ई. नीरज कुमार कतना ने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है। उन्होंने बताया कि कार्य अधूरा रहने पर इसे अगले दिन पूरा किया जाएगा।

कुल्लू अस्पताल में नेपाली मूल के व्यक्ति की मौत, पहचान के लिए पुलिस ने मांगी मदद

भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। जिला कुल्लू के सरवरी क्षेत्र में बीमार अवस्था में मिले नेपाली मूल के करीब 70 वर्षीय व्यक्ति की क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान अमर पुत्र राम दास के रूप में हुई है, लेकिन उसके परिजनों और कानूनी वारिसों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जानकारी के अनुसार, व्यक्ति 12 अक्तूबर को सरवरी में बीमार अवस्था में मिला था। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां 29 अक्तूबर को उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में सुरक्षित रखा है। मृतक की उम्र करीब 70 वर्ष, कद 5 फीट 6 इंच, रंग सांवला और चेहरा गोल है। जिला पुलिस कुल्लू ने आम जनता से मृतक की पहचान और परिजनों का पता लगाने में सहयोग की अपील की है। किसी भी जानकारी के लिए पुलिस थाना कुल्लू के नंबर 01902-222775 पर संपर्क किया जा सकता है।

बच्चों को बाल अधिकारों, पॉक्सो एक्ट और साइबर सुरक्षा के प्रति किया जागरूक



भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। साई स्टार सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गांधी नगर कुल्लू में 'सुरक्षित बचपन अभियान' के तहत एकदिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपनिदेशक उच्च शिक्षा (सेकेंडरी) कुल्लू और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशानुसार आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को बाल अधिकारों, पॉक्सो एक्ट, साइबर सुरक्षा और सुरक्षित-असुरक्षित स्पर्श की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मुख्यातिथि जिला व सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष नरेश कुमार उपस्थित रहे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनमोहन सिंह सहित न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और चाइल्ड हेल्पलाइन के प्रतिनिधियों ने बच्चों का मार्गदर्शन किया। विद्यार्थियों को कानूनी सहायता हेल्पलाइन 15100 और साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 की जानकारी दी गई। वहीं छोटे बच्चों को गुड टच-बैड टच तथा वरिष्ठ विद्यार्थियों को साइबर बुलिंग और ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान चित्रकला, निबंध, स्लोगन लेखन और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। प्रधानाचार्य अंजना ठाकुर ने सभी अतिथियों का आभार जताया।

जनगणना-2027 के लिए गांवों और शहरों की सुविधाओं का बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड



भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जनगणना-2027 के तहत जिला बिलासपुर के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं और संसाधनों का विस्तृत डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसके लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के बैठक कक्ष में श्री नयना देवी जी और सदर उपमंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का शुभारंभ जिला राजस्व अधिकारी नीलाक्ष शर्मा ने किया। प्रशिक्षण में अधिकारियों और कर्मचारियों को आंकड़ों के संग्रहण, निर्धारित प्रारूप में जानकारी दर्ज करने तथा मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन प्रविष्टि करने की प्रक्रिया समझाई गई। इस अभियान के तहत प्रत्येक राजस्व गांव और नगर निकाय में बिजली, सड़क, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, बैंकिंग सेवाएं, पेयजल, आंगनबाड़ी और कृषि सुविधाओं से संबंधित जानकारी जुटाई जाएगी। नीलाक्ष शर्मा ने कहा कि जनगणना के आंकड़े विकास योजनाओं और नीतियों के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार हैं। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सटीक और विश्वसनीय आंकड़े निर्धारित समयसीमा में दर्ज करने के निर्देश दिए।

मतपत्रों से हुए चुनावों में भी कांग्रेस को हार अब किसे दोष देंगे राहुल गांधी : डॉ. राजीव

धर्मशाला से लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ अभियान का शंखनाद

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। भाजपा ने धर्मशाला में 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' अभियान के अंतर्गत पदयात्रा आयोजित कर प्रदेशव्यापी जनजागरूकता अभियान का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर मुख्य वक्ता कांगड़ा-चंबा लोकसभा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन की राजनीतिक कार्यशैली पर सवाल उठाए तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जिम्मेदार आचरण की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ. राजीव भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को निर्वाचन आयोग और चुनाव प्रणाली पर आरोप लगाने से पहले अपने चुनावी प्रदर्शन का आत्ममंथन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आते हैं, तो पार्टी निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाती, लेकिन प्रतिकूल परिणाम



आने पर मतदाता सूची और मतदान प्रणाली को कठघरे में खड़ा करने लगती है। उन्होंने कहा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र के विधान परिषद शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में मतपत्रों से हुए चुनावों के परिणाम भी कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का विषय हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भाजपा-जद(एस) गठबंधन ने चारों सीटों पर जीत दर्ज की। डॉ. भारद्वाज ने कहा कि लोकतंत्र में मतपत्र हो अथवा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मतदाताओं के निर्णय का सम्मान करना सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। यदि किसी चुनावी प्रक्रिया को लेकर शिकायत है तो उसे तथ्यों और प्रमाणों के साथ संवैधानिक संस्थाओं के समक्ष रखा जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस की प्रस्तावित 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राजनीतिक नारों के साथ-साथ कांग्रेस नेतृत्व को चुनावी पराजयों और अपनी संगठनात्मक स्थिति पर भी जवाब देना चाहिए।

धर्मशाला से शुरू हुआ प्रदेशव्यापी अभियान

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा कि धर्मशाला से प्रारंभ हुआ 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' अभियान प्रदेश के अन्य क्षेत्रों तक पहुंचेगा। इसके माध्यम से जनता के बीच संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रदेश सरकार की जवाबदेही से जुड़े विषय उठाए जाएंगे। परमार ने कहा कि कांग्रेस को निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठाने के साथ-साथ अपने चुनावी वादों की स्थिति भी स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश की जनता को सरकार के कार्यकाल का पूरा लेखा-जोखा जानने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि भाजपा जनहित के मुद्दों पर जनता से संवाद जारी रखेगी और प्रदेश सरकार से उसके चुनावी वादों तथा निर्णयों पर तथ्यात्मक जवाब मांगेगी।

हरियाणा के मंत्री कृष्ण कुमार वेदी पहुंचे कुल्लू, वाल्मीकि समाज से की मुलाकात



धनेश गौतम, भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार वेदी अपने कुल्लू दौरे के दौरान वाल्मीकि समाज के लोगों से रूबरू हुए।

इस अवसर पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। मंत्री ने मंदिर में माथा टेककर आशीर्वाद लिया और समाज के लोगों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं, मांगों तथा आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक स्थिति को लेकर विस्तार से चर्चा की। मंत्री कृष्ण कुमार वेदी ने कहा कि कुल्लू दौरे का उनका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव को देखना और यहां रह रहे वाल्मीकि समाज के अपने भाइयों से मिलकर उनका कुशलक्षेम जानना था। इस दौरान समाज के प्रतिनिधियों और स्थानीय पार्षदों ने उन्हें क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। बैठक में स्थानीय लोगों ने भूमि से जुड़ी मांग को प्रमुखता से उठाया। बताया गया कि कुछ लोग दो विश्व भूमि की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनके पास जमीन से संबंधित पुख्ता दस्तावेज और प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। इस पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि समाज की ओर से सौंपे गए मांग-पत्र को वह देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री तक पहुंचाएंगे, ताकि इस मामले को उचित स्तर पर उठाया जा सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार समाज की इन समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। मंत्री ने कहा कि किसी भी प्रदेश और देश के विकास में समाज के प्रत्येक वर्ग की अहम भूमिका होती है। मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी, इंजीनियर और डॉक्टर के साथ-साथ वाल्मीकि समाज का भी राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति के योगदान और सम्मान को समान रूप से महत्व दिया जाना चाहिए। इस अवसर पर मंत्री कृष्ण कुमार वेदी ने सभी प्रदेशवासियों को अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा तथा आगामी त्योहारों की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

एंटी चिट्टा अभियान: नूरपुर पुलिस ने जब्त की 48 .30 लाख रुपए की संपत्ति

भारतेन्दु संवाददाता, इंदौरा। एंटी चिट्टा अभियान के तहत नूरपुर पुलिस ने नशा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 48.30 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है।

पुलिस थाना डमटाल के अंतर्गत आरोपी शमशेर सिंह पुत्र गुरदियाल सिंह निवासी वार्ड नंबर-9, डमटाल की संपत्ति एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त की गई है। एएसपी धर्म चंद वर्मा ने बताया कि सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, नई दिल्ली ने 22 अक्तूबर को एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 68-I(1) और 68-I(3) के तहत जब्ती आदेश जारी किया था। इसके तहत गांव चन्नी, तहसील इंदौरा स्थित आरोपी के दो मंजिला मकान, जिसमें बेसमेंट भी शामिल है, का मूल्य 45,90,557 रुपए निर्धारित किया गया है। इसके अलावा नशे के अवैध कारोबार से अर्जित 2,40,440 रुपए की नकदी भी जब्त की गई है। कुल जब्त संपत्ति का मूल्य 48,30,997



रुपए है। पुलिस ने 29 अक्तूबर 2026 को आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68- के तहत आदेश तामील करवाया। इसके तहत उसे जब्त संपत्ति का कब्जा संबंधित विभाग को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का पालन नहीं करने पर सक्षम प्राधिकारी कानूनी कार्रवाई कर संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर सकता है। एएसपी ने कहा कि एंटी चिट्टा अभियान के तहत पुलिस नशा तस्करों की गिरफ्तारी के साथ उनकी अवैध संपत्तियों की पहचान और जब्ती भी कर रही है। इसका उद्देश्य नशा तस्करी के आर्थिक नेटवर्क को कमजोर करना और अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति पर कानूनी कार्रवाई करना है।

जवाहर नवोदय विद्यालय की छठी कक्षा की प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी

भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। जवाहर नवोदय विद्यालय की छठी कक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली चयन परीक्षा-2027 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए प्रवेश परीक्षा 28 नवंबर, 2026 को आयोजित की जाएगी। जवाहर नवोदय विद्यालय बंदरोल के प्रधानाचार्य प्रताप सिंह ने बताया कि परीक्षा के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की आधिकारिक वेबसाइट या सीधे एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक का उपयोग कर सकते हैं। प्रधानाचार्य ने अभ्यर्थियों से समय रहते अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड करने तथा उसमें दर्ज परीक्षा संबंधी जानकारी जांचने की अपील की है।

मेधावी छात्र के सम्मान पर राजनीति कर रहे कांग्रेस विधायक सुरेश कुमार : राकेश

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कांग्रेस विधायक सुरेश कुमार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सुरेश कुमार झूठ की राजनीति करने के आदी हो चुके हैं।

राजनीतिक लाभ लेने और अपने नेताओं को खुश करने की होड़ में वह अब मेधावी विद्यार्थियों की उपलब्धियों और उनके सम्मान को भी राजनीतिक विवाद का विषय बनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। राकेश ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज के मेधावी छात्र सर्वेश शर्मा के मामले में विधायक सुरेश कुमार ने जिस प्रकार का भ्रामक बयान दिया है, वह उनकी राजनीतिक हताशा और असुरक्षा की भावना को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सर्वेश शर्मा को केवल उनकी मेधा, प्रतिभा और उपलब्धि के लिए सम्मानित किया था। यह सम्मान उसी प्रकार था, जिस प्रकार मुख्यमंत्री



सुखविंद्र सिंह सुक्खू, राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और स्वयं विधायक सुरेश कुमार ने भी विद्यार्थी की उपलब्धि पर उसे सम्मानित किया था।

राकेश ठाकुर ने स्पष्ट किया कि सांसद अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा सर्वेश शर्मा को 3.5 करोड़ रुपए का बजट उनकी सिफारिश पर जारी होने संबंधी कोई बात नहीं कही गई थी। इसके बावजूद विधायक सुरेश कुमार द्वारा इस सम्मान को बजट जारी करवाने की सिफारिश से जोड़कर प्रस्तुत करना तथ्यों को तोड़-मरोड़कर जनता को गुमराह करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि सर्वेश शर्मा के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति करना विधायक सुरेश कुमार की संकीर्ण राजनीतिक सोच को दर्शाता है। एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की उपलब्धि पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर गर्व महसूस किया जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस विधायक ने विद्यार्थी के सम्मान को भी राजनीतिक हथकंडा बना दिया। राकेश ठाकुर ने कहा कि यदि सर्वेश शर्मा के साथ किसी प्रकार का अन्याय हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच करवाना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रदेश सरकार के अधीन संचालित संस्थान है और उससे सम्बन्धित किसी भी अनियमितता की जांच करवाने का अधिकार एवं दायित्व राज्य सरकार का है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना सरकार की प्राथमिकता: रोहित

विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के 21वें स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता की



भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गत चार वर्षों में हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए नए सोपान हासिल किए हैं। वह शुक्रवार को बल्ह विधानसभा क्षेत्र के बगला में विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के 21वें स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में हिमाचल प्रदेश वर्ष 2021 में देशभर में 21वें स्थान पर था, जबकि अब पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। एनएएस-2025 में प्रदेश ने देशभर में प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में भी हिमाचल 13वें से छठे स्थान पर पहुंचा है। उन्होंने कहा कि 99.55 प्रतिशत साक्षरता दर के साथ प्रदेश ने पूर्ण साक्षर राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के साथ विद्यार्थियों और शिक्षकों को विदेशों में शैक्षणिक भ्रमण के अवसर भी उपलब्ध करवा रही है, ताकि वे आधुनिक शिक्षण पद्धतियों और तकनीकों से परिचित हो सकें। रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्ति के चरित्र निर्माण और समाज के विकास का आधार है। शिक्षण संस्थानों को विद्यार्थियों में अनुशासन, नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करनी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से बड़े लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने तथा माता-पिता और शिक्षकों का सम्मान करने का आह्वान किया।

उन्होंने विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि संस्थान को नैक से मान्यता मिलना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस अवसर पर उन्होंने संस्थान के प्रस्तावित स्कूल भवन की आधारशिला रखी तथा परिसर में पौधारोपण भी किया। विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। समारोह में पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव सोहन लाल ठाकुर, जल प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष शशि शर्मा, एसडीएम बल्ह स्मृतिका नेगी, संस्थान के चेयरमैन गौरव मारवाह, चेयरपर्सन कविता मारवाह, प्रधानाचार्य डॉ. दीप्ति सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित रहे।

केलांग में रैंप परियोजना के तहत स्टेकहोल्डर कॉन्क्लेव आयोजित, 40 उद्यमियों ने लिया भाग



भारतेन्दु संवाददाता, केलांग। उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से रैंप परियोजना के तहत केलांग में एकदिवसीय स्टेकहोल्डर कॉन्क्लेव आयोजित किया गया।

इसमें जिले के 40 उद्यमियों एवं विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सरकारी योजनाओं, वित्तीय सहायता और व्यवसाय विकास के अवसरों की जानकारी देना रहा। कार्यक्रम में जिला उद्योग केंद्र लाहौल-स्पीति के प्रबंधक सोमेश शर्मा तथा भारतीय स्टेट बैंक के लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सुनील मुख्यातिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने उद्यमियों को सरकारी योजनाओं और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसका संचालन नताशा कटोच ने किया। उन्होंने योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को मिलने वाले कौशल प्रशिक्षण, वजीफे, 15 हजार रुपए तक के टूलकिट प्रोत्साहन और रियायती ब्याज पर ऋण की जानकारी दी। इसके अतिरिक्त उद्यमियों को वित्तीय सहायता, बैंकिंग सुविधाओं और व्यवसाय विस्तार के विकल्पों से अवगत करवाया गया। कार्यक्रम में सतर्कता और साइबर सुरक्षा को लेकर शपथ भी दिलाई गई। कॉन्क्लेव का उद्देश्य स्थानीय उद्यमियों और कारीगरों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर क्षेत्र में स्वरोजगार, आर्थिक सशक्तीकरण और एमएसएमई क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना रहा।

निवेदिता नेगी ने संभाला उपायुक्त लाहौल-स्पीति का कार्यभार

भारतेन्दु संवाददाता, केलांग। आईएएस अधिकारी निवेदिता नेगी ने शुक्रवार को उपायुक्त लाहौल-स्पीति के रूप में कार्यभार संभाल लिया। जिला मुख्यालय केलांग पहुंचने पर जिला प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। कार्यभार



ग्रहण करने के बाद उन्होंने जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले की भौगोलिक परिस्थितियों, विभागीय कार्यप्रणाली और विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। निवेदिता नेगी ने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध पहुंचाना और आम जनता की समस्याओं का समाधान करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने जिले के समग्र विकास के लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय और आपसी सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए विकासात्मक गतिविधियों में तेजी लाने का आह्वान किया।

लंबित बिजली बिलों का समय पर भुगतान करें उपभोक्ता : नितिन

भारतेन्दु संवाददाता, सरकाघाट। विद्युत उपमंडल भांबला ने उपभोक्ताओं से लंबित बिजली बिलों का शीघ्र भुगतान करने की अपील की है।

सहायक अभियंता नितिन चंदेल ने कहा कि बिल जमा नहीं करवाने वाले उपभोक्ताओं को डिफॉल्टर नोटिस जारी किए जाएंगे। इसके बावजूद भुगतान न करने पर बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं ने पिछले माह के बिल जमा नहीं करवाए हैं, वे जल्द भुगतान सुनिश्चित करें। कनेक्शन कटने के बाद दोबारा जुड़वाने के लिए 250 या 500 रुपये आरसीओ फीस भी देनी पड़ सकती है। उन्होंने उपभोक्ताओं से हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की वेबसाइट, गूगल पे, पेटीएम अथवा विद्युत उपमंडल भांबला के कार्यालय में बिल जमा करवाने का आग्रह किया, ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके।

विद्यार्थियों को बाल अधिकारों एवं संरक्षण कानूनों के प्रति किया जागरूक

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला के दिशा-निर्देशों के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर की ओर से 'सुरक्षित बचपन अभियान' के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिलासपुर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। 26 से 31 अक्तूबर तक चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों को बाल अधिकारों, संरक्षण कानूनों और बाल शोषण की रोकथाम के प्रति जागरूक करना है।

कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष ज्योत्सना सुमंत डडवाल विशेष रूप से उपस्थित रहीं। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने और सर्वांगीण विकास के समान अवसर मिलने का अधिकार है। बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार के शोषण, उत्पीड़न या दुर्व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाने और जरूरत पड़ने पर



संबंधित अधिकारियों से सहायता लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को बाल विवाह निषेध अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) तथा बाल एवं किशोर श्रम निषेध कानूनों की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके अलावा बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा उपायों और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया। न्यायिक अधिकारियों ने कहा कि बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाने में अभिभावकों, शिक्षकों और समाज के प्रत्येक व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी को मिलकर बच्चों के लिए सुरक्षित और सकारात्मक माहौल तैयार करना चाहिए। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नविश भारद्वाज तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश-सह-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रतीक गुप्ता भी उपस्थित रहे।

बच्चों को व्यक्तिगत सुरक्षा और कानूनी अधिकारों के प्रति किया जागरूक

भारतेन्दु संवाददाता, सरकाघाट। लॉर्ड्स कॉन्वेंट स्कूल सरकाघाट में 'सुरक्षित बचपन, सशक्त भारत' अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को बाल अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा और सुरक्षित बचपन के महत्व के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम में सिविल जज-कम-ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मीनाक्षी ठाकुर, अधिवक्ता दिनेश तथा अधिवक्ता सोनिया ने विशेष रूप से शिरकत की। उन्होंने विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वक्ताओं ने कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना सुरक्षित एवं सशक्त समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों को आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। साथ ही किसी भी अनुचित परिस्थिति में बिना झिझक अभिभावकों, शिक्षकों या विश्वसनीय व्यक्ति से सहायता लेने का संदेश दिया। अंत में विद्यालय प्रबंधन ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया।

लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए एक नवंबर को दिल्ली में जुटेंगे कांग्रेसी

- रामलीला मैदान में कांग्रेस की हुंकार, हिमाचल से कार्यकर्ताओं को

एंड्रिया बोटेज का खूबसूरत अंदाज

कनाडा। एंड्रिया बोटेज एक कनाडाई शतरंज खिलाड़ी, कंटेंट क्रिएटर, डीजे और ट्विच स्ट्रीमर हैं। वह चैंपियन शतरंज खिलाड़ी एलेक्जेंड्रा बोटेज की बहन भी हैं।



न्यूजीलैंड ने भारत को 87 रन से हराया

259 रन का पीछा करते हुए नौ विकेट पर 172 रन ही बना सकी भारतीय टीम

एजेंसी, ऑकलैंड

ग्लेन फिलिप्स के तूफानी शतक और माइकल ब्रेसवेल की आक्रामक अर्धशतकीय पारी के दम पर न्यूजीलैंड ने चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 87 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड के 259 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 172 रन पर सिमट गई। हालांकि इस हार के बावजूद भारत पांच मैचों की श्रृंखला में 3-1 से आगे है।

260 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। जैकब डफी ने पहले ही ओवर में संजू सैमसन को चार रन और ईशान किशन को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने 15 गेंदों में 27 रन बनाए। उन्होंने तीन चौके और एक छक्का लगाया।

मैथ्यू फिशर ने उन्हें पांचवें ओवर में आउट कर दिया। श्रेयस अय्यर ने 11 गेंदों में 22 रन की तेज पारी खेली। उनकी पारी में चार चौके शामिल रहे, लेकिन छठे ओवर में एडम मिल्ने ने उन्हें बोल्ड कर दिया। पावरप्ले के छह ओवर के बाद भारत का स्कोर चार विकेट पर 61 रन था। इसके बाद नमन धीर और तिलक वर्मा ने पारी को संभालने की कोशिश की। नमन ने 13 गेंदों में 28 रन बनाए, जिसमें दो चौके और दो छक्के शामिल थे। डफी ने 12वें ओवर में उन्हें आउट किया। डेरिल मिचेल और नाथन स्मिथ ने मिलकर बाउंड्री के पास उनका कैच पकड़ा। नमन के अलावा नितीश रेड्डी ने भी 10 गेंदों पर 2 छक्कों की बदौलत 21 रन बनाए। उन्हें सेंटनर ने अपना शिकार बनाया। तिलक वर्मा ने 35 गेंदों में 35 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में चौके और छक्के लगाए और आखिरी तक संघर्ष जारी रखा। हालांकि, पारी के दूसरे अंतिम ओवर में मैथ्यू फिशर ने उनका विकेट लेकर भारत की बची हुई उम्मीदों को भी झटका दिया। प्रिंस यादव ने अंतिम ओवरों में कुछ तेज रन बनाए और 18 रन बनाकर नाबाद रहे। न्यूजीलैंड की ओर से जैकब डफी ने चार ओवर में 23 रन देकर चार विकेट हासिल किए। मिचेल सैंटनर और मैथ्यू फिशर ने दो-दो, जबकि एडम मिल्ने को एक सफलता मिली। वहीं, भारत की ओर से मयंक यादव ने तीन विकेट लिए, जबकि अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, नितीश कुमार रेड्डी और अक्षर पटेल को एक-एक सफलता मिली।



फिलिप्स ने 49 गेंदों में बनाए 107 रन

ग्लेन फिलिप्स के शानदार शतक और माइकल ब्रेसवेल की तूफानी अर्धशतकीय पारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने शुक्रवार को चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भारत के खिलाफ सात विकेट पर 259 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। फिलिप्स ने 49 गेंदों में 107 रन बनाए, जबकि ब्रेसवेल ने महज 25 गेंदों में 65 रन की विस्फोटक पारी खेली। दोनों ने चौथे विकेट के लिए सिर्फ 40 गेंदों में 115 रन की साझेदारी की। भारतीय गेंदबाजों के लिए वर्ष 2026 काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। इस साल टी-20 क्रिकेट में भारतीय गेंदबाज 11 बार 200 से अधिक रन लुटा चुके हैं। किसी एक कैलेंडर वर्ष में किसी टीम के गेंदबाजों का यह सबसे खराब प्रदर्शन है। इससे पहले 2026 में ही पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज नौ-नौ बार 200 से अधिक रन दे चुके थे। पहले तीन टी-20 मुकाबलों में 198, 180 और 225 रन के लक्ष्य हासिल कर चुकी भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को लगातार दबाव में रखा था। लेकिन चौथे मुकाबले में मेजबान टीम ने जोरदार वापसी करते हुए श्रृंखला का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया।

राशिद टी20 में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने

एजेंसी, दुबई। अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान मेंस टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए। उन्होंने 120 मैचों में यह माइल स्टोन हासिल किया। शारजाह में वीरवार को राशिद खान ने दूसरे टी-20 मैच में जिम्बाब्वे के विकेटकीपर तादिवनाशे मरुमानी को आउट किया। मरुमानी राशिद का 200वां विकेट बने। इस मैच को अफगानिस्तान ने 19 रन से जीता। उसने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। तीसरा मुकाबला एक नवंबर को खेला जाएगा।



मैच में ये रिकॉर्ड भी बने

अफगानिस्तान शुरुआती 4 विकेट 20 से कम रन पर गंवाने के बाद टी-20 इंटरनेशनल मैच 200 से ज्यादा रन बनाने वाली पहली टीम बनी। 40 साल 188 दिन की उम्र में 320वां शतक लगाया। वे मेंस टी20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने। अजमतुल्लाह उमरजई और इजाज अहमद अहमदजई ने 142 रन की साझेदारी की। यह टी20 में छठे या उससे निचले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है।

स्पोर्ट्स विंडो

अन्वय, आर्यवीर अंडर-19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम में शामिल

एजेंसी, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज खिलाड़ियों राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग के बेटे अन्वय द्रविड़ और आर्यवीर सहवाग को अंडर-19 एशिया कप के लिए शुक्रवार को घोषित भारतीय टीम में शामिल किया गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) पुरुष अंडर-19 एशिया कप का आयोजन वनडे प्रारूप में पांच से 14 नवंबर तक ओमान की राजधानी मस्कट में किया जाएगा। कर्नाटक के अन्वय और दिल्ली के आर्यवीर ने हाल ही में संपन्न वीनू मांकड़ ट्रॉफी में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से प्रभावित करते हुए चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा था। सत्रह साल के अन्वय ने इस महीने की शुरुआत में अंडर-19 प्रतियोगिता में गुजरात के खिलाफ महज 100 गेंदों पर 151 रन की विस्फोटक पारी खेली थी। उनकी इस पारी की बदौलत कर्नाटक ने 300 से अधिक रन के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया था। उन्होंने इससे पहले जुलाई में हंबनटोटा में श्रीलंका के खिलाफ युवा एकदिवसीय मुकाबले में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। उन्होंने उस मैच में 67 गेंदों पर 87 रन बनाए थे।

रयबाकिना ने चोट के कारण पैन पैसिफिक ओपन से नाम वापस लिया

एजेंसी, टोक्यो। विश्व की नंबर एक महिला टेनिस खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल करने के एक दिन बाद ही एलेना रयबाकिना ने गर्दन की चोट के कारण पैन पैसिफिक ओपन से नाम वापस ले लिया। कजाखस्तान की 27 वर्षीय खिलाड़ी को शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में कनाडा की लेयला फर्नांडीज से भिड़ना था, लेकिन चोट के कारण वह मुकाबले में नहीं उतरीं। रयबाकिना ने दर्शकों को संबोधित करते हुए बताया कि वह पिछले कुछ दिनों से गर्दन की चोट से परेशान हैं। उन्होंने दर्शकों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और उन्हें ऑटोग्राफ भी दिए। रयबाकिना ने कहा, 'मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ नहीं खेल पाऊंगी, खासकर जब अगले महीने एक बहुत महत्वपूर्ण टूर्नामेंट होने वाला है।' उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले महीने होने वाले डब्ल्यूटीए फाइनल्स तक वह पूरी तरह फिट हो जाएंगी। रयबाकिना ने टोक्यो में अपने शुरुआती मुकाबले में यूलिया पुतिनत्सेवा को 6-2, 6-3 से हराकर साल के अंत में विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान सुनिश्चित किया था। पिछले महीने उन्होंने पहली बार अमेरिकी ओपन का खिताब जीता था और इसके बाद रैंकिंग में आर्यना सबालेंका को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया। रयबाकिना के लिए यह साल शानदार रहा है। उन्होंने जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता और पिछले सप्ताह निंगबो ओपन सहित कुल चार खिताब अपने नाम किए।

वियना ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे अलेक्जेंडर ज्वेरेव

एजेंसी, वियना। जर्मनी के स्टार टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने वियना ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के साथ ही पहली बार विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करना सुनिश्चित कर लिया है। वीरवार को खेले गए प्री-क्वार्टर फाइनल में ज्वेरेव ने नीदरलैंड के टालोन ग्रिक्सपुर को 6-4, 7-5 से हराया। सोमवार को जारी होने वाली नई रैंकिंग में वह इटली के यानिक सिनर को पीछे छोड़कर दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी बन जाएंगे। 29 वर्षीय ज्वेरेव फ्रेंच ओपन और अमेरिकी ओपन के खिताब जीतने के बाद शानदार लय में हैं। वह 1991 में बोरिस बेकर के बाद विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले जर्मनी के दूसरे पुरुष टेनिस खिलाड़ी होंगे। वर्ष 1973 में विश्व रैंकिंग शुरू होने के बाद शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाले वह 30वें पुरुष खिलाड़ी बनेंगे। ग्रिक्सपुर के खिलाफ ज्वेरेव ने दमदार खेल दिखाया। उन्होंने लगातार दो सेट जीतकर मुकाबला अपने नाम किया। मैच का अंत उन्होंने ऐस लगाकर किया। इस उपलब्धि के बाद कोर्ट पर विशेष समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उनकी टीम के साथ ऑस्ट्रिया के पूर्व विश्व नंबर एक खिलाड़ी थॉमस मस्टर भी मौजूद रहे। ज्वेरेव ने कहा कि दुनिया के शीर्ष पर पहुंचने का एहसास बेहद खास है। नई रैंकिंग जारी होने पर अपने नाम के आगे नंबर एक देखना उनके लिए अविस्मरणीय अनुभव होगा।

रोबिन उथप्पा और धवल कुलकर्णी की आईपीएल 2027 में वापसी

एजेंसी, नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग यानि आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक और पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने बड़ा ऐलान किया है। आईपीएल 2027 से पहले शुक्रवार को अपने कोचिंग स्टाफ में व्यापक फेरबदल करते हुए टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी रोबिन उथप्पा को अपना बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। बता दें कि उथप्पा के अलावा न्यूजीलैंड के मिशेल मैक्लेनाघन को बॉलिंग कोच, जबकि पूर्व भारतीय कोच टी. दिलीप को फील्डिंग कोच और धवल कुलकर्णी को डेवलपमेंट बॉलिंग कोच नियुक्त किया है। ये सभी हेड कोच कीरोन पोलार्ड के साथ मिलकर एक नए कोचिंग ग्रुप का हिस्सा बनेंगे। इस तरह से उथप्पा, मैक्लेनाघन और कुलकर्णी की मुंबई इंडियंस की टीम में वापसी हो रही है, जो पहले खिलाड़ी के तौर पर इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा रह चुके हैं। यह तीनों नवनियुक्त मुख्य कोच कीरोन पोलार्ड के साथ मिलकर नए कोचिंग स्टाफ का हिस्सा बनेंगे। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल में अपना आखिरी खिताब 2020 में जीता था। पिछले सत्र में उसकी टीम नौवें स्थान पर रही थी।

हांगकांग सिक्सेस में पाकिस्तान ने भारत को चार विकेट से हराया

अब्बास अफरीदी ने 8 गेंदों पर 35 रन बनाए

एजेंसी, हांगकांग

हांगकांग इंटरनेशनल सिक्सेस में पाकिस्तान ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। शुक्रवार को खेले गए ग्रुप-सी के मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर में 5 विकेट पर 88 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान ने 3.5 ओवर में 2 विकेट पर 91 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। पाकिस्तान ने 13 गेंद बाकी रहते 89 रन का टारगेट हासिल किया। पाकिस्तान की जीत में अब्बास अफरीदी और ख्वाजा नफे ने अहम भूमिका निभाई। अब्बास ने 8 गेंदों पर 35 रन बनाए। उन्हें को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। राहुल त्रिपाठी 5 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद नीतीश राणा ने 14 गेंदों पर 19 रन बनाए।



पाकिस्तान ने 3.5 ओवर में खत्म किया मैच

89 रन के टारगेट का पीछा करने उतरे पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही तेज बल्लेबाजी की। ख्वाजा नफे और अब्बास अफरीदी ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया। दोनों ने पहले विकेट के लिए 2.1 ओवर में 59 रन जोड़े। अब्बास 8 गेंदों पर 35 रन बनाकर शशांक सिंह की गेंद पर आउट हुए।

कृष्णा न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर

एजेंसी, नई दिल्ली। प्रसिद्ध कृष्णा न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने शुक्रवार को बताया कि प्रसिद्ध को फिट होने की शर्त पर ही टीम में शामिल किया गया था। लेकिन, उन्हें पूरी तरह ठीक होने में थोड़ा समय और लगेगा। प्रसिद्ध जांघ की चोट (हैमस्ट्रिंग) से उबर रहे हैं। वे 30 सितंबर को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में चोटिल हुए थे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज 4 नवंबर से खेली जाएगी। फिलहाल, टीम इंडिया 5 मैचों की टी-20 सीरीज में 3-0 से आगे चल रही है। आज चौथा टी-20 मैच खेला जाएगा। प्रसिद्ध फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ तीसरे अनऑफिशियल टेस्ट के लिए इंडिया-ए से जुड़ेंगे। इससे उन्हें टेस्ट सीरीज से पहले मैच प्रैक्टिस करने में मदद मिलेगी।

हायलो ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचीं सिंधु और अनमोल खरब

एजेंसी, सारब्रुकेन

भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने हायलो ओपन 2026 के महिला एकल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वीरवार को खेले गए प्री-क्वार्टर फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने फ्रांस की रोसी ओक्टाविया पंकासारी को सीधे गेमों में 21-9, 21-6 से हराया। यह मुकाबला 30 मिनट से भी कम समय में समाप्त हो गया।

क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना डेनमार्क की अमाली शुल्ज से होगा। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु इस सुपर 500 प्रतियोगिता में फ्रेंच ओपन सुपर 750 में उपविजेता रहने के बाद उतरी हैं। फ्रेंच ओपन के फाइनल में उन्हें विश्व की नंबर एक खिलाड़ी दक्षिण कोरिया की आन से यंग से हार का सामना करना पड़ा था।





इस बीच युवा भारतीय खिलाड़ी अनमोल खरब ने भी शानदार वापसी करते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। 19 वर्षीय अनमोल ने प्री-क्वार्टर फाइनल में उच्च वरीयता प्राप्त डेनमार्क की लाइन क्रिस्टोफरसन को एक घंटे तीन मिनट तक चले मुकाबले में 11-21, 21-18, 25-23 से हराया। पहला गेम गंवाने के बाद अनमोल ने दूसरे गेम में वापसी की और मुकाबले को निर्णायक गेम तक पहुंचाया। तीसरे गेम में उन्होंने धैर्य बनाए रखते हुए 25-23 से जीत दर्ज की। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए अब उनका सामना भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा।

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस के नए सीईओ बने विवेक कन्नन

एजेंसी, नई दिल्ली। हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस ने विवेक कन्नन को अपना नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है। वह सचिन पिल्लई का स्थान लेंगे, जिन्होंने 29 अक्टूबर, 2026 को कंपनी के प्रबंध निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, पिल्लई कंपनी के निदेशक मंडल में गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। विवेक कन्नन वर्ष 2020 में मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) के रूप में हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस से जुड़े थे। वित्तीय सेवा क्षेत्र में उन्हें दो दशक से अधिक का अनुभव है। अपनी नई जिम्मेदारी में वह कंपनी की बाजार में मौजूदगी बढ़ाने, कारोबारी क्षमताओं को मजबूत करने और सतत विकास को गति देने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कन्नन की नियुक्ति पर कंपनी के चेयरमैन धीरज जी हिंदुजा ने कहा कि उनके नेतृत्व में कंपनी अपनी क्षमताओं को लगातार मजबूत करेगी। साथ ही ग्राहकों और अन्य हितधारकों को दीर्घकालिक मूल्य उपलब्ध कराने की दिशा में काम करेगी। कंपनी को उम्मीद है कि कन्नन का अनुभव और परिचालन संबंधी समझ भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने में सहायक होगी। नेतृत्व में इस बदलाव के साथ हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस का लक्ष्य आवास वित्त बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करना और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है।



टाटा-अदाणी की साझेदारी से एयरपोर्ट्स पर खुलेंगे आठ नए होटल

एजेंसी, नई दिल्ली

देश के दो प्रमुख औद्योगिक समूह टाटा और अदाणी ने आतिथ्य क्षेत्र में बड़ी साझेदारी की है। टाटा समूह की होटल कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (आईएचसीएल) और अदाणी समूह की एयरपोर्ट संचालक इकाई अदाणी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड ने देश के प्रमुख विमानन केंद्रों पर आठ नए होटल विकसित करने के लिए समझौता किया है। इस योजना के तहत मुंबई, नवी मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी सहित प्रमुख शहरों में 2000 से अधिक कमरों की क्षमता वाले होटल बनाए जाएंगे। इनका संचालन ताज, विवांता, गेटवे और जिंजर जैसे ब्रांड के तहत होगा।



इस साझेदारी की घोषणा अदाणी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स के निदेशक जीत अदाणी और आईएचसीएल के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुनीत चटवाल ने की। परियोजना के पहले चरण में छह शहरों में लगभग 2.2 करोड़ वर्ग फुट क्षेत्र का विकास किया जाएगा। इसके लिए 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश प्रस्तावित है। अदाणी समूह ने हवाई अड्डों के आसपास विकास कार्यों के लिए अदाणी एयरपोर्ट सिटी लिमिटेड की स्थापना की है।

भारत-मेक्सिको व्यापार वार्ता शुरू

कृषि, दवा, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बढ़ेगा कारोबारी सहयोग

एजेंसी, नई दिल्ली

भारत और मेक्सिको ने आपसी व्यापार एवं आर्थिक संबंधों को नई मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दोनों देशों ने तरजीही व्यापार समझौते (पीटीए) पर बातचीत शुरू करने के लिए संदर्भ शर्तों (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना, निवेश के नए अवसर पैदा करना और दोनों देशों के कारोबारियों के लिए बाजार तक पहुंच आसान बनाना है। प्रस्तावित समझौते से कृषि एवं खाद्य उत्पाद, ऑटोमोबाइल, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा और चिकित्सा उपकरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में व्यापार की संभावनाएं बढ़ेंगी।

पीआईबी के अनुसार, समझौते को लेकर होने वाली बातचीत में वस्तुओं के बाजार तक पहुंच, उत्पादों के मूल स्थान से जुड़े नियम, सीमा शुल्क प्रक्रिया और व्यापार को आसान बनाने जैसे विषय शामिल होंगे। इसके अलावा व्यापार विवादों का समाधान, खाद्य एवं कृषि उत्पादों के स्वास्थ्य और स्वच्छता मानक, तकनीकी बाधाएं तथा व्यापार सुरक्षा उपायों पर भी चर्चा की जाएगी। इससे दोनों देशों की कंपनियों को एक-दूसरे के बाजार में कारोबार बढ़ाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, आयात शुल्क में कितनी कटौती होगी और किन उत्पादों को इसका लाभ मिलेगा, यह बातचीत के अंतिम परिणामों पर निर्भर करेगा।



भारत-बेल्जियम-लक्जमबर्ग के बीच एयरोस्पेस सहयोग को मिलेगी नई दिशा

एजेंसी, मुंबई

भारत, बेल्जियम और लक्जमबर्ग ने एयरोस्पेस, अनुसंधान, नवाचार और उच्च शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। तीनों देशों ने व्यापार और निवेश संबंधों की समीक्षा करते हुए आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के नए अवसर तलाशे। इस संबंध में भारत-बेल्जियम-लक्जमबर्ग आर्थिक संघ (बीएलईयू) के संयुक्त आर्थिक आयोग का 19वां सत्र 29 अक्टूबर को लक्जमबर्ग में आयोजित किया गया।

बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल, बेल्जियम के फिलिप वांडेन बुल्के और लक्जमबर्ग के हेनरी शूमाकर ने की। सत्र में व्यापार एवं निवेश के मौजूदा संबंधों की समीक्षा के साथ व्यापारिक गतिविधियों को सुगम बनाने और निवेश प्रवाह बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। तीनों पक्षों ने विमानन एवं अंतरिक्ष क्षेत्र, अनुसंधान, नवाचार, उच्च शिक्षा और कौशल विकास में सहयोग की संभावनाएं तलाशने पर भी सहमति जताई।

निवेश के अवसर बढ़े

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बैठक के बाद लक्जमबर्ग की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी व्यावसायिक चर्चा की। उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक विकास दर और निवेश की संभावनाओं का उल्लेख करते हुए कंपनियों को भारतीय बाजार में दीर्घकालिक निवेश के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि वित्तीय सेवाओं, उन्नत विनिर्माण, रसद, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और अनुसंधान के क्षेत्रों में साझेदारी की व्यापक संभावनाएं हैं।



वापसी मजबूत परिचालन प्रदर्शन से इंडिगो की आय 23,364 करोड़ रुपए पहुंची

इंडिगो की कमाई में 25.9 प्रतिशत की बढ़त

एजेंसी, मुंबई

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के वित्तीय परिणाम घोषित कर दिए हैं। कंपनी को इस दौरान पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले घाटे में राहत मिली है। सितंबर में समाप्त हुई तिमाही में कंपनी का समेकित शुद्ध घाटा घटकर 1,879 करोड़ रुपये रह गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में यह 2,582 करोड़ रुपये था। इस तरह कंपनी के घाटे में 703 करोड़ रुपये की कमी दर्ज की गई है। वहीं, हवाई यात्रा की मजबूत मांग का सकारात्मक असर कंपनी की कमाई पर दिखाई दिया। परिचालन से कुल आय सालाना आधार पर 25.9 प्रतिशत बढ़कर 23,364 करोड़ रुपये पहुंच गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 18,555 करोड़ रुपये थी।

परिचालन के मोर्चे पर भी कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इंडिगो का ईबीआईटीडीए (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई) पिछले साल के 579 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,908 करोड़ रुपये हो गया।



◆ ईबीआईटीडीए में 229 प्रतिशत की बढ़ोतरी

मानसून में सुस्त पड़ता है विमानन कारोबार

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विली वॉल्श ने वित्तीय नतीजों पर कहा कि सितंबर में समाप्त होने वाली तिमाही आमतौर पर विमानन कारोबार के लिए सुस्ती वाली होती है। इस दौरान मानसून के कारण हवाई यात्रा की मांग पर असर पड़ता है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर जारी भू-राजनीतिक तनाव और परिचालन संबंधी व्यवधानों ने भी कंपनी के कारोबार को प्रभावित किया।

चुनौतियों के बीच विस्तार की राह पर इंडिगो

वॉल्श ने भारतीय विमानन क्षेत्र के भविष्य को लेकर सकारात्मक रुख जताते हुए कहा कि देश में हवाई यात्रा की दीर्घकालिक संभावनाएं बेहद आकर्षक हैं। बढ़ती यात्रियों की संख्या में वृद्धि से विमानन क्षेत्र को आगे भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।